



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2011/फाल्गुन 3, 1932

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2011/PHALGUNA 3, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 फरवरी, 2011

सं. टीएएमपी/26/2010-बीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कार्गो प्रहस्तन संभाग के श्रमिकों को तैनात करने के लिए लेवी के निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन न्यास के टॉरिफ प्राधिकार

मामला सं. टीएएमपी/26/2010-बीपीटी

विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट

...आवेदक

आदेश

(जनवरी, 2011 के 18वें दिन में पारित किया गया)

यह मामला कार्गो संभलाई प्रभाग (सीएचडी) कर्मकारों के डिप्लाइमेंट के लिए समय दर मजदूरी के प्रतिशत के रूप में लेवी की जाने वाली लेवी निर्धारण के संबंध में विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट (वि पो ट्र) से 4 मई, 2010 में प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. दिनांक 4 मई 2010 में वि पो ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पोत परिवहन, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी की गई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड (वीडीएलबी) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ 26 सितंबर 2008 से विलीन हुआ। इस संबंध में, सितंबर 2008 को औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 12 (3) के अंतर्गत विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड के प्रबंधन, उसके कर्मकारों की यूनियन और वीपीटी के बीच एक समझौता हुआ।

2.2 दिनांक 4 मई 2010 को वि पो ट्र द्वारा दिए गए प्रमुख मद निम्नांकित है :

- (i) वीपीटी में वीडीएलबी विलीन होने के पूर्व, डॉक कर्मकार रोजगार विनियम जिसके अंतर्गत जो पंजीकृत योजना और अपंजीकृत योजनाओं को अनुमोदित किया है के अनुसार कर्मकारों को उपलब्ध किये गये कार्य अवसरों पर भुगतान की गई समय दर मजदूरी के प्रतिशत पर लेवी वसूल करने की पद्धति चालू थी। वीडीएलबी ने निर्णय लिया कि समय समय पर लेवी का प्रतिशत वसूल किया जाए। तदनुसार, स्टीवडोर्स दावों को बढ़ाते हुए आवधिक रूप से लेवी वसूल किया।
- (ii) कर्मकार वर्ग के चालू अधिकतम समय दर मजदूरी का 189% की दर से समेकित लेवी वसूल किया गया। लेवी की वसूली के अलावा, वास्तविक कार्य चान्सेस के लिए कर्मकारों को किया गया समय दर मजदूरी और पीस रेट का भुगतान स्टीवडोर्स से वसूल किया जाता है जो कार्गो संभलाई प्रभाग के कर्मकारों को नियुक्त करते हैं।
- (iii) मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2009 में निदेश दिया कि फिलहाल पूर्ण डिप्लॉयड के मजदूरी लागत को गिनते हुए लेबर के मजदूरी प्रतिशत के बजाय स्टीवडोरिंग लेवी ट्रैक्जे के आधार पर केलिक्यूलेट किया जिसे बाद में अभिलेखित जा सके। इस निदेशों पर, ट्रेड के साथ बैठक हुई और ट्रेड ने लेवी वसूली में समय दर मजदूरी और पीस रेट के लिए वर्तमान पद्धति को कुछ ज्यादा अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया।
- (iv) विलीन के दिन पर, वीडीएलबी की कुल संख्या 1228 था जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / सेवनिवृत्ति और मृत्यु के कारण कम होकर 1165 रही। पिछले तीन वर्षों 2010-11 और 2011-12 से 2013-14 वर्षों में सीएचडी प्रभाग के स्टाफ की संख्या क्रमशः 1165, 1015, 981 और 974 दिखाई गई।
- (v) लेवी वसूली करने का विचार संगठन के प्रशासनिक व्यय को लाभ-हानि से परे पूरा करना था। फिर भी, प्रशासनिक और कल्याण व्यय के लिए वूसल किया गया लेवी का प्रतिशत अपर्याप्त है और इस प्रक्रिया में वीडीएलबी और वर्तमान कार्गो संभलाई प्रभाग को हानि हुई है और 31 मार्च 2009 को सूचित वित्तीय घाटा 21.78 करोड़ हुआ। अस्थायी ऑफिसों के अधार पर वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 24.40 करोड़ की प्रत्याशित हानि हुई।
- (vi) वि पो ट्र और ट्रेड के प्रतिनिधियों के बीच संपन्न हुई 18 मार्च 2010 की बैठक में ट्रेड के सीएचडी से संबंधित वित्तीय हानि की सूचना दी गई। बैठक में ट्रेड के प्रतिनिधियों ने 1 अप्रैल 2010 से 3 महीनों की अवधि तक वर्तमान लेवी को 189% से 250% तक बढ़ाने और 1 जुलाई 2010 से दर मजदूरी पर 350% की वृद्धि के लिए सहमत हो गये। टॉप्स के पास अनुमोदन के लिए लंबित लेवी को बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गये।
- (vii) 30 मार्च 2010 को संपन्न हुई मंडल बैठक में वि पो ट्र के प्रस्ताव को वी पी टी मंडल ने मंजूरी दी।
- (viii) जलयान संभलाई के लिए रटीवडोर को प्राक्कलित रकम का 100% अग्रिम के रूप में चुकाना पड़ता है जो जलयान पूरा होने के बाद अंतिम बिल में समायोजित किया जाता है। स्टीवडोर को निर्धारित अवधि में बकायां को पूरा करने में असफल होने पर, भारतीय स्टेट बैंक पीएलआर के अनुसार केलिक्यूलेटेड ब्याज पर और दो प्रतिशत चुकाना होगा।
- (ix) वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वि पो ट्र ने कार्गो संभलाई प्रभाग के 25 सितंबर 2008 और 31 मार्च 2009 के समेकित तुलन पत्र और आय और व्यय प्रस्तुत किये हैं। पोर्ट ने कार्गो संभलाई प्रभाग के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के घास्तविक कास्ट स्टेटमेंट के वर्तमान दर और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के प्राक्कलन का ब्यौरा भी दिया है। वि पो ट्र द्वारा फाईल की गई कास्ट स्टेटमेंट में दिखाई गई कास्ट पोजीशन का सारांश नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक		वर्तमान टॉरिफ पर ग्राहकलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(i)	कुल आय	4424.26	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22
(ii)	व्यय (आरओसी ई को मिलाकर)	5172.36	559406	595171	6095.31	6814.93	7018.44
(iii)	पूँजी नियोजित	--	209.03	185.99	163.86	141.74	119.61
(iv)	आरओसीई :						
	व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	10.31	9.04	7.91	6.78	5.65
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	9.18	8.2	7.27	6.31	5.35
(v)	कुल व्यय +आरओसीई (ii+iv)	5172.36	5613.55	5968.97	6110.48	6828.02	7029.44
(vi)	आय के ऊपर अधिक व्यय (i-v)	(748.10)	(2440.45)	(1439.59)	(1618.27)	(2199.03)	(2251.22)

2.3 इस पृष्ठभूमि में, और जैसा कि लेवी वसूली के लिए ट्रेड द्वारा तदर्थ दर को ट्रेड ने आपसी सहमति दी वि पो ट्र ने निम्न दरों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया :

- (i) कर्मकारों के दैनिक मजदूरी दर @ 250% से तीन महीनों की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2010 तक और 350% की दर पर 1 जुलाई 2010 से आगे लेवी वसूल किया जाए ताकि प्रबंधन और अन्य कल्याण कार्यों के व्यय को पूरा किया जा सके।
- (ii) वास्तविक पर समय दर मजदूरी और पीस रेट भुगतान वसूल करना और साथ में वर्तमान पद्धति के अनुसार थर्मल कोयला पर पी आर लेवी को भी वूसूल करना।
- (iii) बिना आपत्ति के सभी प्रचालनों पर समय समय पर निर्धारित किये अनुसार लेवी प्रतिशत वसूल करना।

2.4 तदनुसार, वि पो ट्र ने - पोर्ट की दर-मान में निम्नांकित को शामिल करने का प्रस्ताव रखा :

- (i) वि पो ट्र के प्रस्तावित दर-मान की धारा - 1 में कार्गो संभलाई प्रभाग की परिभाषा, डॉक कार्य, डॉक कर्मकार, लेवी दर, समय दर मजदूरी और पीस रेट को शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया।
- (ii) धारा 4 के अंतर्गत निम्नांकित को शामिल करना - कार्गो संबंधित प्रभार की अनुसूची
4.7.4: -

कार्गो संभलाई सेवाओं पर लेवी :

क्र सं.	विवरण	लेवी
(i)	ट्रेड से कर्मकारों को उपलब्ध कराये गये कार्य चान्सेस पर दी गई दैनिक मजदूरी दर पर लेवी वसूल करना।	1 अप्रैल 2010 से दैनिक मजूदरी दर तीन महीनों की अवधि के लिए 250% और 1 जुलाई 2010 से 350%।
(ii)	समय दर मजदूरी और पीस रेट भुगतान की वसूली (वर्तमान पद्धति के अनुसार थर्मल कोल पर भी पी आर लेवी वसूल की जायेगी।)	वर्तमान के अनुसार

3. प्रस्तावित लेवी प्रतिशत कार्य को प्रस्तुत करने के हमारे सुझाव पर वि पो ट्र ने दिनांक 2 जून 2010 के पत्र में निम्नांकित को प्रस्तुत किया :

- (i) 2008-09 में कार्गो संभलाई प्रभाग की लेवी से आय रु.44.24 करोड़ थी और वर्ष 2009-2010 में यह रु. 31.73 करोड़ प्रत्याशित थी। वर्ष 2008-09 में इसका व्यय रु. 51.72 करोड़ है जिसमें रु. 7.48 करोड़ का घाटा है। वर्ष 2009-10 में आपरेटिंग व्यय रु. 55.94 करोड़ प्रत्याशित था और पूँजी नियोजन पर प्रतिलाभ रु. 0.19 करोड़ को ध्यान में रखते हुए कुल व्यय का प्राक्कल रु. 56.13 करोड़ था जिसमें रु. 24.40 करोड़ का घाटा है।
- (ii) 31.03.2009 से, कार्गो संभलाई प्रभाग का संचित घाटा रु. 21.78 करोड़ और पेशन निधि में रु. 27.09 करोड़ की कमी है। विलयन पूर्व स्कीम के अनुसार, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति कमी सहित पूरा व्यय स्टीवडोर के खाते में है। तदनुसार, पेशन निधि में कमी और 31.03.2009 को संचित घाटा, 5 वर्ष की अवधि के लिए अस्थगित व्यय समझा गया।
- (iii) उपर्युक्त अस्थगित व्यय रु. 9.77 करोड़ वार्षिक पर विचार करने पर कुल व्यय रु. 65.90 करोड़ वार्षिक हो गया जब कि प्रत्याशित आय का प्राक्कलन रु. 31.73 करोड़ है। ऊपर बताये गये आय और व्यय पर विचार करते हुए वर्तमान लेवी को 1.4.2010 से 189% से 350% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।
- (iv) ग्रूप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हुई। चूँकि दैनिक मजदूरी पर प्रतिशत लेवी है अतः इस कारण अतिरिक्त अंशदान हुआ। 161% वृद्धिगत लेवी को ध्यान में रखते हुए लेवी में रु. 12.89 करोड़ की अतिरिक्त वसूली होगी।
- (v) बढ़ायी गयी लेवी के उक्त प्रस्ताव को स्टीवडोर्स के सामने रखा गया विस्तृत चर्चा के बाद स्टीवडोर्स ने दिनांक 1.4.2010 से लेवी को 250% तक बढ़ाने और एक वर्ष तक बाद करने के लिए सम्मति दी। विस्तृत चर्चा के बाद वे दिनांक 1.4.2010 से लेवी 250% और 1.7.2010 से 350% तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गये।
- (vi) स्टीवडोर्स ने आगे कहा कि वर्तमान करार एवं उनके अधिकतर नियम जून 2010 को समाप्त हो जाएंगे और नए करार जुलाई 2010 से प्रारंभ किये जायेंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने 1.4.2010 से ग्रारंभ हुए तीन महीनों की अवधि के लिए वर्तमान करार दर से 250% लेवी पर विचार करने के लिए अनुरोध किया उसके बाद नए करार में जाने के लिए, 350% प्रस्तावित लेवी को प्रिंसिपल्स के सूचना में रखने और तदनुसार नए करारों को अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया।
- (vii) उक्त औचित्य को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि दिनांक 1.4.2010 से 350% लेवी प्रस्तावित की गई परन्तु 1.4.2010 से तीन महीनों की अवधि के लिए 250% और 1.7.2010 के आगे से 350% लेवी पर विचार किया गया।
- 4.1 तमिल नाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) ने उनके दिनांक 17 अप्रैल 2010 के पत्र में सूचित किया कि वि पो ट्र ने दिनांक 30 मार्च 2010 के पत्र में सूचित किया कि लेवरों को नियुक्त करने के लिए लेवी 1 अप्रैल 2010 से वर्तमान लेवी 184% से 250% और 1 जुलाई 2010 से 350% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसलिए, दिनांक 27 अप्रैल 2010 के हमारे पत्र में वि पो ट्र से अनुरोध किया गया कि टीएनईबी द्वारा दिये गये पाइंटों पर विवरण दें और साथ में इस की अनुज्ञाप्ति दें कि किस आधार पर वृद्धिगत लेवी पोर्ट द्वारा वसूल की जा रही है।।।
- 4.2 वी पी टी ने अपेन प्रस्ताव को दोहराते हुए दिनांक 27 मई 2010 के पत्र में टीएनईबी के पाइंटों पर उत्तर दिया। वी पी टी द्वारा दिये गये मुख्य पाइंटों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :

- (i) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए कार्गो संभलाई प्रभाग के सामने रु. 23.00 करोड़ की वित्तीय कमी थी, प्रबंधन ने ट्रेड सदस्यों की उपस्थिति में वर्तमान लेवी तीन महीने की अवधि अर्थात् 1.4.10 से 30.6.2010 तक 189% से बढ़ाकर 250% और उसके बाद 350% लेवी बढ़ाने के लिए सम्मति से निर्णय लिया।

- (ii) बताया गया कि जब ट्रेड के साथ लेवी का प्रतिशत बढ़ाने पर सम्मति हुई उस समय इस बैठक में मेसर्स टीएनईबी का हैंडलिंग ऐजन्ट था । इस संदर्भ में पोर्ट ने दिनांक 18.3.2010 को ट्रेड के साथ संपन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त की प्रति भी दी ।
- 4.3 वि पो ट्र द्वारा दिये गये पाइंटों के संदर्भ में, हमारे पत्र दिनांक 9 अगस्त 2010 में वि पो ट्र को बताया गया कि वि पो ट्र के दर मान में कार्गो संभलाई प्रभाग से कर्मकारों के डिप्लायमेंट के लिए लेवी को इस प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं दी गई । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 के अनुसार सूचीगत सेवाओं के लिए, प्राधिकार की अनुमति के बिना टैरिफ वसूली करने के लिए महा पत्तन न्यास को अधिकार नहीं है । प्रस्तावित दर को वसूल न करने का वि पो ट्र का निर्णय यदि कोई है तो, पोर्ट को उसके दायित्व और परिणाम भुगतने होंगे ॥
5. निर्धारित पद्धति के परामर्श के अनुसार, दिनांक 4 मई 2010 को वि पो ट्र से प्राप्त प्रस्ताव संबंधित उपभोक्ताओं को / संगठन निकायों को उनके विचार जानने लिए परिचालित किया गया । उपभोक्ता / संगठन निकायों से प्राप्त टिप्पणी वि पो ट्र को फीडबैक सूचना के रूप में भेजी गई । उपभोक्ता / संगठन निकायों से दिये गये विवरण और टिप्पणी पर वि पो ट्र ने अपने विचार प्रस्तुत किये ।
- 6.1 प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा के आधार पर, वि पो ट्र से हमारे पत्र दिनांक 9 सितंबर 2010 के द्वारा विविध पाइंटों पर सूचना / स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया । वि पो ट्र ने दिनांक 22 अक्टूबर 2010 के पत्र में जवाब दिया । हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न और वि पो ट्र द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण नीचे तालिकाबद्ध रूप में दिये गये हैं :

क्र सं.	हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न	वि पो ट्र द्वारा दिये गये जवाब
(i)	यह बताया गया कि 26 सितंबर 2008 से विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड (विडीएलबी) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में विलीन हो गया और प्रचालन पोस्ट-मर्जर महापत्तन न्यास अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है । लेकिन लेवी निर्धारण प्रस्ताव मई 2010 में फाईल किया गया । प्रस्ताव फाईल करने में 1/2 वर्ष विलंब होने के कारण स्पष्ट करें ।	औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अंतर्गत, वीपीटी में वीडीएलबी के विलयन के समय स्टीवडोर्स से वर्तमान पद्धति के अनुसार किये गये समझौता ज्ञापन में समय दर मजदूरी पर लेवी वसूली करने का प्रस्ताव था । तदनुसार, प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली जारी रहा । उपर्युक्त मामले पर, महापत्तनों के लिए स्टीवडोर्सिंग नीति - लेवी कर्मकारों की मजदूरी के प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर करने के लिए दिनांक 24-6-09 का मंत्रालय का पत्र दिनांक 13.7.2009 को प्राप्त हुआ । मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल की जाए और तदनुसार दिनांक 3.8.2009 को संपन्न मंडल बैठक में कार्यसूची मद रखा गया जिसमें मंत्रालय के निदेशों पर टॉप्स के अनुमोदन की शर्त पर मंडल ने कर्मकारों के मजदूरी के प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमति दी । मंडल के अनुमोदन के बाद, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के कार्य की रूपात्मकता के लिए एक समिति का गठन किया और उसके बाद समिति ने अन्य महा पत्तन न्यासों में, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूली के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी की सूचना प्राप्त की । इस प्रस्ताव के निश्चित होने के बाद, स्टीवडोर्स को 13.2.2010 को और बाद में दिनांक 24.2.2010 और 3.3.2010 को आयोजित बैठकों में आमंत्रित किया गया । 18.3.2010 को आयोजित बैठक में, स्टीवडोर्स ने टन्नेज के आधार के बजाय लेवी प्रतिशत को कुछ समय तक जारी करने का अनुरोध किया । उक्त बैठक में 1.4.2010 से प्रारंभ तीन महीने की अवधि के लिए 250% दर पर बढ़ाया लेवी और 1.7.2010 के बाद से 350% दर पर और

		उसके बाद टर्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए सम्मति दी। सम्मति के अनुसार, दिनांक 31.3.2010 को आयोजित वि पो ट्रॉ के द्वासी संभल बैठक में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए और यह प्रस्ताव टॉम्प को प्रस्तुत करने का संकल्प किया। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्ताव टॉम्प को फाईल करने में 1 1/2 वर्ष का विलंब हुआ।																												
(ii)	(क) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ पूर्व विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड को विलीन करने के उद्घेश्य-नियमित रूप से रोजगार सुनिश्चित करना, उच्च श्रम उत्पादकता, जलयान का शीघ्र आवर्तन और कार्गो संभलाई में दर प्रभाव-समझौता ज्ञापन में विशिष्ट रूप से दिखाये गये थे। कृपया समझौता ज्ञापन में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को स्पष्ट करें।	विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ पूर्व विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड को विलीन करने के समझौता ज्ञापन में दिखाये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्गो संभलाई प्रचालन में दर के प्रभावी होने की दिशा में वि पो ट्रॉ ने मैनिंग स्केल पर नेशनल ट्रिब्युलन अवार्ड को कार्यान्वित किया और तदुनसार कार्गो संभलाई की विविध गतिविधियों में मैनिंग स्केल का संशोधन किया। परिणाम स्वरूप प्रति हुक्म प्रति पारि में मैनपावर कम होगायी और साथ ही 31.3.2010 के वर्तमान टॉरिफ ने अनुसार प्रति टन दर में हुई बदल को दिखाया गया। वि पो ट्रॉ द्वारा दिया गया विवरण निम्न है: कार्गो संभलाई प्रचालन में प्रति टन पर दर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल अधिनियम से पूर्व और उसके बाद																												
	(ख) विलयन पूर्व दो वर्षों अर्थात् 2006-07 एवं 2007-08 एवं विलयन के बाद अगरतः 2010 तक कार्गो संभलाई कर्मकारों के औसतन प्रति हुक्म, प्रति पारी वस्तुवार, जलयान का आवर्तन संबंधी तुलनात्मक स्थिति बतायें।	रु. प्रति टन <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्गो का नाम</th> <th>पहले मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन</th> <th>बाद में मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन</th> <th>यूनियन करार के बाद मैनिंग स्केल का कार्यान्वयन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उर्वक</td> <td>20.00</td> <td>6.00</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>लोहा अवरक</td> <td>44.00</td> <td>59.00</td> <td>233.00</td> </tr> <tr> <td>कोकिंग कोल</td> <td>16.00</td> <td>6.00</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>सामान्य कार्गो</td> <td>54.00</td> <td>134.00</td> <td>121.00</td> </tr> <tr> <td>सभी कोक</td> <td>22.00</td> <td>9.00</td> <td>27.00</td> </tr> <tr> <td>बल्क कार्गो</td> <td>37.00</td> <td>8.00</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table> उक्त के अतिरिक्त उच्च श्रम उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए पोर्ट ने वर्तमान विद्युत वार्फ क्रेनों के स्थान में अधिक क्षमतावाले वार्फ क्रेनों को रखने ओर साथ में वर्तमान ग्रेव क्षमता में अधिक क्षमतावाले ग्रेवों को रखने का प्रस्ताव रखा। इन सभी प्रयासों से लंबी अवधि के आधार पर जलयान का शीघ्र आवर्तन सुनिश्चित होगा अतः यह कहा जा सकता है कि पोर्ट ने समझौता ज्ञापन उद्घेश्यों को पूरा करने का प्रयास किया।	कार्गो का नाम	पहले मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन	बाद में मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन	यूनियन करार के बाद मैनिंग स्केल का कार्यान्वयन	उर्वक	20.00	6.00	21.00	लोहा अवरक	44.00	59.00	233.00	कोकिंग कोल	16.00	6.00	16.00	सामान्य कार्गो	54.00	134.00	121.00	सभी कोक	22.00	9.00	27.00	बल्क कार्गो	37.00	8.00	24.00
कार्गो का नाम	पहले मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन	बाद में मैनिंग स्केल पर कार्यान्वयन	यूनियन करार के बाद मैनिंग स्केल का कार्यान्वयन																											
उर्वक	20.00	6.00	21.00																											
लोहा अवरक	44.00	59.00	233.00																											
कोकिंग कोल	16.00	6.00	16.00																											
सामान्य कार्गो	54.00	134.00	121.00																											
सभी कोक	22.00	9.00	27.00																											
बल्क कार्गो	37.00	8.00	24.00																											
	(ख) विलयन पूर्व दो वर्षों अर्थात् 2006-07 एवं 2007-08 एवं विलयन के बाद अगरतः 2010 तक कार्गो संभलाई कर्मकारों के लिए औसतन प्रति हुक्म, प्रति पारी वस्तुवार, जलयान का आवर्तन, दो वर्ष 2006-07, 2007-08 विलयन के पहले और पोर्ट विलयन 31.8. 2010 की अवधि तक उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति का विवरण दिया गया।																													

(iii)	<p>(वि पो द्र द्वारा अग्रेषित) नई स्टीवडोरिंग नीति का प्रतिपादित करने संबंधी दिनांक 24 जून 2009 के भारत सरकार के पत्र सं. एलबी-130184/05-एल-ii देखें, जिसमें सभी पत्तन न्यासों को निदेश किया कि कर्मकार के मजदूरी प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर स्टीवडोरिंग लेवी का परिकलन करें। इस संदर्भ में वि पो द्र ने सरकार के निदेशों को अनुपालन ना करने के मान्य कारण नहीं देने को छोड़कर स्टीवडोरिंग अनुरोध पर वर्तमान मजदूरी दर के प्रतिशत पद्धति पर लेवी वसूल जारी रखने के लिए कहा। वि पो द्र से अनुरोध है कि सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण स्पष्ट करें। यदि, प्रति टन की लेवी पर स्टीवडोरिंग की गतिविधि पर वि पो द्र ने सरकार से पूछताछ किया और सरकार से कोई छूट प्राप्त किया हो तो, संबंधित कागजात प्रस्तुत करें।</p>	<p>उपर्युक्त स्पष्टीकरण क्र सं.(i) में, फरवरी 2010 में आयोजित बैठक में स्टीवडोर ने वर्तमान प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली कुछ समय तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया और तदनुसार वि पो द्र ने मंडल बैठक में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल जारी करने के लिए संकल्प किया। बैठक में लिये गये स्टीवडोर के निर्णय के समर्थन में, बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये।</p>
(iv)	<p>वि पो द्र द्वारा दिनांक 1.7.2010 से दैनिक मदजूरी दर पर लेवी 350% का प्रस्ताव फाइल किया गया। कार्गो संभलाई प्रभाग के कर्मकारों की नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित लेवी के संबंध में ट्रेड सदस्यों के साथ आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में यह दिखाया गया है कि ट्रेड ने वर्तमान प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली की पद्धति कुछ समय तक जारी रखने का अनुरोध किया। सरकारी निदेशों के अनुसार वि पो द्र टन्नेज के आधार पर दरों में परिवर्तन लाने के पहले कितने समय तक का लेवी की प्रतिशत पद्धति जारी रखेगा, यह स्पष्ट नहीं है।</p>	<p>वि पो द्र ने लेवी दर 350% वसूल करने का प्रस्ताव उस समय तक रखा है जब तक दिनांक 31.3.2009 को रु. 21.78 करोड़ प्रोद्भूत वित्तीय कमी और आगे दिनांक 31.3.2010 तक (लेखा परीक्षा के अनुसार) रु. 41.74 करोड़ की प्रोद्भूत और साथ में पेंशन निधि में रु. 166 करोड़ कमी को पूरा नहीं किया जाता। यह प्रत्याशित है कि प्रस्तावित दर 350% 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा ताकि प्रोद्भूत वित्तीय कमी के साथ साथ पेंशन निधि की कमी को भी पूरा किया जा सकें। यदि वही 5 वर्ष से कम समय में होने से, मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करेगा।</p>
(v)	<p>सी एच डी से नियोजित श्रमिकों की उत्पादकता के संदर्भ में वी पो द्र द्वारा दिया गया कार्गोवार निष्पादन का आश्वासन स्पष्ट रूप से बताना होगा, जो दर-मान में एक शर्त के रूप में शमिल किया जाएगा। वी पो द्र को स्पष्ट करे कि प्रस्तावित दर प्राप्त करने केलिए कैसे मान लिया कि पोर्ट में कार्गो संभलाई कर्मकारों के विलयन से उत्पादकता में वृद्धि होगी।</p>	<p>व्यापार योजना में सूचित पूर्वानुमान के आधार पर भविष्य में वर्तमान कार्गो प्रोफाइल ही जारी रहेगा। सीएचडी कर्मकारों को वर्क चान्सेस उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्याशित है कि भविष्य में भी बल्कि कार्गो संभलाई जारी रहेगा और इस के लिए सीएचडी कर्मकारों को नियुक्त करने के लिए कारण होगा। इस आश्वासन पर, पोर्ट ने भविष्य में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल करने का प्रस्ताव किया। यिलीन के बाद सीएचडी के उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई।</p>

(vi)	<p>(क) मंत्रालय द्वारा गठित त्रिपक्षीय निकाय में प्रबंधन के, यूनियन और स्टीवडोर से सदस्य होते हैं प्रस्ताव में बताया गया है कि त्रिपक्षीय निकाय के अनुमोदन के आधार पर पोर्ट द्वारा 189% समय दर मजदूरी वसूल किया जाता है। कृपया वर्तमान लेवी की मञ्जूरी प्रति और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राजपत्र की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करें।</p>	<p>त्रिपक्षीय निकाय में यूनियन, स्टीवडोर के प्रतिनिधि और प्रबंधन से सदस्य होते हैं उनके द्वारा समय दर मजदूरी 189% वसूली करने का संकल्प किया गया। आगे, डॉक लेबर बोर्ड के लेवी दरों को राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए इसके लिए राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध नहीं है।</p>
	<p>(ख) पहले ही निर्धारित किया वर्तमान 189% लेवी अतीत में किस आधार पर निर्धारित की गई उसके बारे में संक्षिप्त में स्पष्टीकरण दें।</p>	<p>वर्तमान 189% लेवी में विविध प्रकार की लेवी है अर्थात् 95% दर पर सामान्य लेवी, 39% दर पर विशेष लेवी और 50% दर पर अतिरिक्त लेवी और समय दर मदजूरी पर 5% का उत्पादकता लिंकड रिवार्ड लेवी। संगठन के प्रशासनिक व्यय के लिए सामान्य लेवी, श्रेणी - I और श्रेणी - II के अधिकारियों के लिए और श्रेणी - 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के बकायों खाते पर व्यय को पूरा करने के लिए विशेष लेवी, संचित वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लेवी और 5% लेवी कर्मकारों को पीएलआर चुकाने के लिए। यह जिम्मेदारी सिर्फ स्टीवडोर की है जो डॉक कर्मकार रोजगार विनियम एवं रोजगार अधिनियम योजना के अंतर्गत पहले में ही रखा गया।</p>
(vii)	<p>प्रस्ताव यह बताता है कि थर्मल कोल पर समय दर मजदूरी तथा पीस-रेट (उजरती दर) भुगतान वास्तविकता पर वसूल किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जाए :-</p>	
	<p>(क) इस कार्गो मद के लिए केवल वास्तविकता के आधार पर ही लेवि जुटाने के लिए भिन्न तरीका प्रस्तावित करने के कारणों का औचित्य बतायें।</p>	<p>इस पोर्ट में बल्क में बड़ी मात्रा में थर्मल प्राप्त किया जाता है और कार्गो संभलाई का परिचालन डॉक वर्कर्स द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में चूँकी स्टिवडोर्स को सभी भुगतानों सहित समय-दर मजदूरी, पीस-रेट (उजरती दर) भुगतान तथा लेवि प्रतिशत के अलावा समयोपरी भत्ता इत्यादि का अन्य व्यय भुगतान करना पड़ता है, तथा इस पोर्ट में और अधिक कार्गो आकर्षित करने के उद्देश्य से थर्मल कोल के लिए लागत सार्थकता का प्रस्ताव किया गया। इसको ध्यान में रखकर थर्मल कोल पर समय-दर मजदूरी (टाइम-रेट थेजि) किया और पीस-रेट भुगतान संग्रह करने का प्रस्ताव किया गया।</p>

	(ख) कृपया थर्मल कोल संभलाई के लिए अमिकों को नियोजित करने संबंधी वास्तविक आय और वास्तविक व्यय के बारे में, विलयन से पूर्व और विलयन के बाद की अवधि के लिए अलग से लागत विवरणिका में सुचित करें।	विलयन से पूर्व और विलयन के बाद की अवधि के लिए थर्मल कोल संभलाई हेतु नियोजित श्रमिकों के बारे में वास्तविक आय और वास्तविक व्यय के विवरण प्रस्तुत किया गया है। वि. पो. द्र. द्वारा थर्मल कोल के लिए प्रस्तुत की गयी लागत विवरणिका का सारांश नीचे दिया गया है :																				
		(रु. लाख में)																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>26.09.08 से 31.03.09 तक</th><th>2009-10</th><th>01.04.10 से 31.08.10 तक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td><td>आय</td><td>469.47</td><td>1009.96</td><td>1500.35</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>व्यय</td><td>757.41</td><td>1544.48</td><td>1039.71</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>अधिशेष / हानि</td><td>(-287.94)</td><td>(-534.52)</td><td>(-460.64)</td></tr> </tbody> </table>	क्रमांक	विवरण	26.09.08 से 31.03.09 तक	2009-10	01.04.10 से 31.08.10 तक	(i)	आय	469.47	1009.96	1500.35	(ii)	व्यय	757.41	1544.48	1039.71	(iii)	अधिशेष / हानि	(-287.94)	(-534.52)	(-460.64)
क्रमांक	विवरण	26.09.08 से 31.03.09 तक	2009-10	01.04.10 से 31.08.10 तक																		
(i)	आय	469.47	1009.96	1500.35																		
(ii)	व्यय	757.41	1544.48	1039.71																		
(iii)	अधिशेष / हानि	(-287.94)	(-534.52)	(-460.64)																		
(ग)	कृपया यह दर्शायि कि, लेवि के लिए थर्मल कोल की संभलाई हेतु अप्रत्यक्ष लागत जैसे अतिरिक्तों (ओवरहैड्स) इत्यादि को कैसे निर्धारित किया जा सकता है ?	लेवि रेट के लिए अप्रत्यक्ष लागत जैसे अतिरिक्तों (ओवरहैड्स) का संग्रह, थर्मल कोल और अन्य कार्गो की मात्रा के बीच अनुपात के आधार पर किया जाता है।																				
(घ)	कृपया पुष्टि करें और दिखायें कि इस कार्गो द्वारा अन्य कार्गो से किसी प्रकार का क्रास सबसेडि प्राप्त नहीं किया गया है।	यह पुष्टि किया जाता है कि इस कार्गो द्वारा कोई क्रास सबसेडि प्राप्त नहीं की गयी है और उसके समर्थन में लागत विवरणिक संलग्न की गयी है।																				
(च)	थर्मल कोल पर पी आर लेवि शब्द की व्याख्या दें। थर्मल कोल से इस प्रकार की लेवि जुटाने के लिए विद्यमान प्रक्रिया समझायें।	सामान्य लेवि 95% के अलावा, उत्तराई वैगनों पर थर्मल कोल परिचालन के लिए नियोजित वर्कर्स के समय-दर मजदूरी का 95% की दर पर एक अन्य लेवि वसूल किया जाता है और इसे पी.आर. लेवि कहा जाता है तथा वर्तमान लेवि का प्रतिशत 300% है जबकि 1.4.2010 से 30.6.2010 तक यह 250% था।																				
(viii)	वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए 25 सितंबर 2008 तक एवं 26 सितंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक (अगस्त 2010 तक) का वी.डी.एल.बी. को वी.पी.टी.के साथ विलयन के बाद एवं वर्ष 2010-11 से 2013-14 के प्राक्कलन के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें :-																					
	(क) प्रति हुक / प्रति गैंग वर्कर्स का ऑन-बोर्ड गठन (कम्पोजिशन)	प्रति हुक / प्रति गैंग ऑन-बोर्ड वर्कर्स का गठन वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए 25.9.2008 तक तथा 26.9.2008 से 31.3.2009 तक 2010-11 तक (अगस्त 2010 तक) वी.डी.एल.बी. को वी.पी.टी.के साथ विलयन के बाद तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है।																				
	(ख) संभलाया गया कार्गोवार वास्तविक यातायात तथा सी एच डी से सर्विसेस प्राप्त वर्ष 2007-08 से 31.3.2010 तक, तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए प्रक्षेपण सहित प्रस्तुत किया गया है।	संभलाया गया कार्गोवार वास्तविक यातायात तथा सी एच डी से सर्विसेस प्राप्त वर्ष 2007-08 से 31.3.2010 तक, तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए प्रक्षेपण सहित प्रस्तुत किया गया है।																				

(ix)	<p>परिशोधित ईरिफ (प्रशुल्क) मार्गदर्शन के खण्ड 2.6.2 के अनुसार, विधि की सम्यक प्रक्रिया के बाद कार्मिक आवश्यकता माप / डॉट्स को नियमित रूप से व्यवस्थित करना आवश्यक है। साथ ही समझौता ज्ञापन में यह अनुबन्ध है कि वर्कर्स का नियोजन, यूनियनों द्वारा नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड पर फाइल की गयी रिट्रिटिशन (समादेश-याचिका) के निष्कर्ष की शर्त पर होगा। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल एवार्ड वर्ते रोका हुआ दिया और देश के सभी नैशनलों में इसी तुरंत कार्यान्वयित अखल के आदेश दिये। अतः वी पी टी को पुरावर्ता हु कि, यह नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड के अनुसार परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप उनी, रोक एवं वी पी ले अभिक विभाग के लिए में कार्यान्वयित किया जाया है? इस विधय में वी पी टी कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें।</p>	
	<p>(क) नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड द्वारा परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप अधिसूचित करने से पूर्व कार्मिक आवश्यकता माप का पुनरीक्षण करने के बाद विविध वस्तुओं के लिए कार्मिक आवश्यकता माप की तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाली एक विवरणिका।</p>	<p>वी पी टी ने नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड का कार्यान्वयन विचार करने से अनुसार कार्मिक आवश्यकता माप वी नये बनाये। वर्तमान कार्मिकशक्ति का नियोजन परिशोधित कार्मिक आवश्यकता मापन के अनुसार है। पत्र में यथा सूचित अनुसार नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड द्वारा परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप अधिसूचित करने से पूर्व वाद कार्मिक आवश्यकता माप का पुनरीक्षण करने के बाद विविध वस्तुओं के लिए कार्मिक आवश्यकता माप की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की गयी है।</p>
	<p>(ख) कृपया स्पष्ट करें कि लागत विवरण में स्वीकृत (टाइम-रेटवेज कॉस्ट) समय-दर मजदूरी लागत, परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप के अनुसार अभिक के वास्तविक नियोजन के आधार पर है, और इस संबंध में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए परिकलन प्रस्तुत करें।</p>	<p>लागत विवरणिका में स्वीकार की गयी टाइम-रेट-वेज (समय-दर मजदूरी) परिशोधित कार्मिक आवश्यकता मानक के अनुसार अभिक के वास्तविक नियोजन के आधार पर है। संबंधित वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए स्वीकृत परिकलन के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।</p>
	<p>(ग) वि.पो.द्र. ने 2010-11 से 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 313 संख्या में नैमित्तिक मजदूरों को स्वीकार किया है। कृपया यह सूचना दें कि लागत विवरण में नैमित्तिक मजदूरों के लागत के संबंध में क्या निरूपण दिया गया हैं और यह भी सूचना दें कि, किस कार्गों संभलाई कार्यप्रणाली के लिए उन्हें नियोजित किया गया। कृपया लागत विवरणिका में अनुभानित नैमित्तिक मजदूरों की लागत दर्शाने के लिए छार्टवाइट प्रत्रतुत करें दि - यह राज्यकोष झाजन के अनुसार, प्रति दिन रु. 250 रेटिकल मजदूरी के आधार पर है</p>	<p>वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक हर वर्ष स्वीकारी 313 नैमित्तिक मजदूरों को डी एल बी के नियमित अभिकों वी रामाप्ति होने के बाद तटीय तथा कार्गों संभलाई परिचालन के लिए नियोजित किया गया। लागत विवरण तैयार करते राज्य इन नैमित्तिक मजदूरों को दिया गया निरूपण, अलग से दिलाता रहा है।</p>

(घ) कृपया विलयन के बाद की अवधि, तथा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए कार्य संभलाई मजदूरों की (वर्षधार) नियुक्ति के औसतन दिनों की सूचना दें। कृपया दर्शायें कि, वी डी एल बी विलयन के बाद सी एच डी से मजदूरों की कोई नैशनल बुकिंग नहीं हुई है।

सी एच डी के औसतन दिनों की नियुक्ति को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत है। संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है :

पंजीकृत कर्मकार :

वर्ग	वास्तविकता		अनुमान		
	2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
टाली क्लक	23	7	14	13	14
टिडल	23	7	14	14	14
विच डाइनर	18	10	13	14	15
टी/सिंगल मैन	21	17	20	21	23
मजदूर्स	22	12	19	20	21

गैर पंजीकृत कर्मकार :

वर्ग	वा	वकता	अनुमान				
			2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
डब्ल्यू/यूएल मिस्ट्री	23	13	--	--	--	--	--
आई एड एस टिडल्स	17	13	16	20	20	20	20
आई एड एस मिस्ट्री	22	--	20	20	21	21	21
जी के मिस्ट्री	22	--	--	--	--	--	--
डब्ल्यू एस स्वीप्स मजदूर्स	24	--	--	--	--	--	--
नैमितिक मजदूर	--	7	13	13	13	14	14

विलयनेतर परिदृश्य में, यह बताया जाता है कि सी एच डी से कोई नैशनल बुकिंग नहीं रही और इसे शून्य समझा जाये।

(घ) वी डी एल बी का वी पी टी के साथ विलयन के लिए पृष्ठ सं. 7 में दि.8 सितंबर 2008 के समझौता ज्ञापन की प्रतिलिपि बताता है कि, नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड के कार्यक्रम आवश्यकता मापन के अनुसार वर्तमान डैक फोरमैन अनावश्यकवर्ग के हैं, तथा वर्तमान डैक फोरमैन के लिए अदालती मामले का निपटारा होने के बाद विचार करने के लिए निर्णय लिया गया। उक्त अदालती मामलों की वर्तमान स्थिति बताये और यह बतायें कि उक्त मुकदमेबाजी का सी एच डी लेवि के लिए वी पी टी द्वारा फाइल की गयी (टैरिफ) वर्तमान प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव पर कोई प्रभाव है।

डैक फोरमैन से संबंधित उपार्जित लागत फिलहाल सहायक श्रम आयुक्त (ए एल सी) (केन्द्रीय) को वापस भेजा गया है और यह अबतक ए एल सी के पास लंबित है। डैक फोरमैन के वर्ग को डैक कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत करने के कारण, ये डैक फोरमैन को चुकाये गये वेतन स्टिवलोर्स द्वारा वसूल किया जाएगा और इन वेतन पर लागू लेवि कम्पोनेन्ट भी वि पी टी को प्राप्त होगा। फिर भी परिकलन करते समय डैक फोरमैन को दी गयी टाइम-रेट मजदूरी तथा वसूली को शून्य कर दिया जाएगा तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को, सांविधिक निधि इत्यादि को पूरा करने के लिए केवल लेवि कम्पोनेन्ट ही प्रशासन के पास होगा। इस वर्ग के अंतर्गत केवल 16 डैक फोरमैन हैं, इससे वर्तमान प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ix) (क) पीस-रेट बेजेस मुगलान को प्रोत्साहन योजना के अनुरूप बताया गया है। कृपया वर्तमान प्रोत्साहन योजना का विवरण दें जिसके आधार पर वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए समय-दर मजदूरी अनुमानित किया था।

सी एच डी के डॉक मजदूरों के लिए लागू होने के लिए बनायी गयी प्रोत्साहन योजना की प्रति संलग्न की गयी है। यह योजना शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी। वर्तमान प्रोत्साहन योजना दि.1.5.2010 से निर्णयि किया गया है और प्रस्ताव के साथ ग्रस्तुत की गयी लागत विवरणिका में वर्तमान प्रोत्साहन योजना शामिल है।

(ख) परिशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 4.7.3 को सभी महा पत्तनों में नैशनल वेज सेटलमेंट के निबंधन में समय समय पर डाटम और पीस-रेट स्कीम की दरों को परिशोधित करना अपेक्षित है। वर्तमान पीस-रेट के

पूर्व पैरा में पहले ही उल्लिखित अनुसार नयी प्रोत्साहन योजना को दि.1.5.2010 से परिशोधित किया गया था जिसमें डॉट्स भी परिशोधित किया गया। 5 वर्षों का आवर्तन, नैशनल वेजसेटलमेंट के निबंधन में टैम्प के बराबर है, अतः बाद का परिशोधन 5 वर्षों के बाद किया जाएगा। फिर भी भविष्य में होने वाले उत्पादन को

	मामले में पिछली बार डॉट्स कब परिशोधित किया था, कृपया इसकी सूचना दें। विलयन के बाद पीस रेट स्कीम को औचित्य बनाने के लिए वि पी टी द्वारा किये गये उपायों के बारे में बतायें।	ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर डॉट्स को परिशोधित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
(xi)	<p>(क) पोर्ट के व्यापारिक योजना की श्रेणी में मजदूरों की नियुक्ति का अनुमान लगाने के लिए मान्यता प्राप्त यातायात और राजस्व का पुष्टिकरण करें। कृपया टाइम-रेट, पीस-रेट तथा लेवि से राजस्व परिकलन के विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>(ख) वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए अनुमानित आय में क्वार्टर्स, स्टाल्स तथा बिल्डिंग्स के किराये से अनुमान के आधार को स्पष्ट करें।</p>	आवश्यकता योजनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके मजदूरों को पूरा रोजगार मिलेगा और तदनुसार राजस्व का परिकलन किया गया है। लागत विवरणिका में संलग्न टाइम-रेट, पीस-रेट तथा लेवि से राजस्व का परिकलन, टैम्प को प्रस्तुत किया गया है।
	(ग) प्रशासन प्रभार डैक फोरमैन, भाड़ा प्रभार-एस एस वी तथा विद्युत एवं गैस प्रभार एस एस वी अन्य प्राप्तियां विलंब भुगतान पर व्याज, सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों का चिकित्सा प्रभार, भाड़ा प्रभार तथा विद्युत एवं गैस प्रभारों से अनुमानित आय की प्रवृत्ति किस आधार पर की गई, इसका वर्णन करें साथ ही स्टिवडोरिंग परिचालन के लिए मजदूरों को नियोजित करने के प्रति लेवि निधीरित करने के लिए इसकी संबद्धता का वर्णन करें।	क्वार्टर्स से किराये की आय वर्तमान अभिभावण के आधार पर की गयी है और साथ ही दरों का विचार संबंधित वर्गों के लिए लागू होने के अनुसार किया गया है। स्टाल्स और अन्य बिल्डिंग्स पर विवाया आय, संगठन द्वारा फिलहाल व्याप्त मासिक किराया मूल्यों के आधार पर है।
	(घ) पोर्ट ट्रस्ट ने बताया कि वर्तमान लेवि (प्रस्तावित परिशोधन से पूर्व) टाइम-रेट वेजेस का 189% है। इसके विपरीत, वि पोर्ट द्वारा 1.4.2008 से 25 सितंबर 2008 तक उसके बाद 31 मार्च 2009 अवधि तक टाइम रेट प्रतिशत के संबंध में जुटाई गयी वास्तविक लेवि 87% तथा 123% होता है। बाद के दो वर्ष 2009-10 के लिए यह वास्तविक टाइम रेट वेजेस का 143% है; कृपया 189% पर रिपोर्ट की गयी वर्तमान लेवि के संबंध में वैधता के कारण बताएं और सही स्थिति बताएं।	प्रशासन प्रभार से उत्पन्न आय - डैक फोरमैन तथा विलंब भुगतान पर व्याज मजदूरों तथा कार्यालयों से संबंधित है, अतः उसे लेवि निर्धारण प्रयोजन के लिए जल्दी जाना जाएगा; अन्य दरों एस एस वी, विद्युत तथा एस एस वी और जैसे जागत प्रभार, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से चिकित्सा प्रभार, भाड़ा प्रभार तथा विद्युत एवं लागत प्रभारों को भी लेवि निर्धारण के समय में स्वीकार किया जाता है वहाँके लेवि का प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों को ज्ञानने के लिए हैं जिसमें उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत होने वाले व्यय शामिल हैं। अतः यह बताया जाता है कि उपर्युक्त शीर्ष पर उत्पन्न आय को स्टिवडोरिंग आपरेशन्स के लिए मजदूरों को नियोजित करने के लिए लेवि निर्धारण में युक्तसंगत होगा, वहाँके संगठन के सभी प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के साथ साथ मजदूरों के कल्याणकारी उपायों की जिम्मेदारी भी स्टिवडोर्स की है।
	(ix)	उत्पर्युक्त क्रम सं. (vi) (ख) में उल्लिखित अनुसार 189% लेवि, विशेष लेवि का सम्मिश्रण है जिसमें सामान्य लेवि का उपायान (कम्पोनेन्ट) ही आय और व्यय के ब्यौरा में दिखाया गया है। बाकी उपर्युक्त (कम्पोनेन्ट) विशेष प्रत्यक्षि के हैं अतः उन्हें संबंधित लेवि अंक में समाझोजित किया गया, अतः 1.4.2008 से 25.9.2008 तक उसके बाद 31.3.2009 अवधि के लिए लेवि प्रतिशताता में विकल्प हुई। प्रारंभ में वेतन पुनरीक्षण बकायों के लिए दिशेष लेवि उदास 20% ही स्वीकार किया गया था जो बाद में 35% तक उदास दिया गया, इसके सपोर्ट में मंडल संकल्प की प्रति प्रस्तुत हो रही है। वर्कर्स को पी एल आर भुगतान के लिए सदृश अंक 15% लेवि, संबंधित घी एल आर निधि के शीर्ष में विकल्प हो रहा है। अतः इसे आय और व्यय में अंक में नहीं दिया जाएगा। दूसरी प्रकार उसे वार्षिक अधि और व्यय की कमी को पूरा करने के लिए जुटाई गयी 50% लेवि भी सामान्य आरक्षण निधि में जातीरह किया जा और तदनुरूप यह उपायान (कम्पोनेन्ट) भी आय के व्यापार में नहीं दिखाया गया।

	(घ) स्टिवडोरिंग सर्विसेस का प्रशुल्क निर्धारण करने में को-ऑपरेटिव सोसाइटि के ऋण पर व्याज आमदनी को विचारने की युक्तिसंगत का विवरण दें।	वि डी एल बी ने कोऑपरेटिव सोसाइटि को ऋण रकम दिया जो वि डी एल बी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए है। डॉक वर्कर्स विनियम तथा रोजगार अधिनियम के तहत योजना के प्रावधान के अनुसार, सोसाइटि सहित डॉक वर्कर्स के कल्याण उपाय, ऋण प्रदान करने द्वारा अथवा अन्यथा डॉक वर्कर्स के लिए बनी विशेष लाभ के लिए तथा मंडल के लाभार्थी, समय समय पर मंडल द्वारा ऋण प्रदान किया गया। अतः इस प्रक्रिया में लागत विवरण में उपादान (कम्पोनेन्ट) शामिल नहीं किया गया है। फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटि के ऋण पर व्याज आय को प्रशुल्क निर्धारण में विचारा गया क्योंकि निधियों को वि डी एल बी के सामान्य आरक्षण निधि से व्यवस्थित किया गया, जो मुख्यतः लेवि उपादान (कम्पोनेन्ट) से संचित किया गया था। जो टाइम-रेट वेजेस का एक विशिष्ट प्रतिशत के अलावा और कुछ नहीं है। अतः इसे आरक्षण निधि पर संचित राजस्व का हिस्से के रूप में माना गया और लागत विवरण में इस कम्पोनेन्ट (उपादान) को शामिल किया गया। वि. पो. द्र. के साथ वि डी एल बी विलयन होने के बाद सोसाइटि को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया।
(xii)	व्यय प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)	डॉक वर्कर्स के वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित की गयी टाइम दर वेज प्रभाव को मान लिया गया है।
	(क) वर्ष 2010-11 के लिए रु. 1395.19 लाख पर अनुमानित टाइम-रेट वेज के कारण स्टॉफ तथा अधिकारियों पर वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव पड़ा है तो कृपया इसकी पुष्टि दें।	टैम्प के पत्र दि. 18.5.2010 द्वारा यथा सूचित 3.76% स्वतः वृद्धि घटक (फैक्टर), सी एच डी द्वारा टाइम-रेट वेजेस के संबंध में, मजदूरों को भुगतान, स्टॉफ भुगतान तथा सांविधिक निधियों के अंशदान संबंधी व्यय के मामले में लागू नहीं हो सकता। इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि, व्यय का बड़ा हिस्सा केवल लेबर कम्पोनेन्ट (मजदूर घटक) के रूप में होने के कारण लागत विवरणिका तैयार करते समय स्वतः वृद्धि फैक्टर को 5% से 10% रेंज तक माना गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर सी एच डी के लिए 3.76% स्वतः वृद्धि फैक्टर का लागू होना, को छूट दिया गया है।
	(ख) हमारे पत्र सं. टैम्प/27/2005-विविध, दिनांक 18 मई 2010 में सभी महा पत्तनों को वर्ष 2009-10 के लिए डब्ल्यू पी आई में औसतन संचालन के आधार पर सूचित अनुसार, 3.76% का स्वतः वृद्धि घटक (फैक्टर) को वर्ष 2010-11 में निर्धारित की जाने वाली प्रशुल्क मामलों में विचार किया जायेगा। अतः वि. पो. द्र. द्वारा अनुमान में विचारी गयी वार्षिक स्वतः वृद्धि को उक्त स्तर पर परिवर्तित किया जाये।	वर्ष 2009-10 के लिए पेंशन निधि के लिए रु. 8,52,87,600/- तथा उपदान निधि के प्रति रु. 5,43,04,899/- योगदान अनुमानित किया गया है। पेंशन निधि और अन्य निधियों के लिए मंडल के योगदान में तीव्र वृद्धि, वेतन पुनरीक्षण के कारण स्टॉफ/मजदूर तथा अधिकारियों को मजदूरी/वेतन में वृद्धि होने से हुई। मजदूर एवं स्टॉफ के लिए लगभग 26% वृद्धि है।
	(ग) प्रस्तावित लेवि, जो संग्रह किया जाना है, वह ऊपरी व्यय के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, उपदान, वार्धक्य-निवृत्ति इत्यादि को कवर करने के लिए है। पेंशन निधि/उपदान निधि योगदान के लिए अनुमानित रकम सूचित करें। अनुमोदित करें कि, प्रस्तावित लेवि इन दायिताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।	

	<p>पेशन निधि तथा और अन्य निधियों के लिए वर्ष 2008-09 में मंडल का योगदान रु. 565 लाख रिपोर्ट किया गया यानि 1403 लाख है जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है। भविष्य की अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए वार्षिक रु.1053 लाख से रु. 1048.76 लाख तक अनुमानित किया गया है। वर्ष 2009-10 में इस मद में तीव्र वृद्धि के कारण बताये, तथा इस संबंध कार्यचालन प्रस्तुत करें। राजस्व के स्त्रोत जहां से मंडल ने उक्त योगदान बनाया था, उसकी सूचना भी दें।</p>
	<p>(घ) वेतन बकाया प्रावधान दि.1.1.2007 से फरवरी 2010 के कार्यचालन में विचार किये गये अंक स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत करें:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए वास्तविक मजदूरी लागत वर्गवार, विधिवत रूप से कुल वेतन लागत को तत्संबंधित वार्षिक लेखा में रिपोर्ट किये गये अंकों के साथ भिलान करते हुए आंकड़े। ➤ कार्यचालन के साथ-साथ वास्तविक वेतन लागत के आधार के संबंध में वर्गवार वेतन पुनरीक्षण प्रभाव का परिकलन। ➤ वर्ष 2007-08 से 2009-10 में वेतन पुनरीक्षण के लिए किया गया प्रावधान। ➤ प्रशुल्क मार्गदर्शन को खण्ड 2.5.2 जिसमें यह विर्दिष्ट किया गया, कि एक बारी व्यय (वन टाइम एक्सपेन्डीचर) जैसेकि वेतन का बकाया और पेशन, वी आर एस प्रतिपूर्ति आदि को प्रशुल्क निर्धारित करते समय स्वीकार्य लागत के रूप में शामिल नहीं किया गया था। वि.पो.ट्र. ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए "वेतन पुनरीक्षण अधिकारी, स्टॉफ एवं मजदूर" नामक शीर्षक के अंतर्गत एक अलग लागत अनुमानित किया था। कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह अनुमान वेतन बकाया के लिए था। यदि हो, तो यह प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 2.5.2 की पद्धति में नहीं है और प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में गठित नहीं किया सकता है।

	(च) प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 2.5.2 के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित करते समय वी आर एस लाभ को लागत मद के रूप में लागत विवरण में शामिल नहीं किया गया, इसलिए संभवतः हटा दिया गया ।	
(xiii)	<u>नियोजित पूँजी :</u>	
	(क) सी एच डी के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र-4ए के अनुसार नियोजित पूँजी का विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत करें ।	सी एच डी के लिए नियोजित पूँजी का विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत किया गया है ।
	(ख) परिसंपत्तियों को व्यापार परिसंपत्ति और व्यापार से संबंधित परिसंपत्ति के रूप में पृथक्करण करने का आधार सूचित करें और पुष्टि करें कि यह टैरिफ मार्गदर्शन की खंड 2.9.7 के अनुसार है ?	परिसंपत्तियों को व्यापार परिसंपत्ति और व्यापार से संबंधित परिसंपत्ति के रूप में पृथक्करण टैरिफ मार्गदर्शन की खंड 2.9.7 के अनुसार ही किया गया है ।
(xiv)	कृपया सूचित करें कि वर्तमान सैटअप में कोई अधिशेष श्रमिक हैं और क्या उस प्रकार की अधिशेष श्रमिकों के लिए हुई व्यय लागत सारणी में शामिल किया गया ?	सी एच डी ने कार्य की दृष्टि से देखने पर कम हो रही श्रमिक शक्ति पर ध्यान रखते हुए 313 कर्मकारों को कैजुअल कर्मकार के रूप में विचार किया । यह भी सूचित किया जाता है कि इन 313 कैजुअल कर्मकारों को जोड़ने पर भी जब कभी आवश्यक पड़ती है तो बाहर से प्राईवेट कर्मकारों को लेने के लिए स्टीवडोरों को अनुमति दी गई है ।
(xv)	वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 और 2009-2010 से संबंधित कार्ग संभलाई प्रभाग की संशोधित लागत सारणी का संक्षिप्त विवरण और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक प्राक्कलन निम्नानुसार है :	यह पुष्टी किया जाता है कि किसी भी कॉस्ट इलिमेंट में या सामान्य पुनरीक्षण प्रस्ताव में प्राक्कलित पूँजी नियोजन में और सी एच एल डी के लिए प्रस्तुत लागत सारणी में कोई ओवरलेपिंग नहीं है । इस संबंध में सी एच डी से संबंधित कांपोनेंट्स को हटाते हुए एक वर्क शीट प्रस्तुत किया जाता है ।

6.2 वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 और 2009-2010 से संबंधित कार्ग संभलाई प्रभाग की संशोधित लागत सारणी का संक्षिप्त विवरण और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक प्राक्कलन निम्नानुसार है :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	वास्तव		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(i)	कुल आय	4424.62	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22
(ii)	व्यय (आर औ सी ई के अलावा)	5172.36	5594.06	5745.22	5745.21	5968.09	6148.86
(iii)	पूँजी नियोजन	प्रस्तुत नहीं किया	209.03	185.99	163.86	141.73	119.61
(iv)	आर औ सी ई :						
	व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	10.31	9.04	7.91	6.77	5.65
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	9.18	8.22	7.27	6.31	5.35
(v)	कुल व्यय + (आर औ सी ई) (ii+iv)	5172.36	5613.55	5762.48	5760.69	5981.17	6159.86
(vi)	आय से अधिक व्यय (I-v)	(748.10)	(2440.45)	(1233.10)	(1268.48)	(1352.18)	(1381.64)

- 7.1 दि.2 नवंबर 2010 को विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में इस मामले पर संयुक्त सुनवाई हुई । वि पो ट्र ने इसकी प्रस्ताव पर एक पावर प्वार्इट प्रजेंटेशन दिया । इस संयुक्त सुनवाई में वि पो ट्र एवं संबंधित उपभोक्ता / संगठन निकाय ने उनकी प्रस्तुति दिए हैं ।
- 7.2 संयुक्त सुनवाई में लिया गया निर्णय के अनुसार वि पो ट्र को निम्न लिखित प्वार्इटों पर अपना उत्तर देने के लिए सुझाव दिया गया :
- (i) पिछली अवधि तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक व्यय का विस्तृत ब्रेक-अप विचाराधीन है ।
 - (ii) इस कार्यकलाप से संबंधित पिछले अवधि की हानि क्या है और वर्तमान टैरिफ में उस प्रकार की पिछली हानि को समायोजित करने के लिए की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण दें । पोर्ट को समीक्षा करना होगा कि किस अवधि के अंदर इस प्रकार की पिछली हानि को पुनःवसूल करने का प्रस्ताव है ।
 - (iii) संयुक्त सुनवाई के दौरान एक यूजर एसोसियेशन ने बताया कि पोर्ट ने प्रस्तावित लेवी को पहले ही 350% से 300% तक कम किया । पोर्ट की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में लेवी के प्रस्तावित प्रतिशत पर समीक्षा की जाए ।
- 7.3 संयुक्त सुनवाई में चर्चा किए गए प्वार्इटों के संदर्भ में वि पो ट्र ने अपना उत्तर दि.18 नवंबर 2010 को दिया । वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्वार्इटों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :
- (i) पिछली अवधि तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक व्यय का विस्तृत ब्रेक-अप सारणी सहित एक सारणी प्रस्तुत की गई है । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की तुलना में वर्ष 2009-10 व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण दि.1.1.2007 से श्रेणी-1 एवं 2 अधिकारी तथा ग्रूप सी एवं डी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अनुपालन से हुई और बकाया वर्ष 2010-11 के दौरान चुकाया गया । शीर्ष “स्वारक्ष्य” के अंतर्गत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों (लगभग 3000 पेंशनर्स) को और परिवार पेंशनर्स को रेशनलाईजड चिकित्सा सुविधा विस्तार करना था, जिस में इन हाऊस इलाज करने की वर्तमान पद्धति से हटकर रिफरल मामलों को बाहरी अस्पतालों में भेजना भी शामिल है । श्रेणी-1 अधिकारियों के कैडर रीस्ट्रक्युरिंग के अनुपालन के परिणाम रूप में वार्षिक वेतनवृद्धि के अलावा वेतन में वृद्धि को वर्ष से वर्ष के आधार पर विचार करने से हुई ।
 - (ii) पहले वी डी एल बी को एक कार्यकलाप होता था अर्थात मैन्युअल कार्गो संभलाई परिचालन । दि.31.3.2009 तक गणन की गयी पिछली अवधि की हानि ₹.22.57 करोड थी और दि.31.3.2010 तक संचित शुद्ध हानि ₹.55.40 करोड थी । पूर्व हानि को समायोजित करने के लिए वर्तमान सी एच डी ने वर्तमान टैरिफ को दि.1.4.2010 से तीन महीने की अवधि के लिए 189% से 250% तक, और दि.1.7.2010 से 31.12.2010 तक 300% की दर पर और दि.1.1.2011 से 350% की दर पर बढ़ाने का प्रस्ताव किया । इन प्रतिशत पर विचार करते हुए और दि.1.1.2011 से 350% लेवी जारी रखने के कारण वार्षिक हानि घाटा दि.1.4.2010 से 5 वर्षों में समायोजित करने का अनुमान है ।

(iii) संयुक्त सुनवाई में पहले ही बताए गए अनुसार बढ़ाया गया लेवी 350% से 300% तक कम करने के लिए व्यापारियों के अनुरोध पर विचार करते हुए 300% की दर पर संशोधित लागत लेवी सारणी गणन किया गया और संशोधित लागत सारणी प्रस्तुत किया गया। 300% की दर पर प्रतिशत को मानते हुए पिछली हानि दि.1.4.2010 से 7 से 8 वर्षों में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है। लेवी के रूप में 189%, 250%, 300% एवं 350% के साथ आय और व्यय की तुलनात्मक सारणी प्रस्तुत है। वर्ष 2010-11 में दि.1.4.010 को कर्मकारों की संख्या 958 थी जबकि वी आर एस का अनुपालन के कारण दि.1.8.2010 को संख्या 873 तक कम हुई। तदनुसार टाईम रेट भजदूर का एवं लेवी आय का गणन किया गया।

(iv) संशोधित लागत सारणी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	विवरण	वार्षिक		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	लेवी %			250% 300%	300%	300%	300%
(i)	कुल आय (लेवी आय सहित)	4424.26	3089.69	8624.30	8026.82	8644.42	9326.06
(ii)	व्यय (आर औ सी ई के अलावा)	5172.36	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii)	पूँजी नियोजन	--	--	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv)	आर औ सी ई व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	--	6.89	4.43	2.22	0.01
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	--	6.97	4.61	2.29	0.01
(v)	कुल व्यय + आर औ सी ई (ii+iv)	5172.36	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi)	आय से निधिक व्यय (i-v)	(748.10)	(4174.03)	--	--	--	--
(vii)	व्यय से अधिक आय (i-v)	--	--	798.69	529.17	707.61	831.58
(viii)	पूर्व अवधि ली हानी को समायोजित करने वाल घाटा / अधिशेष	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4212.14)	(3504.53)	(2672.95)

उपर्युक्त मद सं.2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत सूचना से पूर्वावधि की हानि को समायोजित करने के लिए अवधि को कम करने के लिए टैंप को दि.1.1.2011 से उपर्युक्त हानि समायोजित होने तक 350% लेवी के प्रतिशत पर विचार किया जाए, जिस के लिए व्यापारी लोगों ने पहले ही सहमति दी थे और बाद में उचित रूप से लेवी का प्रतिशत पर समीक्षा की जाए ।

8 संयुक्त सुनवाई के बाद विशाखपट्टणम स्टीवडोर्स एसोसियेशन (वि एस ए) ने पत्र सं.दि.10 नवंबर 2010 द्वारा प्रस्ताव पर लिखित निवेदन फाईल किया । वि एस ए द्वारा प्रस्तुत निवेदन टिप्पणी हेतु वि पो ट्रू को अग्रेषित किया गया । वि पो ट्रू ने वि एस ए द्वारा प्रस्तुत निवेदन का उत्तर दिया ।

9.1 वि पो ट्रू के उनके पत्र दि.22 अक्टूबर 2010 एवं 18 नवंबर 2010 द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर जांच करने के बाद दि.14 दिसंबर 2010 को वि पो ट्रू से ई-मेइल द्वारा और सूचना प्राप्त किया गया । हमारे द्वारा उठाये गए सवाल और वि पो ट्रू द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण नीचे की सारणी में दिया गया :

क्र.सं	हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न	वि पो ट्रू द्वारा प्रस्तुत उत्तर
(i)	अनुलग्नक-23 में प्रस्तुत टाईम दर मजदूरी का कंप्यूटेशन दि.13 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा फाईल किया गया संशोधित लागत सारणी के टाईम दर मजदूरी से नहीं मिल रहा है ।	अनुलग्नक-23 में प्रस्तुत टाईम दर मजदूरी का कंप्यूटेशन प्री-रिवार्इजड वेतनमान के आधार पर किया गया जबकि दि.18 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा भेजा गया डॉटा का कंप्यूटेशन संशोधित वेतनमान के आधार पर किया गया । अतः भिन्नता एवं दि.18 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा भेजी गई सूचना को ही मान लिया जाए ।
(ii)	विविध प्राप्तियों की पद्धति - वर्ष 2010-11 के दौरान ₹.180.00 लाख तक अनुमानित टाईम दर मजदूरों की भिन्नता पर स्पष्टीकरण दिया जाए ।	फिलहाल लागू पद्धति के अनुसार टाईम दर मजदूरी नियोजित उस वर्ग के कर्मकार का अधिकतक मजदूरी दर के आधार पर वसूल किया जाता है, लेकिन कर्मकारों को वास्तव के आधार पर भुगतान किया जा रहा है । वसूल किया गया टी आर मजदूरी एवं वास्तविक भुगतान के बीच में यदि कुछ भिन्नता है तो टी आर मजदूरी की भिन्नता शीर्ष के तहत विविध प्राप्तियों के रूप वर्गीकृत किया जाता है ।
(iii)	कर्मकारों को भुगतान शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वर्ष 2008-09 की ₹.967.52 लाख की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान ₹.1975.76 तक असाधारण वृद्धि हुई । वर्ष 2009-10 के दौरान इस व्यय में असाधारण वृद्धि के कारण - जो भविष्य के प्राक्कलन केलिए आधार बन जाता है - विशेषतः उस तथ्य की दृष्टि से स्पष्ट करें कि पोर्ट ने कहीं स्पष्टीकरण दिया कि वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव 26% रहा ।	कर्मकारों को भुगतान शीर्ष के अंतर्गत व्यय में भिन्नता का मुख्य कारण वेतन पुनरीक्षण का अनुपालन पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्थात् दि.1.1.2007 से करने से हुई । वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान कर्मकारों को चुकाया गया रकम क्रमशः ₹.452.35 लाख तथा 517.61 लाख शामिल है और वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन बोर्ड एरियर्स-वर्कर्स शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्थित ₹.966.83 लाख अलग से दिखाया गया । वेतन पुनरीक्षण, कर्मकार, कर्मचारी एवं अधिकारी को चुकाया के प्रावधान के लिए दि.31.3.2010 को अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल या 2109.36 लाख दिखाया गया, जिस में कर्मकारों के लिए व्यवस्थित ₹.1936.79 लाख शामिल है ।

(iv)	<p>स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के बारे में वि. पोट ने अपना ई-मेल दि. 18 नवंबर 2010 को स्पष्ट किया कि शीर्ष “स्वास्थ्य” के अंतर्गत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और परिवार पेंशनर्स को रेशनलाईज़ड चिकित्सा सुविधा विस्तार करना था, जिस में इन हाऊस इलाज करने की वर्तमान पद्धति से हटकर रिफरल मामलों को बाहरी अस्पतालों में भेजना भी शामिल है। यदि ऐसा है तो स्पष्टीकरण दें कि इन हाऊस स्वास्थ्य एवं अस्पताल पर खर्च किए जाने वाले रकम उस सीमा तक समायोजित किया गया क्या?</p>	<p>चिकित्सा सुविधाओं का रेशनलाईज़ेशन के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और परिवार पेंशनर्स को इन-हाऊस इलाज के अलावा बाहर के अस्पतालों में रिफर कर सकते हैं। अतः इस शीर्ष के अंतर्गत वृद्धि हुई।</p>																				
(v)	<p>पोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि पहले वसूल किया गया 189% लेवी से 50% वार्षिक आय और व्यय में घाटा को पूरा करने के लिए सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित किया गया। कृपया दिखायें कि सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित 50% लेवी आय घाटा को कैसे पूरा किया।</p>	<p>हानि को समायोजित करने हेतु एक लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए पूर्व वी डो एल बी छारा पास किया गया मंडल की संकल्प संख्या 17/2007 के आधार पर 50% कह दर पर अतिरिक्त लेवी वसूल किया जा रहा है। तदनुसार संचित हानि को पूरा करने के लिए लेवी आरक्षण निधि में स्थानांतरित किया गया, परिणाम रूप में इसका प्रभाव सामान्य आरक्षण निधि लेखा में पड़ा। विवरण निम्नानुसार है:</p> <p>रूपये लाखों में</p> <table border="1" data-bbox="703 985 1328 1267"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2008-09</th> <th>2009-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क)</td> <td>संचित हानि का आदि शेष</td> <td>228807508</td> <td>225729197</td> </tr> <tr> <td>(ख)</td> <td>चालू वर्ष की हानि</td> <td>82684988</td> <td>417402808</td> </tr> <tr> <td>(ग)</td> <td>घटाईए : अतिरिक्त लेवी से प्राप्तियां</td> <td>85763299</td> <td>89131783</td> </tr> <tr> <td>(घ)</td> <td>संचित हानि का अंत शेष</td> <td>225729197</td> <td>554000222</td> </tr> </tbody> </table>			2008-09	2009-10	(क)	संचित हानि का आदि शेष	228807508	225729197	(ख)	चालू वर्ष की हानि	82684988	417402808	(ग)	घटाईए : अतिरिक्त लेवी से प्राप्तियां	85763299	89131783	(घ)	संचित हानि का अंत शेष	225729197	554000222
		2008-09	2009-10																			
(क)	संचित हानि का आदि शेष	228807508	225729197																			
(ख)	चालू वर्ष की हानि	82684988	417402808																			
(ग)	घटाईए : अतिरिक्त लेवी से प्राप्तियां	85763299	89131783																			
(घ)	संचित हानि का अंत शेष	225729197	554000222																			
(vi)	<p>वर्ष 2009-10 के लिए विशाखपट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (यातायात विभाग) के अंतर्गत काम कर रहे कार्गो संभलाई प्रभाग का लेखापरीक्षा की गई आय एवं व्यय तथा वर्ष 2010-11 के लिए अक्टूबर 2010 तक वास्तव प्रस्तुत करें</p>	<p>वर्ष 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा की गई आय एवं व्यय तथा वर्ष 2010-11 में अक्टूबर 2010 तक वास्तव प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए संशोधित प्राक्कलन अगस्त 2010 तक अर्थात् 5 महीने के आधार पर है और सितंबर 2010 से मार्च 2011 तक प्राक्कलन भी प्रस्तुत किया गया जो 5% व्याज सहित 5 महीने के वास्तव पर वश्वास रखते हुए 7 महीने के लिए प्रोरेटा के आधार पर गणन किया गया।</p>																				
(vii)	<p>स्पष्टीकरण दें कि लेवी से आय का अनुमान कैसे किया गया। इस संबंध में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत करें। पुष्टी करें कि क्या कार्गो संभलाई के लिए नियोजित कर्मकारों को चुकाए जाने वाले वास्तविक समय दर मजदूरी पर लेवी से आय का प्राक्कलन किया गया?</p>	<p>कार्गो संभलाई के लिए नियोजित कर्मकारों से वसूल किया गया वास्तविक समय दर मजदूरी की आय का प्राक्कलन किया गया। वर्ष 2010-11 के लिए अक्टूबर 2010 तक खर्च किया गया वास्तविक समय दर मजदूरी प्राक्कलन किया गया और बाकी 5 महीने के लिए महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि आदि को दृष्टि में रखते हुए 3% की वृद्धि दिखायी गयी। लेवी को मंडल के संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रतिशतों में अर्थात् समय दर मजदूरी के 189% से 350% तक कंप्यूट किया गया। उदाहरण के रूप में टी आर वेज एवं लेवी 300% की दर पर प्रस्तुत किया गया।</p>																				

9.2 पोर्ट ने संशोधित लागत सारणी प्रस्तुत किया, जिस में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक मित्र समय दर मजदूरी का प्राक्कलन किया गया जो पहले पोर्ट द्वारा नहीं माना गया । यि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 से 09-10 तक कार्गो संभलाई प्रभाग की अंतिम संशोधित लागत सारणी का सारांश और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक प्राक्कलन नीचे दिया गया है :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	वास्तव		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	लेवी %			250% & 300%	300%	300%	300%
(i)	कुल आय	4424.26	3089.69	8624.30	8086.82	8684.42	9356.06
(ii)	व्यय (आर औ सी ई के अलावा)	5251.11	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii)	पूँजी नियोजन	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv)	आर औ सी ई :	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया	13.86	9.04	4.51	0.02
(v)	कुल व्यय + आर औ सी ई (ii+iv)	5251.11	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi)	आय से अधिक व्यय (-) एवं व्यय से अधिक आय (+) (i-v)	(826.85)	(4174.03)	798.60	589.17	747.61	861.58
(vii)	पूर्व अवधि की हानी को समायोजित करने बाद घाटा / अधिशेष	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4152.14)	(3404.53)	(2542.95)

10. तत्पश्चात यि पो ट्र ने दि.28 दिसंबर 2010, 30 दिसंबर 2010, 4 जनवरी 2011 तथा 7 जनवरी 2011 को आगे की सूचना / स्पष्टीकरण भेजा जो नीचे दिया गया है :

- (i) वर्ष 2010-11 के लिए वास्तव के आधार पर अक्तूबर 2010 तक समय दर मजदूरी का प्राक्कलन का कार्यचालन तथा लेवी प्रस्तुत किया ।
- (ii) वर्ष 2011-11 के दौरान रु.87 लाख के लिए प्राक्कलित पिछले वर्ष से संबंधित मुद्रों का ब्रेकअप प्रस्तुत किया । यि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत करने का ब्रेकअप के अनुसार वेतन पुनरीक्षण बकायों से संबंधित रु.52 लाख पिछले वर्ष से संबंधित है ।
- (iii) पोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि वर्ष 2009-10 के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ग्रूप लेवी एनकैशमेंट योजना के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रूप लेवी एनकैशमेंट योजना में रु.4.47 करोड़ प्रभार्य किया गया ।
- (iv) (क) पोर्ट ने वर्ष 2009-10 के दौरान पेंशन निधि में रु.15.19 करोड़ अंशदान का ब्रेकअप भी प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :

अधिकारी, कर्मचारी, कर्मकार एवं पेंशनरों के लिए पेंशन निधि में अंशदान	85287000
पेंशनरों के लिए वेजबोर्ड प्रावधान	66700000
कुल	151987600

(ख) पोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि पेंशन अंशदान में वृद्धि का कारण संशोधित वेतनमान, डी ए में आवधिक वृद्धि आदि के परिणाम रूप में संशोधित वास्तविक मूल्यांकन से है । संशोधित

पेंशन बकाया केवल जनवरी 2010 में प्राप्त होने के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान पेंशनरों को वेतन पुनरीक्षण के आऊटकम के आधार पर पेंशन बकाया भुगतान करने के लिए प्रावधान किया गया ।

- (ग) पेंशन निधि में अंशदान - वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मकारों को मिलने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 27% तक किया गया । वर्ष 2009-10 के लिए पेंशन में 27% अंशदान करते समय कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते प्रति कर्मचारी को एक लाख रुपये तक सीमित किया गया । अतः कम प्रावधान किया गया । वर्ष 2010-11 के दौरान सी एच डी के कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 27% अंशदान किया गया, ऐसे करने के बाद कुल रकम रु.1,00,000/ से ज्यादा होता तो तब इसे प्रति कर्मचारी को एक लाख रुपये तक सीमित किया गया ।
- (घ) एकचूरियल एल आई सी द्वारा किया गया एकचूरियल मूल्यांकन के अनुसार दि. १ अप्रैल 2010 को अनुमानित पेंशन निधि रु.320 करोड़ था । पोर्ट ने एकचूरियल मूल्यांकन को एकचूरियल रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रमाणित किया । पोर्ट ने बताया कि दि. १ अप्रैल 2010 को पेंशन निधि का शेष रु.158.20 करोड़ था, अतः पेंशन निधि में कमी रु.162 करोड़ रहा ।

11. इस मामले के परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है । संबंधित पार्टियों द्वारा प्राप्त टिप्पणी और की गई चर्चा के उद्घरण संबंधित पार्टियों को अलग से भेजा जाएगा । ये विवरण हमारे वेबसाईट <http://tariffauthority.gov.in> में भी उपलब्ध किया जाएगा ।

12. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नांकित स्थिति उभरती है :-

- (i) भूतपूर्व विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड (वीडीएलबी) का 26 सितम्बर 2008 से विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में विलय हो गया है । विलय से पहले, वीडीएलबी से श्रमिकों को तैनात करने के लिए लेवी का निर्णय डॉक लेबर बोर्ड द्वारा किया जाता था । वीडीएलबी के साथ वीपीटी के विलय के साथ वीपीटी के अन्तर्गत कार्गो प्रहस्तन संभाग / कार्गो हैंडलिंग डिविजन (सीएचडी) नामक एक अलग संभाग कार्गो प्रहस्तन प्रयोजनों के लिए श्रामिकों की नियुक्ति के कार्य की देखरेख करता है और इसलिए, इसके लिए लगाए जाने वाले प्रभार इस प्राधिकरण के नियामक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ।
- (ii) वीपीटी और वीडीएलबी के बीच निष्पादत समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पत्तन ने, विलयोत्तर परिदृश्य में, तात्कालिक प्रचलित लेवी का 189%, 31 मार्च 2010 तक जारी रखा । पत्तन का तात्कालिक प्रस्ताव, समय दर मजदूरी की (तात्कालिक रुप से) प्रचलित लेवी 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक तीन माह के लिए 189% से 250% और 1 जुलाई 2010 तथा उसके बाद 350% बढ़ाने के लिए है ।

पत्तन ने औचित्य बताते हुए कहा है कि तात्कालिक 189% की लेवी, जो विलय से पहले एकत्रित की जाती थी, प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है । लेवी में प्रस्तावित वृद्धि का एकमात्र उद्देश्य / लक्ष्य सीएचडी के प्रशासनिक एवं कल्याण संबंधी खर्चों की पूर्ति करना, पाँच वर्ष की अवधि में बीते समय की रु. 55.40 करोड़ की हानि की भरपाई / वसूली करना और पेंशन निधि देनदारियों में कमी को पूरा करना है । पत्तन ने जोर देकर कहा है कि लेवी में प्रस्तावित का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । व्यापार जगत से हुई चर्चा और उनकी सहमति के आधार पर पत्तन ने लेवी में प्रस्तावित वृद्धि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दी है । यद्यपि पत्तन का प्रस्ताव था कि लेवी को टाइम रेट वेजेज का 350% बढ़ा दिया जाए किन्तु व्यापार-जगत के अनुरोध पर यह इस समय टाइम रेट वेजेज के 300% पर वसूल किया जा रहा है जैसा पत्तन द्वारा सूचित किया गया है । कुछ उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है ।

(iii) प्रशुल्क मार्गदर्शियों की द्वारा 4.7.2, स्टीवेडरिंग गतिविधि के लिए, जब स्टीवेडरिंग प्रचालन पत्तन द्वारा एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाए, प्रति टन आधार पर लेवी प्रदान करने की सिफारिश करती है। जहाँ केवल ऑन - बोर्ड श्रमिक प्रदान किए जाते हैं वहाँ मार्गदर्शी वास्तविक मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी की अनुमति प्रदान करते हैं। वीपीटी में पत्तन की भूमिका श्रमिकों की आपूर्ति करने तक सीमित है। वीपीटी ने बताया है कि पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं.एल.बी.-13018/4/05-L-II, दिनांक 24 जून 2009 के माध्यम से एक नई स्टीवेडोरिंग नीति तैयार की है जिसमें उसने सभी पत्तन न्यासों को निर्देश दिया है कि वे स्टीवेडोरिंग की गणना, श्रमिकों की मजदूरी की गणना प्रतिशतता की बजाय टनेज आधार पर की जाए। सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने के जब कारण मांगे गए तो वीपीटी ने स्पष्ट किया कि जब पत्तन ने प्रतिटन दर प्रदान किए जाने का आग्रह किया तो व्यापार-जगत और स्टीवेडोरिंग ने सीएचडी प्रतिटन मजदूरों के लिए प्रति टन लेवी पर आपति व्यक्त की है और अनुरोध किया है कि प्रतिशतता आधार पर लेवी की वसूली की प्रचलित प्रणाली कुछ और समय जारी रखी जाए। वीपीटी के न्यासी मंडल ने अपने पिछले रुख पर पुनर्विचार किया और प्रतिशतता आधारित लेवी जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया। यह नोट करने योग्य है कि 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी वास्तविक मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी प्रदान किए जाने की ही अनुमति देते हैं, जहाँ सेवा केवल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए हो। वर्तमान मामले में भी स्थिति यही है। इसको देखते हुए, और वास्तविक मजदूरी की प्रतिशतता पर लेवी की प्रचलित विधि को जारी रखने के वीपीटी के प्रस्ताव को मान्य करना व्यापार-जगत द्वारा किए गए अनुरोध से आता है जिसकी 18 मार्च 2010 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति से पुष्टि होती है। इस बैठक में विशाखापत्तनम् स्टीवेडर्स एसोसिएशन (वीएसए) समेत प्रासांगिक व्यापारिक सदस्यों ने भाग लिया था। टाइमरेट वेजेज / समय दर मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी के लिए वीपीटी का प्रस्ताव वर्तमान चक्र के लिए स्वीकार किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्रमिकों की उत्पादकता से जुड़ी प्रतिटन दर बेहतर निष्पादनता प्राप्त करने हेतु स्टीवेडर्स के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी और कथित प्रक्रिया (ट्रॉफिकोण) एक ही श्रमिक समूह / दल के अनेक हिसाब-किताबों (तोखा) की संभावना को अग्रिम रूप से समाप्त कर देगा। इस नजरिए से देखने पर और, स्टीवेडरिंग गतिविधि के लिए प्रतिटन लेवी प्रदान करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय से प्राप्त विशिष्ट निर्देश को देखते हुए पत्तन को अगली समीक्षा / सीएचडी गतिविधि के संशोधन के समय टन / टनभार आधारित लेवी तैयार करने की सलाह दी जाती है।

(iv) यद्यपि वीडीएलबी का वीपीटी के साथ विलय हो गया है, समझौता ज्ञापन के अनुसार सीएचडी के लिए खाते (लेखा) अलग ही बनाए रखे गए। विलय स पहले अर्थात् 25 सितंबर 2008 तक) वर्ष 2008-09 के वास्तविकों के आधार पर सीएचडी गतिविधि के लिए वीपीटी ने लागत विवरणी प्रस्तुत कर दी है। इसने विलय के बाद की अर्थात् 26 सितंबर 2008 से और वर्ष 2009-10 की वास्तविक लागत स्थिति और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए अनुमानित स्थिति प्रस्तुत कर दी है। हमारे अनुरोध पर, पत्तन ने बाद में वर्ष 2010-11 के लिए अक्टूबर 2010 तक सीएचडी गतिविधि के लिए वास्तविक प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण की तैयारी के दौरान प्रस्तुत सूचना / स्पष्टीकरण के साथ वीपीटी द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत फाइनल संशोधित लाभत विवरणी में दाखिल किए गए अनुमानों पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

(v) सीएचडी गतिविधि में 31 मार्च 2010 तक कुल जमा हानि (घाटा) रु. 55.40 करोड़ बताया गया है। पत्तन का प्रस्ताव है कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सीएचडी गतिविधि पर होने वाले कुल खर्च तथा उस पर प्रतिलाभ की वसूली की जाए और 31 मार्च 2010 तक विगत अवधि के लिए आकलित रु. 55.40 करोड़ की कुल जमा हानि में से पिछली अवधि की कुल हानि रु. 29.97 करोड़ की भरपाई कर ले। विगत अवधि की रु. 25.43 करोड़ की शेष हानि (घाटा) को अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित करने का प्रस्ताव है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वीएसए समेत उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों ने, सीएचडी गतिविधि में विगत हानियों की भरपाई (समायोजन) के लिए वीपीटी के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से कोई बिन्दुवार आपत्ति व्यक्त नहीं की है। केवल एक सुझाव दिया है कि सामान्य लेवी के साथ जोड़ने की बजाए, विगत अवधि हानि को पूरा करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए एक अलग विशेष लेवी प्रदान कर दी जाए। किन्तु, बीएसए की मांग थी कि ऐसी विशेष लेवी सीधे-सीधे आयातकों / निर्यातकों से वसूल की जानी चाहिए। जैसाकि यह लेवी उन स्टीवेडरों से वसूल की जाती है जो कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की सेवाएं स्टीवेडोरिंग प्राप्त करते हैं, यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस प्रशुल्क बोझ को किसी अन्य उपयोगकर्ता समूह पर डालने का कोई औचित्य भी नजर नहीं आता है।

वीपीटी द्वारा एक समेकित लेवी प्रस्तावित के लिए जो विगत घाटों (हानियों) की पूर्ति के लिए निधि उपलब्ध करवाएगा, अपनाया गया दृष्टिकोण (तरीका) अधिक सारगमित नजर नहीं आता है क्योंकि इसमें न केवल पिछली हानि आगामी वर्षों में भी जाएगी, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित नहीं होता है कि इस विनिर्दिष्ट वसूली से पिछली हानियां समायोजित हो भी, पाएंगी या नहीं। ऐसी स्थिति में, टाइम-रेट-वेज की एक प्रतिशतता के रूप में एक अलग लेवी, विगत अवधि हानि को पूरा करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए परिणामित की गई है। इस प्रकार, जैसा कि कुछ उपयोगकर्ता एसोसिएशनों द्वारा समझा गया है, विगत अवधि हानि का बुनियादी लेवी के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा और साथ ही, इससे पत्तन वित्तीय रूप से किसी हानिप्रद / नुकसान दायक स्थिति में भी नहीं पड़ेगा।

- (vi) सीएचडी से तैनात किए गए श्रमिकों को देय टाइम-रेट-वेजेज और पीस-रेट-वेजेज स्टीवेडरों से वसूल किए जाते हैं। इसीलिए, श्रमिकों को देय टाइम-रेट-वेजेज और पीस-रेट-वेजेज का अनुमान वीपीटी द्वारा आय की ओर के साथ-साथ व्यय की ओर ठीक ही दर्शाया गया है। लेवी टाइम-रेट-वेजेज पर ही वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित है। वीपीटी द्वारा अनुमानित टाइम-रेट-वेजेज और हमारे विश्लेषण में किए गए परिवर्तन की इसके नीचे व्याख्या की गई है:-
- (क) पत्तन ने पुष्टि की है कि गोदी श्रमिकों के बारे में मजदूरी-संशोधन के प्रभाव पर वर्ष 2010-11 के टाइम-रेट-वेजेज के अनुमान में विचार किया गया है। टाइम-रेट-वेजेज सीएचएलडी से श्रमिकों की तैनाती पर निर्भर करेगा। पत्तन ने अक्टूबर 2010 तक वास्तविक टाइम-रेट-वेज प्रस्तुत किया है। वर्ष 2010-11 के अनुमान के प्रयोजन से, वीपीटी द्वारा अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिए सूचित किए गए वास्तविक टाइम रेट वेज के साथ शेष पाँच महिनों के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत यथानुपात अनुमान पर विचार किया गया है। अनुमानों में डिफरेंशियल टाइम रेट वेजेज भी जोड़े गए हैं जिसके कारण परवर्ती पैराग्राफों में बताए गए हैं।
- (ख) वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित टाइम-रेट-वेजेज की गणना वीपीटी द्वारा, पिछले वर्ष के समान ऑकड़ों में 1.4% की वृद्धि करके की गई है। वीपीटी इसका कोई तार्किक कारण नहीं दे सका कि उसने टाइम-रेट-वेजेज में वृद्धि को 1.4% तक ही सीमित क्यों रखा है। जबकि, इसके द्वारा प्रस्तुत सामान्य संशोधन में, वर्ष 2011-12 के दौरान समूचे यातायात में 7.5% की वृद्धि दिखाई गई है और इस वर्ष में विशेषकर कोयला के यातायात में 22.6% की वृद्धि प्रोजेक्ट की गई है। इसके अलावा, बाद के दो वर्षों 2012-13 और 2013-14 के लिए टाइम-रेट-वेजेज में ग्रामशः 9.4% और 10.4% की वृद्धि अनुमानित की गई है।

वीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 में श्रमिकों की औसत तैनाती श्रमिकों की अधिकतर श्रेणियों के लिए एक माह में 14 से 16 दिन और मजदूरों, शिखनलग्नमैन और प्रिसित्रीयों के लिए एक माह में 19 से 20 दिन है। दिनांक 22 अक्टूबर 2011-12 से 2012-13 के दिन

प्रस्तुत टाइम-रेट-वेजेज की गणना की जाँच पड़ताल करने पर यह देखा गया है कि सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाली कार्गो मात्रा में वृद्धि के कारण सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती में वृद्धि को पत्तन ने परिगणित नहीं किया है। सीएचडी सेवाएं प्राप्त करने वाला अपेक्षित कार्गो यातायात और मजदूरी लागत में वार्षिक वृद्धि, ऐसे दो अवयव हैं जो टाइम-रेट-वेजेज का अनुमान लगाने के लिए प्रासंगिक हैं।

पत्तन ने, उससे अनुरोध किए जाने के बावजूद, वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने / उपयोग करने वाले कार्गो की मात्रा नहीं प्रस्तुत की है। वर्ष 2010-11 में अगस्त 2010 तक सीएचडी की सेवा प्राप्त कर चुकी वारस्तविक कार्गो कथित रूप से मात्रा के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए सीएचडी का कुल यातायात 161.65 लाख टन होगा। दरमान के सामान्य संशोधन के लिए वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव में, जिस पर अलग से कार्वाई की जा रही है, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए समूचे यातायात में अनुमानतः क्रमशः 7.5% और 11.5% की वृद्धि होने वाली है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए सीएचडी से संबंधित वीपीटी द्वारा प्रदत्त किसी यातायात विवरण के अभाव में, किन्तु उसी समय सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाली मात्रा को मान्य करते हुए, इस विश्लेषण के प्रयोजन से यह आवश्यक तो नहीं की सीएचडी की सेवाएं लेने वाले यातायात की मात्रा में पत्तन के यातायात में समूची बढ़वार के स्तर पर वृद्धि हो। सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाले कार्गों / यातायात की मात्रा में टाइम रेट वेज का अनुमान लगाने के प्रयोजन से 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि मानी गई है। सात महिनों के वारस्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित टाइम रेट वेज आधार माना गया है, यातायात में 5% प्रति वर्ष की वृद्धि मानी गई है। सात महिनों के वारस्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित टाइम रेट वेज आधार माना गया है, यातायात में 5% बढ़वार के लिए उसमें समायोजन किया गया है और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए टाइम-रेट-वेज का अनुमान लगाने के लिए 3.76% वार्षिक वृद्धि लगायी गई है। आय की ओर विचार किया गया टाइम-रेट-वेज अनुमान व्यय की ओर भी दर्शाया गया है।

(ग)

वीपीटी ने सूचित किया है कि श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए टाइम-रेट-वेज उच्चतम मजदूरी स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं। श्रमिकों (कर्मचारियों) को वारस्तविक भुगतान प्रत्येक कर्मचारी की हकदारी के अनुसार देय मजदूरी के संदर्भ से किया जाता है। स्टीवेडरों से वास्तव में लिए गए टाइम-रेट-वेज और (श्रमिकों को) वास्तव में भुगतान किए गए टाइम रेट वेज के बीच अंतर को, "टाइम-रेट-वेज का अंतर", शीर्ष के अन्तर्गत विविध प्राप्तियों के रूप में लेखा में डाला जाता है।

आदर्श रूप में, टाइम-रेट-वेज, तैनात किए गए कर्मचारियों को देय वारस्तविक मजदूरी (के आधार) पर लिया जाना चाहिए। किन्तु इस बात को स्वीकार करते हुए कि कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उच्चतम टाइमरेट वेज वशूल करने की प्रथा पहले से ही प्रचलित है और बिलिंग मुद्दों के लिए, इस प्रशुल्क घक्र में उसी को अनुमत किया गया है। इस प्रथा की सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल करने पर पता चलेगा कि अपनायी गई बिलिंग विधि से, स्टीवेडरों की कीमत पर पत्तन को कोई अनपेक्षित लाभ होने वाला नहीं है। प्राप्त किए गए टाइम-रेट-वेज और वास्तव में भुगतान किए गए के

बीच का अंतर आय के रुप में गिना गया है जो लेवी से पूरा किए जाने वाले अन्कवर्ड घाटे को कम करता है।

हमारे द्वारा तैयार की गई लागत विवरणी में लेवी के निर्धारण के प्रयोजन से वीपीटी द्वारा अलग से दिखाये गये टाइम-रेट-वेज का अंतर टाइम रेट वेजज वसूली से राजस्व के अनुमान के साथ मिला दिया गया है ताकि कुल टाइम रेट वेजज का पता चल सके जिस पर लेवी प्राप्त की जाती है।

- (घ) वीपीटी द्वारा अनुमानित टाइम-रेट वेजज में अंतर की मद में राजस्व रु. 180 लाख है। अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिए टाइम रेट वेज में अंतर की मद में वास्तविक प्राप्तियां रु. 131.08 लाख बताई गई हैं। वर्ष 2010-11 के बाकी पांच महिनों के लिए टाइम-रेट-वेजज में अंतर का अनुमान वर्ष 2010-11 के लिए टाइम-रेट-वेज अनुमानित करने हेतु अपनाए दृष्टिकोण के अनुरूप पत्तन द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर यथानुपात लिया गया है। तदनुसार, टाइम-रेट-वेजज अनुमानित करने के लिए अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 2010-11 के लिए इस मद के लिए अनुमान रु. 206.09 लाख लिया गया है।

मूल प्रस्ताव में, पत्तन ने बाद के वर्षों 2011-12 से 2013-14 के लिए टाइम-रेट-वेज में अंतर से राजस्व का अनुमान नहीं किया है। इसने, बाद में, दिनांक 28 दिसंबर 2010 के पत्र के माध्यम से 2011-12 से 2013-14 तक के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत आय का अनुमान क्रमशः रु. 80 लाख, रु. 60 लाख और रु. 40 लाख लगाया है।

इन वर्षों के दौरान टाइम-रेट-वेज में अंतर से राजस्व में तेजी से गिरावट का वीपीटी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। इस शीर्ष के अन्तर्गत कमी / गिरावट, यदि कोई हो तो, वह सभी कर्मचारियों द्वारा वास्तव में अर्जित मजदूरी / वेतन में एक वार्षिक वृद्धि की मद में हो सकती है। आय की इस मद का अनुमान लगाने के लिए पत्तन द्वारा दी गई किसी विस्तृत गणना के अभाव में, विश्लेषण के प्रयोजन से टाइम-रेट-वेजज में अंतर का औसत, जैसा सूचित किया गया है, वर्ष 2008-09 के लिए रु. 326.35 लाख, वर्ष 2009-10 में रु. 79.50 लाख और वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानतः रु. 206.09 लाख है जिसे आधार माना गया है और परिकलिप्त 5% यातायात वृद्धि के लिए समायोजित किया गया है। यह मान्य करते हुए कि यह अनुमान कर्मचारियों को देय एक वृद्धि की सीमा तक, जो 3% है, यह मान्य करते हुए कि यह अनुमान कर्मचारियों को देय एक वृद्धि की सीमा तक, जो 3% है, कम हो जाएगा, 3.76 की मजदूरी लागत में वार्षिक वृद्धि / मजदूरी लागत में 3.76% की वार्षिक वृद्धि है जो अन्यथा लगायी जानी है, लागू नहीं की गई है। उपरोक्त परिवर्तन के अधीन, टाइम रेट वेजज में अंतर से राजस्व का अनुमान वर्ष 2011-12 में रु. 214.13 लाख, वर्ष 2012-13 में रु. 224.89 लाख और वर्ष 2013-14 में रु. 236.13 लाख किया गया है।

- (ड.) लागत विवरणी में विचार किए गए टाइम रेट वेजज में अंतर से राजस्व रु. 1836.99 लाख, रु. 1976.40 लाख रु. 2144.80 लाख और 2327.83 लाख है।

- (vii) वीपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी, टाइम-रेट-वेजज के अलावा आय और व्यय की विभिन्न मदें भी दर्शाती हैं। विचार की गई परिवर्तित लागत विवरणी में आय और व्ययों की प्रकृति के आधार

पर आय और व्यय की विभिन्न चर्चा की जाकृत किया गया है। वीपीटी द्वारा अनुमानित आय और व्यय की अन्य मर्दों से संबंधित विश्लेषण और अनुमानों में किए गए परिवर्तनों पर इसके नीचे रांकेप में चर्चा की गयी है।

(क) वीपीटी ने इस बात की जुड़ी की है कि उसने कार्मिक मापकों पर राष्ट्रीय पंचाट का निर्णय (नेशनल ड्रिल्यूएल अमार्ट) कियान्वित कर दिया है और तदनुसार, कार्गो प्रहस्तन की विभिन्न गणितिहियों के लिए कार्मिक मापक संसोधित किए जा चुके हैं। पत्तन ने इस बात की जुड़ी की है कि वर्तमान प्रोत्साहन योजना को 1 मई 2010 से अंतिम रूप दिया गया था और अनुमानों में वर्तमान प्रोत्साहन योजना की गणिती होती है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्यक्ष अनुमान 2010 तक सूचित किए गए वार्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया गया और इसलिए वीपीटी के अनुमान स्थीकार किए जाते हैं। 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए ईस-रेट पैरेंट के क्रमशः 2.7%, 0.4% और 0.5% गिरने का अनुमान है।

स्टीवेडरों से प्राप्त राशि और वर्तविकियों को भुगतान की वाई राशि को प्रदर्शित करते हुए ईस रेट वैजेज आव के 3.7% साथ व्यय के स्तर पर समान रूप से दिखाए गए हैं।

(ख) वीपीटी ने 2010-11 से 2013-14 तक अनुमानों में सहकारी सोसायटियों को ऋण पर व्याज रो आय, निवेश पर फसल और प्रशासनिक तथा इसर कर्मचारियों को अग्रिम पर व्याज पर आय की ओर विचार किया है। वीपीटी ने, व्यय के खाते में (की ओर) वर्ष 2010-11 के अनुमानों में भीतर निवित न्यास पर देय व्याज पर विचार किया है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुपालित जाभाना नजरिए के अनुरूप, आय पक्ष और व्यय पक्ष दोनों ओर से व्याज अवयव, लगभग छिद्रणी रो बाहर रखा जाता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) पत्तन ने बाताया है कि 3.76% की वार्षिक वृद्धि, प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार अनुग्रह, तात्कालिक मामलों में लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रशुल्क लागत अवयव / घटक श्रमिक अवयव से संबंधित है। पत्तन ने 5% से 10% वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए जायें जब अनुमान लगाया है। वर्ष 2009-10 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अपाराय गया वार्षिक वृद्धि अवयव 3.76% है। 3.76% की वार्षिक वृद्धि वर्ष 2010-11 के निर्धारित अन्य प्रशुल्क संशोधन प्रकरणों, यथा, मुर्गाव पत्तन न्यास साऊथ-वैरेट पराम लिमिटेड इत्यादि पर समान रूप से लागू किया गया है। प्रशुल्क मार्गदर्शी कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी से संबंधित प्रगार निर्धारित करने में किसी विभेदीय / गेदभावमूलक व्यवहार नहीं करते। इसलिए व्यय के अनुमान में वार्षिक वृद्धि जहाँ कहीं इसे अविका पाया गया है, नीचे दिए विश्लेषण की शर्त पर 3.76 % पर सीमित रखी गई है।

(घ) पत्तन ने कर्मचारियों को वीआरएस भुगतान पर एक लागत के रूप में विचार किया है और इस व्यय को पांच वर्षों में किश्त बद्ध किया है। वेतन / मजदूरी तथा पेंशन के बकाया, वीआरएस प्रतिपूर्ति इत्यादि जैसे एक समय के व्यय प्रशुल्क निर्धारित करते

समय स्वीकार्य लागत के रूप में अनुप्रत नहीं है। इसलिए, वीआरएस भुगतान पर वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों की लागत-विवरणियों में विचार नहीं किया गया है।

- (ड) टाइम-रेट-वेजेज उन कर्मचारियों को किया गया भुगतान दर्शाता है जो कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए लगाए गए हैं। टाइम रेट वेजेज के अलावा कर्मचारियों को देय वह मजदूरी जो उस अवधि के लिए दी जाती है जब उन्हें तैनात नहीं किया जाता है, वीपीटी द्वारा लागत विवरणी में व्यय के रूप में अलग से प्रदर्शित की गई है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 में किए गए भुगतान का अनुमान, मजदूरी / वेतन संशोधन के प्रभाव पर विचार करने के बाद ही है। इसने यह भी पुष्टि की है कि इस शीर्ष के अधीन वर्ष 2010-11 के लिए अनुमान में विगत से संबंधित कोई बकाया शामिल नहीं है।

वर्ष 2010-11 में वीपीटी ने कर्मचारियों को अनुमानित भुगतान रु. 1989.46 लाख आंका है। कर्मचारियों (श्रमिकों) एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को भुगतान पर व्यय सामान्य तथा एक निर्धारित ढांचे का अनुपालन करेगा। जब वीपीटी द्वारा अक्टूबर 2010 तक के प्रस्तुत वास्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है तो वीपीटी द्वारा प्रस्तुत अनुमान अधिक ऊंचे पाए गए हैं। अक्टूबर 2010 तक के प्रस्तुत वास्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के अनुमानों को परिवर्तित किया गया है। वर्ष 2010-11 में अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को भुगतान का अनुमान, जब इसकी तुलना अक्टूबर 2010 तक के वास्तविकों के विस्तारित आंकड़ों से की गई तो, तर्क संगत पाया गया और इस लिए स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रशा. कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 5% वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। वीपीटी ने बताया है कि सीएचडी के अन्तर्गत कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 2010-11 में 1165 से, वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक गिरकर क्रमशः 1015, 981 और 974 रह जाने की उम्मीद है। कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को, वीपीटी द्वारा अनुमानित भुगतान में ऐसा लगता है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों / प्रशा. कर्मचारियों की गिरती संख्या, विशेषकर वर्ष 2012-13 और 2013-14 में, पर भी ध्यान दिया गया है।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों / प्रशा. कर्मचारियों को भुगतान के अनुमानों को वर्ष 2010-11 के लिए विचारित कर्मचारियों / प्रशा. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को औसत भुगतान पर विचार करते हुए वीपीटी द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों / प्रशा. कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या-शक्ति पर यह मानते हुए कि औसतन सेवा निवृति भिन्न-भिन्न वर्षों के माध्यम में होगी और 3.76% की वार्षिक वृद्धि लागू करते हुए परिवर्तित किया गया है।

- (च) वीएसए ने तर्क दिया है कि लेवी का प्रावधान कर्मचारियों को देय प्रत्यक्ष खर्चों की वसूली के ही लिये होना चाहिए और परोक्ष व्यय जैसे वे क्वार्टर्स जो अब श्रमिकों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते, रकूल इत्यादि वीपीटी के समूचे उपरिव्यय में शामिल किए जाने चाहिए और पोत घाट शुल्क के जरिए वसूल किए जाने चाहिए। पत्तन ने स्पष्ट

किया है कि प्रशासन एवं अन्य खर्चे सीएचडी गतिविधि से संबंधित हैं और क्वार्टर इत्यादि जैसी सुविधाएं सीएचडी श्रमिकों द्वारा और प्रशा. कर्मचारियों द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही हैं और इसलिए सीएचडी से संबंधित व्यय लेवी के एक भाग के रूप में ही वसूल किया जाना है। वीएसए का सुझाव कि सीएचडी के उपरिव्यय की वसूली पत्तन के दरमान के सामान्य संशोधन के जरिए की जानी चाहिए, अन्य कार्गों को तट के उस बोझ में हाथ बंटाने के लिए साथ जोड़ देगा जो सेवाएं उसने हासिल ही नहीं की हैं। इसके परिणाम स्वरूप सीएचडी गतिविधि की अन्य गतिविधि द्वारा वित्तीय सहायता देना हो जाएगा। इसलिए, वीएसए द्वारा उठाए गए बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता।

- (छ) कार्यालय अनुरक्षण, मरम्मत और अनुरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की मद में वर्ष 2010-11 के लिए वीपीटी द्वारा खर्चों के अनुमान को, अक्तूबर 2010 तक प्रस्तुत किए वास्तविकों के आधार पर आंकड़ों को फैलाकर परिवर्तित / परिष्कृत किया गया है जैसा कर्मचारियों एवं प्रशा. कर्मचारियों को भुगतान के अनुमान के लिए किया गया था।
- (ज) वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए वीपीटी ने अधिकतर मदों का अनुमान लगाते हुए 5% वृद्धि अवयव पर विचार किया है और स्वास्थ्य संबंधी खर्च का अनुमान करते समय 10% वार्षिक वृद्धि अवयव पर विचार किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अनुमानों में, अन्य व्यय अनुमानित करने के लिए अपनाए गए सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप वार्षिक वृद्धि विभिन्न गत वर्षों के अनुमानों पर 3.76% वार्षिक तक सीमित रखी गई है।
- (झ) वर्ष 2009-10 के लिए सूचित वास्तविकों में सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजना (ग्रुप लीव ऐन्केशमेंट स्कीम) की मद में रु. 4.74 करोड़ भी शामिल हैं। पत्तन ने यसपर किया है कि अनुमान वर्ष 2009-10 के लिए भा.जी.बी. निगम द्वारा प्रदत्त सामु.द्यु.न.यो. के बीमांककीय मूल्यांकन पर आधारित है। वर्ष 2010-11 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत रु. 1.33 करोड़ अनुमानित है। जब वीपीटी द्वारा शीर्ष के अंतर्गत अक्तूबर 2010 तक प्रस्तुत वास्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है तो वर्ष 2010-11 के लिए अनुमान मेल खाता हुआ पाया गया है और इस लिए, इस मद के लिए वीपीटी द्वारा प्रस्तुत अनुमान को स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के अनुमानों में सामु.द्यु.न.क.योजना का कोई अनुमान शामिल नहीं है।
- (झ) पेंशन निधि, उपादान-निधि, भविष्य निधि, गृ.निर्मा.अग्रिम निधि इत्यादि की मद में अंशदान, पिछले वर्ष 2008-09 में रु. 565.37 लाख की तुलना में वर्ष 2009-10 में रु. 2124 लाख सूचित किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान पेंशन निधि उपादान निधि इत्यादि में अंशदान में वृद्धि, वर्ष 2008-09 के लिए सूचित किए गए वार्तविक अंशदान की तुलना में लगभग चार गुना पाया गया है। उपरोक्त निधि की मद में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अंशदान क्रमशः रु. 1940 लाख और रु. 1958 लाख अनुमानित किया गया है। बाद के दो वर्षों के लिए पत्तन ने भिन्न-भिन्न पिछले वर्षों के अनुमानों पर क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि का अनुमान किया है।

वर्ष 2008-09 के वास्तविकों से इस मद में एकाएक वृद्धि का कारण मांगने पर पत्तन ने स्पष्ट किया है कि अंशदान में वृद्धि मुख्य रूप से, संशोधित वेतनमान, मंह.भत्ते में सावधिक वृद्धि इत्यादि के परिणामरखरू प संशोधित बीमांककीय मूल्यांकन के कारण है। वर्ष 2009-10 में पेशन निधि में रु. 1519 लाख के कथित अंशदान में से, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि रु. 852.87 लाख पेशन निधि को किया गया वास्तविक अंशदान है और रु. 667 लाख पेशन निधि के लिए अंशदान की मद में किया गया प्रावधान है जो जनवरी 2010 में घोषित किए गए वेतन-संशोधन पर आधारित है। उपादान निधि को अंशदान वर्ष 2009-10 में कथित रूप से रु. 595.58 लाख सूचित किया गया है यह सीएचडी कर्मचारियों के मूल वेतन और मंह.भत्ते के योग का 8.33% किया गया है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2010-11 के दौरान पेशन निधि को किया गया अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन और मंह.भत्ते का 27% है और यदि अंशदान एक लाख रुपये प्रति कर्मचारी से अधिक है तो अंशदान को प्रति कर्मचारी एक लाख रुपया सीमित किया गया है। वर्ष 2009-10 में पेशन-निधि में अंशदान 27% पर किया गया था जिसके लिए मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये पर सीमित किया गया था। पेशन निधि और उपादान निधि को अंशदान कथित रूप से समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप बीमांककीय मूल्यांकन के अनुसार है।

यद्यपि अपने अनुमानों का औचित्य बताने के लिए पत्तन ने प्रयास किया है, तो भी इस मद में एकाएक इतनी वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट रिथति नहीं उभरती। भारत 1 जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल 2010 तक पेशन निधि देनदारी अनुमान, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार रु. 320 करोड़ आंका गया है। पेशन निधि जमा शेष 01.04.2010 को रु. 158.20 करोड़ बताया है और 1 अप्रैल 2010 को पेशन निधि में रु. 162 करोड़ की कमी अनुमानित की गई है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि पेशन निधि, उपादान निधि आदि की मद में अंशदान के अनुमान में कोई बकाया राशि शामिल नहीं है। विशेष अनुरोध किए जाने के बाद भी पत्तन ने दिनांक 28 दिसंबर 2010 के द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के संदर्भ से वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए विभिन्न निधियों को अनुमानित अंशदान की गणना / गणना-विवरण नहीं दिया है।

फिर भी, पत्तन द्वारा प्रस्तुत रिथति से यह उभरता है कि पेशन निधि देनदारी में बहुत ज्यादा कमी है जो 1 अप्रैल 2010 को लगभग रु. 162.00 करोड़ थी। अतएव, पेशन निधि, उपादान निधि, भविष्य निधि आदि में अंशदान जैसा वर्ष 2009-10 में बताया गया है और बीपीटी द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित किया गया है, बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। बाद के वर्षों के लिए विभिन्न निधियों को कुल अंशदान 3.76% की वार्षिक वृद्धि तक सीमित है, जैसा अन्य मदों के लिए अनुमत किया गया है।

जैसा कि पहले बताया गया है, बीपीटी के अनुमानों में स्पष्टता का अभाव है। इस संबंध में वास्तविक रिथति का अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय सत्यापन किया जाएगा और अतिरिक्त अनुमान, यदि कोई होगा तो, जो अभी स्वीकार किया गया होगा, उसे अगले चक्र में ठीक ठाक करने के लिए पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा।

- (अ) (i) वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष से संबंधित मदों का अनुमान रु. 87 लाख है जिसमें पिछले वर्ष के लिए मजदूरी (वेतन) संशोधन बकाया मद में रु. 52 लाख भी शामिल हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान वर्ष 2008-09 और 2009-10 में किया गया था। प्रावधान में रु. 52 लाख की कमी के कारण वर्ष 2010-11 में भुगतान किया गया वेतन संशोधन बकाया, पिछले वर्ष से संबंधित मदों के अंतर्गत एक त्वय माना गया है।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.5.2 के अनुसार वेतन / पेंशन के बकाया भुगतान, वीआरएस मुआवजा, विगत देनदारी के लिए पेंशन निधि में अंशदान आदि जैसी एक समय की देनदारी को प्रशुल्क निर्धारित करते समय ग्राह्य लागत के रुप में अनुमत किया गया है। ऐसी बकाया देनदारियों की पूर्ति संचयित अधिशेषों / आरक्षित (निधियों) से जो विशिष्ट रुप से विनिर्दिष्ट निधियों अथवा प्रावधानों से इतर हैं, की जानी है और यदि ये सब भी अपर्याप्त हो तो एक सीमित अवधि के लिए एक विशेष दर के जरिए विगत अवधि के लिए सीएचडी वार्षिक लेखा में सूचित किए गए घाटे को देखते हुए वेतन बकाया प्रावधान के कभी को आरक्षितियों / अधिशेषों से कवर नहीं किया जा सकता। 2005 के मार्गदर्शी, ऐसी एक समय की देनदारियों को जिनकी आरक्षितियों और अधिशेषों से पूर्ति नहीं की जा सकती, सीमित अवधि के लिए एक विशेष दर के जरिए वसूल करने की अनुमति देते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, मात्र इस एक देनदारी के लिए एक अलग दर प्रदान करने की बजाय इसे विगत अवधि क्षति (हानि) के साथ जोड़ दिया गया है जिसके लिए एक विशेष दर प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2010-11 में सूचित रु. 52 लाख के वेतन बकाया को जो पिछले वर्ष से संबंधित हैं, विगत अवधि हानि के साथ जोड़ा जाता है और उनकी पूर्ति अलग से प्रदत्त विशेष लेवी से की जाती है।

- (viii) वीपीटी ने नियोजित पूँजी में कार्यकारी पूँजी को शून्य माना है। वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखा में वर्णित निब्बल अचल परिसंपत्तियों नियोजित पूँजी के लिए आधार लिया गया है जिस पर विश्वास किया गया है। पत्तन ने 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के दौरान परिसंपत्तियों के सकल खंड में कोई अभिवृद्धि प्रस्तावित नहीं की है। 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए निब्बल अचल परिसम्पत्तियों का अनुमान लगाते हुए वीपीटी द्वारा विचार किए गए मूल्यहास में कुछ अंकगणितीय त्रुटि दिखाई पड़ती है जो हमारे विश्लेषण में ठीक कर दी गई है।

पत्तन ने निब्बल अचल परिसम्पत्तियों को व्यापारिक परिसम्पत्ति और व्यापार संबंधी परिसम्पत्ति के रुप में श्रेणीबद्ध / वर्गीकृत किया है। वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसंपत्तियों के रुप में श्रेणीबद्ध / वर्गीकृत किया है। वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर विश्वास किया गया है। किन्तु निब्बल अचल परिसंपत्तियों के अनुमान में किए गए परिवर्तन की नजर से, निब्बल अचल परिसंपत्तियों के व्यापारिक परिसंपत्ति एवं व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के बीच अनुपात वीपीटी द्वारा अनुमानित स्तर पर बरकरार रखते हुए परिवर्तित किया गया है।

पत्तन ने नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ की गणना व्यापारिक परिसंपत्तियों के लिए 16% पर और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों पर 35% पर परिगणित की है। चूंकि वर्ष 2010-11 के लिए प्रतिलाभ की निर्धारित दर व्यापारिक परिसंपत्तियों के लिए 16% और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के लिए 8.4% है, 2010-11 से 2013-14 तक के सभी वर्षों के लिए प्रतिलाभ की दर, व्यापारिक

परिसंपत्तियों के लिए 16% और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के लिए 8.4 % पर विचार किया गया है।

- (ix) उपरोक्त विश्लेषण के अधीन वीपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी को परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित लागत विवरणी संलग्नक-I के रुप में संलग्न है। हमारे द्वारा तैयार की गई संशोधित लागत विवरणी में प्रतिबिम्बित / प्रदर्शित लागत स्थिति का सार संक्षेप नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

वर्ष	टाइम रेट वेजेज	शुद्ध घाटा	शुद्ध घाटा, टाइम रेट वेजेज के % के रुप में
2010-11	1836.99	(-)5244.23	(-)285%
2011-12	1976.40	(-)5004.77	(-)253%
2012-13	2144.80	(-)4945.40	(-)231%
2013-2014	2327.83	(-)5063.36	(-)218%
2010-11 (मार्च 2011 से 2013-14 तक) की अक्षय के चलए कुल योग	6602.12	(-)15450.55	(-)234%औसत

इस मामले में अनुमोदित लेवी जब तक प्रभावी की जाएगी / लागू की जाएगी तब तक वर्ष 2010-11 समाप्ति पर आ चुका होगा। इसलिए, विशेष लेवी का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2010-11 का अनुपातिक घाटा और ग्यारह माह के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक पत्तन द्वारा वसूल की गई लेवी आय पर विगत अवधि के भाग के रुप में विचार किया गया है।

उपर्युक्त के आधार पर, मार्च 2011 और 2011-12 से 2013-14 तक के वषा का लिए रु. 15450 लाख के कुल अनुमानित घाटे पर लेवी निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। लागत विवरणी के अनुसार रु. 15450 लाख के घाटे की भरपाई करने के लिए लेवी टाइम-रेट-वेजेज का 234% है। इस प्रकार सीएचडी के लिए लेवी टाइम-रेट-वेजेज का 234% पर प्रदान की गई है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि तापीय कोयले के वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों में लगाए गए कर्मचारियों (श्रमिकों) के मामले में सामान्य लेवी के अतिरिक्त, सामान्य लेवी के बराबर एक अलग लेवी प्राप्त की जा रही है जिसे, विलय के समय से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पीस रेट लेवी कहा जाता है। पीस रेट लेवी के नाम में अलग लेवी प्राप्त करने का पत्तन द्वारा कोई तर्क और आधार नहीं बताया गया है। प्रस्ताव में भी, पत्तन ने तापीय कोयले पर स्पष्ट तौर पर पीआर लेवी प्रस्तावित नहीं की है। सिर्फ इतना ही बताया है कि इसे प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार (और) बिना किसी अन्य व्याख्या के प्राप्त किया जाएगा। लागत विवरणी के अनुसार घाटे को पूरा करने के लिए लेवी टाइम रेट वेजेज का 234% है जो वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों के लिए सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती प्राप्त करने वाले तापीय कोयले समेत सभी प्रकार के कोयले पर समान रुप से लागू होगा।

टाइम रेट वेज के 234% पर लेवी श्रमिकों का देय टाइम रेट और पीसरेट की वसूली के अतिरिक्त है जो सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती के लिए व्यापार-जगत से प्राप्त की जाती है।

- (x) (क) यह ध्यान देने योग्य है कि विलय के समय पत्तन द्वारा प्राप्त की जा रही 189% लेवी में टाइम-रेट-वेजेज की 50% लेवी भी शामिल थी जिसे विगत अवधि हानि के समक्ष समायोजित किया गया था। इस प्रकार के समायोजनों के बाद 31 मार्च 2010 को संचयी / समेकित घाटा वार्षिक लेखा में रु. 55.40 करोड़ बताया गया है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के ब्याज-आय, ब्याज-व्ययों और वीआरएस भुगतानों को छोड़ते हुए जिन पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया था, वार्षिक लेखा में वर्णित स्थिति पर विश्वास किया गया है। जैसाकि पहले बताया गया है, वर्ष 2010-11 में किया रु. 52 लाख के वेतन बकाया का भुगतान विगत अवधि घाटा में जोड़ा गया है। उपरोक्त समायोजन के अधीन 31 मार्च 2010 तक कुल विगत अवधि घाटा रु. 5554 लाख है।
- 2005 के मार्गदर्शियों में, विगत हानियों की भरपाई हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस बात को मान्य करना होगा कि यह सारा परिश्रम इस गतिविधि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है जो समझौता ज्ञापन की शर्तों में से एक है। यहां तक कि व्यापार-जगत ने भी कोई बिन्दुवार आपत्ति व्यक्त नहीं की है, सिवाय आधारभूत लेवी निर्धारित करने के लिए विगत अवधि घज्जटे को जोड़ने की बजाय एक अलग लेवी का अनुरोध किया है।
- (ख) लागत वेकरणी के अनुसार गतिविधि वर्ष 2010-11 में रु. 5244.23 लाख का अनुमानित घाटा प्रतिविहित करती है। र्यारह महिनों की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक के लिए घाटा जिसे विगत अवधि का हिस्सा माना गया है, रु. 4807.21 लाख होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि लागत विवरणी में दिखाया गया अनुमानित घाटा पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर वसूल की गई लेवी से आय को गिनने से / खाते में लेने से पहले का है। वीपीटी ने लेवी से आय रु. 6395.31 लाख अनुमानित की थी। पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर लेवी लगाने से अक्टूबर 2010 तक एकत्रित की गई वार्ताविक आय रु. 4091.57 लाख है और नवंबर 2010 से फरवरी 2011 तक शेष चार महिनों के लिए अनुमान, पत्तन द्वारा प्रस्तुत अनुमानों पर यथानुपात आधार पर रु. 2131.77 लाख है। इस प्रकार, लेवी से 28 फरवरी 2011 तक कुल राजस्व रु. 6223.34 लाख है जो समकालीन अवधि के लिए प्रदर्शित घाटे के समायोजन के बाद रु. 1416.13 लाख का अधिशेष छोड़ जाता है। रु. 1416.13 लाख का यह अधिशेष, विगत अवधि के लिए आकलित हानि को पूरा करने के लिए लगाया गया है।
- (ग) ब्याज की आय एवं ब्याज पर व्यय प्रशुल्क-निर्धारण में रवीकार्य नहीं हैं और इसलिए इन्हें बाहर रखा गया है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में अर्जित ब्याज-पर-व्ययों से अधिक ब्याज की आय और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए अनुमानित स्थिति कुछ सीमा तक विगत अवधि घाटे को पूरा करने का साधन है। 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए खर्चों के ऊपर बताई गई शुद्ध ब्याज आय की राशि और वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए अनुमानित कुल राशि रु. 195 लाख को विगत अवधि हानि के समक्ष समायोजित किया गया है।

(घ) टाइम-रेट-वेजेज के 300% पर वर्तमान लेवी से पत्तन, 1 अप्रैल 2010 से शुरू करके सात से अलग राशि की अवधि में विगत अवधि घाटे की वसूली की अपेक्षा करता है। प्रस्तुत यही भारत विवरणी के अनुसार, 300% की प्रचलित लेवी पर इस प्रशुल्क चक्र की अंत में विगत अवधि से संबंधित अनकवर्ड घाटा रु. 25.43 करोड़ रहने की समीक्षा है। विगत अवधि घाटा टाइम-रेट-वेजेज के 350% की प्रस्तावित लेवी पर चार वर्षों में अधीत 2013-14 तक वसूल कर लिए जाने की उम्मीद है। वसूली अवधि को केवल एक विशिष्ट प्रशुल्क चक्र से बांध देने (सीमित कर देने) और उपयोगकर्ताओं पर बोझ डाल देने का कोई विशेष कारण नजर नहीं आता है। संचयित घाटे की वसूली उपयोगकर्ताओं पर कोई बोझ डाले बिना धीरे-धीरे की जानी चाहिए और साथ ही इसे पत्तन की कीमत पर (खर्च पर) बहुत लम्बे समय तक खींचा नहीं जा सकता है। मुर्गाव पत्तन न्यास ने 2006 में अपने प्रशुल्क संशोधन के समय, पांच वर्ष की अवधि में पेशन निधि में वृद्धि करने हेतु विशेष लेवी आरंभ करने का प्रस्ताव किया था। इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि पेशन देनदारी को अपेक्षाकृत लंबी समयावधि में फैला दिया जाए ताकि उपयोगकर्ताओं पर बोझ कम किया जा सके। 2006 में एक प्रशुल्क चक्र के लिए आरंभ की गई विशेष लेवी मई 2010 में अनुमोदित एमओपीटी के प्रशुल्क संशोधन में एक और प्रशुल्क चक्र के लिए विस्तारित कर दी गई। यह ध्यान देने योग्य है कि कोलकाता पत्तन न्यास के मामले में जहां पेशन निधि में कमी बहुत अधिक पाइ गई थी, तीन प्रशुल्क चक्रों में पेशन निधि में वृद्धि करने के लिए एक विशेष लेवी आरंभ की जा रही है। वर्तमान मामले में, विगत अवधि घाटे को 1 मार्च 2011 से आरंभ होने वाले दो प्रशुल्क चक्रों में वसूल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) विगत अवधि घाटे से संबंधित स्थिति का विवरण यहां नीचे दिया गया है:-

(रु. लाखों में)

1.	31 मार्च 2010 तक विगत अवधि घाटा	-5554
2.	(क) लागत विवरणी के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए घाटा (रु. 5244.23 लाख 28 फरवरी 2011 तक 11 महीने के लिए समानुपातिक रुप से विचार किया गया)	-4807.21
	(ख) घटाइएः 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक 250% पर और उसके बाद 28 फरवरी 2011 तक 300% पर तदर्थ आधार पर लेवी की वसूली से वीपीटी द्वारा अर्जित राजस्व	6223.34
	(ग) वर्ष 2010-11 के लिए शुद्ध अधिशेष	1416.13
3.	वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लिए ब्याज खर्चों से अधिक शुद्ध ब्याज आय	195.00
4.	प्राप्त अलग घाटे के लिए शुद्ध घाटा, 1 मार्च 2011 को (1+2+3)	-3942.87
5.	1 मार्च 2011 से 31 मार्च 2014 तक वर्तमान चक्र में वसूल किए जाने वाला दिनांक (शुरू) घाटा	-2026.20
6.	मार्च 2011 के माह तथा 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए कुल टाइम-रेट-वेजेज	6602.12
7.	विगत अवधि घाटे को पूरा करने के लिए विशेष लेवी (टाइम रेट वेज का %)	31%

इन्द्रजुलार, विगत अवधि घाटे की पूर्ति के लिए टाइम-रेट-वेज के 31% की विशेष लेवी की अनुमोदन प्रदान किया जाता है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह विशेष लेवी और संस्करण होने वाली आय का एक अलग खाता रखे और राजस्व का केवल घोषित प्रयोग करें तो लिए ही उपयोग करें। पत्तन को, अगली समीक्षा के समय जांच-पड़ताल के लिए इस संबंध में ऑडिट किया हुआ लेखा प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आधार पर अगले चक्र ते लिए विशेष लेवी की मात्रा का निर्णय लिया जाएगा।

- (xi) वीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन संभाग (कार्गो हैंडलिंग डिविजन), गोदी कार्य (डॉक वर्क), गोदी कर्मचारी (डॉक वर्कर), लेवी-दर (रेट ऑफ लेवी) टाइम-रेट-वेज और पीस रेट (वेज) की परिभाषाओं को अपने दरमान के वर्तमान खंड 1 में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। मुख्य पत्तन न्यास (एमओपीटी), न्यू मैगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी), मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमानों में स्टीवेडरिंग प्रचालनों के लिए कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की तैनाती के लिए प्रभार अनुमोदित करते समय इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। गोदी कार्य गोदी कर्मचारी शब्दों की परिभाषा पत्तन की आम बोलचाल की भाषा है (से शब्द एनएच की बोलचाल की भाषा में : लेवी-दर पर दस्तेमाला फिर लावे हैं) और इसलिए इनकी दरमान में परिभाषित छहों की दरों तक प्रत्यक्षता नहीं है। अतः लेवी वीडीएलबी के बीच प्रतिक्रियित रजिस्ट्रेशन में इनमें दरमान अन्वेषण को परिवर्तित करना चाहिए।

टाइम-रेट-वेज पर लेवी-दर के लिए नियमित रूप से कर्मचारियों को देव दर, अन्य दर वर्गों वर्गों के अनुसार प्राप्त है।

पत्तन ने लेवी-दर को, स्टीवेडरी तो लिए जाने के लिए वर्तमान खंड 1 टाइम-रेट-वेज वर्ग प्रतिशतता के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव किया है। इसका उल्लेख कार्गो प्रहस्तन संभाग के प्रशासनिक एवं कल्पना संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। लेवी की वर्गीकृति का तरीका अनुरूपी में अलग हो वाची है और इसलिए लेवी-दर को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुरूपी के नीचे यह बताने के लिए कि लेवी का भुगतान स्टीवेडरी द्वारा वीपीटी को किया जाता है एक जानकारी चाही है।

- (xii) इस प्रकार पर कार्रवाई करने के दौरान तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त अभ्युक्तियों से यह उभर कर आया कि पत्तन ने प्रस्तावित लेवी लागू कर दी है। दिनांक 9 अगस्त 2010 के हमारे पत्र द्वारा पत्तन को सावधान कर दिया गया था कि इस प्राधिकरण ने वीपीटी के दरमान में, कार्गो प्रहस्तन संभाग से श्रमिकों की तैनाती किए जाने के लिए कोई लेवी अनुमोदित नहीं की है। वीपीटी ने रूपरूप किया है कि सीएचडी में भरपूर वित्तीय घाटे को देखते हुए वीपीटी ने व्यापार-जगत के साथ मतैक्य स्थापित करने के बाद 189% की वर्तमान / प्रचलित लेवी को 1.4.2010 से 30.6.2010 तक की तीन माह की अवधि के लिए 250% तक और इसके बाद 350% तक बढ़ाने का निर्णय लिया। व्यापार जगत में टीएनईबी के प्रहस्तन एजेन्ट, वीएसए के प्रतिनिधि आदि इस समुदाय के अन्य सदस्य भी थे। किन्तु, पत्तन ने व्यापार-जगत द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए लेवी को 300% तक सीमित रखा।

प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.1 से 2.17.3 के अनुसार जब कभी / जहां कहीं किसी सेवा / कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क अधिसूचित दरमान में उपलब्ध नहीं हो, तो पत्तन उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और दर को तदर्थ आधार पर तब तक लगा सकता है जब तक कि दर अंतिम रूप से अधिसूचित न कर दी जाए। इस प्रयोजन से तदर्थ दर तुलनीय / समान सेवाओं / कार्गो के लिए प्रचलित अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर परिणित की जानी चाहिए और इन पर प्रत्येक दर के उपर उपयोगकर्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वीपीटी के दरमान ने सीएचडी के लिए कोई दर प्रदान नहीं की अस्तित्व के लिए जैसे पहली उर्ध्वांत 25 सितंबर 2008 तक इसे वीडीएलबी द्वारा प्रचालित किया जाता था। इसके बाद वीपीटी ने यह सेवा 189% की तात्कालिक लेवी पर प्रदान करना जारी रखा। यह लेवी वीडीएलबी द्वारा प्राप्त की जाती थी। चूंकि तात्कालिक लेवी (दर) पर प्रचालनों को जारी रखना व्यवहार नहीं पाया गया, वीपीटी ने व्यापार-जगत की सहमति प्राप्त करने के बाद लेवी बढ़ाने का प्रस्ताव किया था और पहली अवस्था - 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 पर 250% को प्रस्तावित धूदिष्ठ स्थापू की। 30 जून 2010 के बाद की अवधि के तिए, यद्यपि मूल प्रस्ताव में लेवी को टाइम-रेट-वेज के 350% पर प्रस्तावित किया गया था, पत्तन टाइम रेट वेज के 300% पर लेवी प्राप्त करता आ रहा है।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.4 इस प्राधिकरण को पिछले प्रभाव से तदर्थ रूप में अपनाई गई अंतरिम दर को मान्य करने की अनुज्ञा प्रदान करता है। विशेष लेवी की मात्रा निर्णित करते समय, पत्तन द्वारा क्रियान्वित तदर्थ लेवी के आधार पर वीपीटी द्वारा अर्जित आय पर 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक के लिए विचार किया गया है और अनुमेय स्तर से अधिक राजस्व को विगत अवधि घाटे के समक्ष समायोजित किया गया है। अतएव, पत्तन द्वारा 1 अप्रैल 2010 से तदर्थ आधार पर लागू की गई लेवी को इस प्राधिकरण द्वारा मान्य किया जाता है।

13.1 परिणाम स्पर्श प, और ऊपर प्रदत्त कारणों से तथा समग्र विचार विभास के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी के प्रचलित दरमान में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित दरों को खंड 4 - कार्गो संबंधी प्रभाव के अन्तर्गत अनुसूची 4.7.4 के रूप में अनुमोदन प्रदान करता है:-

अनुसूची 4.7.4 - कार्गो प्रहस्तन संभाग से कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रभारों की लेवी

4.7.4.1 टाइम-रेट-वेजेज पर लेवी

चौरा	टाइम रेट वेज पर लेवी की प्रत्याशता
कार्गो प्रहस्तन संभाग से कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी कार्गो के लिए - वैगन उतारने के लिए कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं लेने वाले तापीय कोयले समेत	234%

नोट:

1. ऊपर निर्देशित लेवी, प्रचलित वेतन करार / प्रोत्साहन योजना की विभिन्न धाराओं के अनुसार कर्मचारियों को देय टाइम रेट वेजेज और पीस रेट वेजेज की वसूली के अतिरिक्त है।
2. उपर्युक्त लेवी स्टीवेडरों द्वारा वीपीटी को देय है।

4.7.4.2 अवशेष लेवी

चौरा	टाइम रेट वेज पर अवश्यकता अवशेष लेवी की प्रत्याशता
कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सभी कार्गो प्राप्त करने वाली सेवाओं पर और वैगन उतारने के लिए कार्गो प्रहस्तन कर्मचारियों की सेवाएं लेने वाले तापीय कोयला पर भी।	31%

नोट :

ऊपर प्रदत्त विशेष लेवी, कार्गो प्रहस्तन के लिए सीएचडी से कर्मचारियों की तैनाती के लिए ऊपर अनुसूची 4.7.4.1 में प्रदत्त लेवी के अतिरिक्त है।

13.2 अनुमोदित लेवी 1 मार्च 2011 से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2014 तक वैध रहेगी।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

विशाखापत्नम प्रतन व्यास के कार्गी प्रहरतन से सबूदित लागत विवरणी

संलग्नक -
क फॉर्म में

36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART III—Sec. 3

क्र. सं.	चयरण	वारसत्वक	वर्तमान में लो या रेही तेकी पर शेषी दाया अनुमान				प्रत्यक्षकरण दाया व्यापार व्यवस्था मात्रा अनुमान वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक से दोनों के बीच तेकी आय छाड़कर				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
I	कृषि और वन्यजीव	250 लरा 300%	305%	300%	300%	300%	300%	305%	305%	305%	305%
(i)	कृषि एवं वन	18456567	1130235332	179456000	176565000	185056500	201057000	183656732	19746414	214473692	232783468
(ii)	वन	84081369	28241832	30608000	2971000	29654000	2952100	30684000	2971053	29654000	29521000
II	नियंत्रित और प्रतिक्रिया	152303661	639531000	536082000	643168000	654171900	0	0	0	0	0
(i)	अन्य प्राकृतिक वित्तीय व्यवस्थाएँ पर	3517602	3123366	3218000	3377600	3544000	3721900	3218000	3377600	3344000	3721900
(ii)	वाय	5216800	3234000	2642000	2083900	212900	3224000	2083900	2083900	2083900	2129000
III	कृषि एवं वन्यजीव सहकारी समितियों को अधिकारीय प्रशासन वाय	6219256	7086312	6055000	5388000	4927000	5016000	0	0	0	0
IV	आय का कुल याम	442426188	3108969303	862430000	808682000	868442000	935660000	220758762	232830414	249770692	268143468
V	दूध										
(i)	टाइम टॉक्सेच	151905621	165072198	167456000	164056000	181056000	194057000	163090661	17622301	191996872	209169897
(ii)	पूर्ण रेट वेन्यू	94081369	28241832	30608000	2971000	29654000	2952100	30688000	2971000	29654000	29521000
(iii)	कम्पनियों को अधिकारीय प्रशासन को व्यापार	197575595	198946800	185000000	194250000	201966000	205000000	195000000	19796662	183949167	589165214
(iv)	अधिकारीय प्रशासन को व्यापार	66218152	75145120	2610000	2610000	2610000	2610000	2610000	2610000	2610000	2610000
(v)	कृषि एवं वन्यजीव सहकारी समितियों को व्यापार	5853290	6080398	6080398	6080398	6080398	6080398	6080398	6080398	6080398	6080398
(vi)	कृषि एवं वन्यजीव सहकारी समितियों को व्यापार	69096532	71029653	71029653	71029653	71029653	71029653	71029653	71029653	71029653	71029653
(vii)	कृषि एवं वन्यजीव सहकारी समितियों को व्यापार	276250	276250	276250	276250	276250	276250	276250	276250	276250	276250
(viii)	कृषि एवं वन्यजीव सहकारी समितियों को व्यापार	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336	3194336
VI	प्रशासन वाय										
(i)	प्रशासन वाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	नियंत्रित वाय	0	235965	3166380	235965	235965	0	350000	0	0	0
(iii)	नियंत्रित वाय को व्यापार	0	412576	412576	412576	412576	1364000	0	0	0	0
(iv)	कृषि एवं वन्यजीव को व्यापार	0	412576	412576	412576	412576	2292500	0	0	0	0
(v)	प्रशासन वाय	51726244	75837213	783175866	74367152	74367152	74367152	749046000	731467092	731467092	773161892
(vi)	प्रशासन वाय	-74810056	-417425603	8155800	53621000	53621000	53621000	527231311	536575795	549292862	-505916424
VI	कृषि एवं वन्यजीव										
(i)	प्रशासन वाय	0	15291002	15291002	15291002	15291002	15291000	15291000	15291000	15291000	15291000
(ii)	नियंत्रित वाय	0	435793	435483	435793	435793	533739	533739	4383446	4383446	3510680
(iii)	नियंत्रित वाय को व्यापार	0	435483	435483	435483	435483	1489186	1489186	14515650	14515650	9025920
(iv)	कृषि एवं वन्यजीव को व्यापार	0	435483	435483	435483	435483	383	383	633350	633350	561613
(v)	प्रशासन वाय	51726244	75837213	783175866	74367152	74367152	74367152	749046000	731467092	731467092	773161892
(vi)	प्रशासन वाय	-74810056	-417425603	8155800	53621000	53621000	53621000	527231311	536575795	549292862	-505916424
VII	प्रशासन वाय										
(i)	प्रशासन वाय	0	73761670	73761670	73761670	73761670	6615562	6615562	-53462951	-53462951	-5683536214
(ii)	नियंत्रित वाय को व्यापार	0	73761670	73761670	73761670	73761670	3936	3936	-285%	-285%	-218%
(iii)	नियंत्रित वाय को व्यापार	0	73761670	73761670	73761670	73761670	9223	9223	-218%	-218%	-218%
VIII	कृषि एवं वन्यजीव										
(i)	कृषि एवं वन्यजीव	0	383	383	383	383	1319760	1319760	1319760	1319760	1319760

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th February, 2011

No. TAMP/26/2010-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust for fixation of a levy for deployment of labour of the Cargo Handling Division as in the order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/26/2010-VPT

Visakhapatnam Port Trust

....Applicant

ORDER

(Passed on this 18th day of January, 2011)

This case relates to a proposal dated 4 May 2010 received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of a levy to be levied as a percentage of Time Rate Wages for deployment of labour of the Cargo Handling Division (CHD).

2.1. The VPT has in its proposal dated 4 May 2010 stated that Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) has been merged with Visakhapatnam Port Trust with effect from 26 September 2008 in accordance with the Gazette Notification issued by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways. In this connection, a Memorandum of Settlement was entered between the management of the Visakhapatnam Dock Labour Board, its workers union and the VPT under Section 12 (3) of Industrial Dispute Act in September 2008.

2.2. The main points made by the VPT in its proposal dated 4 May 2010 are given below:

- (i). Prior to merger of VDLB with VPT, the procedure of collection of levy as percentage of time rate wages paid to the workers for the work chances provided was in operation as per the Dock Workers Regulation of Employment Act, under which Registered scheme and Unregistered scheme are approved. The VDLB decided the percentage of levy to be collected from time to time. Accordingly, the levy was collected periodically by raising claims on the stevedores.
 - (ii). A consolidated levy @ 189% of prevailing highest time rate wage of the category of worker was being collected. Apart from this collection of levy, the Time Rate Wages and Piece rate payments made to the workers for the work chances at actual is also collected from the stevedore who engage the workers of Cargo Handling Division.
 - (iii). The Ministry vide their letter dated 24 June 2009 has directed that stevedoring levy may be calculated on tonnage basis instead of percentage of wages of labour, by taking into account the wage cost of full complement deployed presently which could be tapered off in the long run.
- In this direction, meetings were held with the Trade and the Trade has requested to continue the existing pattern of collection of levy of time rate wages and piece rate at actual for some more period.
- (iv). On the date of merger, the total strength of VDLB was 1228 which has reduced to 1165 due to voluntary retirements / super annuations and deaths. The projected staff strength of the CHD division for the 3 years 2010-11 and 2011-12 to 2013-14 is 1165, 1015, 981 and 974 respectively.
 - (v). The basic concept of collection of levy is to meet the administrative expenditure of the organization in full with no loss – no profit. However, the percentage of levy being collected is insufficient to meet the administrative and welfare expenditure fully and in this process the VDLB and the present Cargo Handling Division have incurred losses and accumulated financial deficit as on 31 March 2009 was Rs.21.78 crores. The anticipated loss during the year 2009-10 is Rs.24.40 crores based on provisional figures.

- (vi) In the meeting between the VPT and the trade representatives on 18 March 2010 it was informed to the trade about the financial losses being incurred in respect of CHD. The trade representatives agreed in the meeting for the increase in the levy from the existing 189% to 250% with effect from 1 April 2010 for a period of 3 months and to 350% on time rate wages with effect from 1 July 2010 onwards. They also agreed to enhance the levy pending approval of TAMZ.
- (vii). The VPT Board in their meeting held on 30 March 2010 has accorded sanction to the proposal of VPT.
- (viii) A stevedore has to pay 100% of the amount estimated for loading of a vessel in advance to be adjusted in the final bill to be raised on completion of the vessel. If the stevedore fails to clear the dues within the stipulated period, then it has to pay interest calculated as per State Bank of India PLR plus ten percent thereon.
- (ix). The VPT has furnished consolidated Balance Sheet and Income and Expenditure of the Cargo Handling Division as on 25 September 2009 and as on 31 March 2009 and for the financial year 2009-10. It has also furnished cost statement for Cargo Handling Division giving the actuals for 2008-09 and 2009-10 and estimates for the years 2010-11 to 2013-14. A summary of the cost position reflected in the cost statement filed by VPT is given below:

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Actuals		Estimates at existing tariff			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(i).	Total Income	4424.26	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22
(ii).	Expenditure (excluding ROCE)	5172.36	5594.06	5951.71	6095.31	6814.93	7018.44
(iii).	Capital Employed	—	209.03	185.99	163.86	141.74	119.61
(iv).	ROCE:						
	16% on Business Assets	—	10.31	9.04	7.91	6.78	5.65
	6.35% on Business Related Assets	—	9.18	8.22	7.27	6.31	5.35
(v).	Total Expenditure + ROCE (ii + iv)	5172.36	5613.55	5968.97	6110.46	6828.02	7029.44
(vi).	Excess of Expenditure over Income (i - v)	(748.10)	(2440.45)	(1439.59)	(1618.27)	(2199.03)	(2251.22)

2.3. In this backdrop, and as the adhoc rate is mutually agreed by the trade for collection of levy, the VPT has sought approval of the following rates:

- (i). To collect levy on the daily wage rate made to workers @ 250% for a period of 3 months w.e.f. 1 April 2010 and 350% from 1 July 2010 onwards to meet the cost of Management and other welfare activities.
- (ii). To collect time rate wages and piece rate payments of actual and PR levy on thermal coal will also be collected as per the existing procedure.
- (iii). To collect the percentage of levy as decided from time to time on all the operations without any exception.

2.4. Accordingly, VPT has proposed to insert the following in the Scale of Rates of transport:

- (i). Definitions of Cargo Handling Division, Dock Work, Dock Worker, Rate of levy, Time Rate Wage and Piece Rate are proposed to be included in the existing Section-1 of proposed Scale of Rates of VPT.
- (ii). Insert the following under Section 4 - Cargo Related Charges Schedule 4.7.4:-

Levy on Cargo Handling Services:

Sl. No.	Description	Levy
(i).	Levy to be collected from Trade on daily wage rate made to the workers for the work chance provided	250% for a period of 3 months with effect from 1 April 2010 and 350% with effect from 1 July 2010 on daily wage rate

(ii).	Collection of Time rate wages and Piece rate payments (PR levy on Thermal Coal will also be collected as per the existing procedure)	At actuals
-------	---	-------------------

3. With reference to our advice to furnish the workings of the proposed percentage of levy, the VPT vide letter dated 2 June 2010 has made the following submission:

- (i). The income from CHLD levy was Rs.44.24 crores in 2008-09 and for the year 2009-10 it is anticipated at Rs.31.73 crores. However, the expenditure for the year 2008-09 was Rs.51.72 crores with a deficit of Rs.7.48 crores. For the year 2009-10 the anticipated operating expenditure is Rs.55.94 crores, and considering the return on capital employed of Rs.0.19 crores, the total expenditure was estimated at Rs.56.13 crores with a deficit of Rs.24.40 crores.
- (ii). As on 31.3.2009, the CHD is having an accumulated deficit of Rs.21.78 crores and a shortfall in the pension fund of Rs.27.09 crores. As per the pre-merged scheme, the entire expenditure including the shortfall towards social responsibility is also to the account of stevedores. Accordingly, the shortfall in the pension fund and the accumulated deficit as on 31.3.2009 was also considered as deferred expenditure for a term of 5 years.
- (iii). Considering the above-deferred expenditure of Rs.9.77 crores per annum, the total expenditure per annum is arrived at Rs.65.90 crores, whereas the anticipated income is estimated at Rs.31.73 crores. Considering the income and expenditure as mentioned above it was proposed to enhance the existing levy of 189% to 350% effective from 1.4.2010.
- (iv). Consequent to implementation of pay revision for Group C and D employees, the daily wages have also increased. As the levy is a percentage on daily wages, there is additional contribution in levy on account of this. By considering the enhanced levy of 161% there will be an additional collection in levy by Rs.12.79 crores.
- (v). When the said proposal for enhancement of levy was placed before the stevedores, after having detailed discussion the stevedores have consented to enhance the levy to 250% w.e.f. 1.4.2010 and watch for one year. After detailed discussion and persuasion they had agreed to enhance to 250% from 1.4.2010 and 350% from 1.7.2010.
- (vi). The stevedores have further stated that the existing contracts with most of their principals will expire by end of June 2010 and new contracts will commence from July 2010 onwards. In this context they made a request for consideration of 250% levy which they can bear from the present contract rates for a period of 3 months commencing from 1.4.2010 and thereafter are they are going to enter into a new contract, the proposed 350% levy can be brought to the notice of their principals and accordingly new contracts could be finalised.
- (vii). In view of the said justification though it was proposed to 350% levy from 1.4.2010 onwards, the levy was considered at 250% for a period of 3 months from 1.4.2010 and 350% from 1.7.2010 onwards.

4.1. The Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) vide letter dated 17 April 2010 has informed that the VPT vide letter dated 30 March 2010 has intimated that the levy for engaging the labourers is proposed to be increased from the present levy of 184% to 250% with effect from 1 April 2010 and to 350% with effect from 1 July 2010. The VPT was, therefore, vide our letter dated 27 April 2010 requested to furnish its comments on the point made by TNEB and also furnish authorization on basis of which such enhanced levy was being collected by the port.

4.2. The VPT, vide its letter dated 27 May 2010 responded to the points made by the TNEB mainly reiterating its proposal. The main points made by VPT are summarised below:

- (i). Since the CHD is foreseeing a financial loss to the tune of 23.00 crores for the financial year 2009-2010 the Management reportedly with the consensus arrived in the presence of Trade Members has decided to enhance the levy from the existing 189% to 250% for a span of three months i.e., w.e.f. 1.4.2010 till 30.6.2010 and thereafter 350%.

(ii). It has stated that consensus was arrived with the trade while enhancing the proposed percentage of levy, the Handling Agent of the M/s.TNEB also attended the meeting. The port has furnished a copy of the minutes of its meeting held with the trade on 18.3.2010 in this regard.

4.3. With reference to the points made by the VPT, it was pointed out to the VPT vide our letter dated 9 August 2010 that this Authority has not approved any levy for deployment of labour form Cargo Handling Division in the Scale of Rates of VPT. As per the Section 48 of Major Port Trusts Act, 1963, Major Port Trust is not empowered to levy a tariff without the approval of this Authority for the services listed therein. The decision, if any, taken by the VPT to levy the proposed rate will be only at the risk and consequences of the port.

5. In accordance with the consultation process prescribed, the proposal dated 4 May 2010 received from the VPT was circulated to the concerned users / organisation bodies seeking their comments. The comments received from the users / organisation bodies were forwarded to the VPT as feedback information. The VPT has furnished its remarks on the comments made by the users / organisation bodies.

6.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the VPT was requested to furnish information/clarifications on various points vide our letter dated 9 September 2010. The VPT has furnished its reply vide letter dated 22 October 2010. A summary of the queries raised by us and the clarifications furnished by the VPT are tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Reply furnished by VPT
(i).	It is reported that the Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) was merged with Visakhapatnam Port Trust (VPT) w.e.f. 26 September 2008 and the operations post-merger would come under the purview of MPT Act. But, the proposal for fixation of levy has been filed only in May 2010. The reason for delay of almost a year and a half in filing the proposal may be explained.	In the Memorandum of Settlement entered into under Section 12 (3) of Industrial Dispute Act, at the time of merger of the then VDLB with VPT, it was proposed to continue the collection of levy as per the existing pattern on the time rate wages from the Stevedores. Accordingly, the collection of levy was continued on percentage basis. As the matter stands above, a letter dated 24.6.2009 on Stevedoring Policy for Major Ports – collection of levy on the tonnage basis instead of percentage of wages of labour was received from the Ministry on 13.7.2009. As per the Ministry's directions, the levy is to be collected on tonnage basis and accordingly the agenda was placed in the Board Meeting held on 3.8.2009, wherein the Board resolved to approve in principle collection of levy on tonnage basis instead of percentage of wages of labour as directed by the Ministry subject to approval of TAMP. As resolved by the Board, a Committee was constituted to work out modalities for collection of levy on tonnage basis and thereafter the Committee had ascertained the information from the other Major Ports where the levy on tonnage basis was implemented. After firming up the proposal, the Stevedores were invited for a meeting convened on 13.2.2010 and subsequent meetings were also held on 24.2.2010 and 3.3.2010. In the meeting held on 18.3.2010, the Stevedores made a request for continuation of percentage levy for some more time instead of tonnage basis. In the said meeting a consensus was reached for collection of enhanced levy at the rate of 250% for a period of 3 months commencing from 1.4.2010 and 350% from 1.7.2010 onwards and thereafter to introduce the levy on tonnage basis. As per the consensus arrived, the Board of Trustees of VPT in the meeting held on 31.3.2010 resolved for collection of levy on percentage basis and to submit a proposal to the TAMP. Under these circumstances, there was a delay of 1 ½ years in filing the proposal to the TAMP.

(ii).	(a). The objective of the merger of the erstwhile Visakhapatnam Dock Labour Board with the VPT as highlighted in the Memorandum of Settlement is to ensure regularity of employment, higher labour productivity, quicker turn round of vessel and cost effectiveness in the cargo handling. Please explain the steps taken to achieve the objectives set out in Memorandum of Settlement.	<p>In order to achieve the objectives of the merger of the erstwhile VDLB with VPT as highlighted in the Memorandum of Settlement, towards cost effectiveness in the cargo handling operations the Port Trust had implemented the National Tribunal Award on manning scales and accordingly the manning scales were revised for various activities of cargo handling. This resulted in reduction in manpower per hook per shift and also economy in per ton cost as per the existing tariff as on 31.3.2010 is furnished. The details furnished by VPT is given below:</p> <p>Cost per tonne in cargo handling operations before National Industrial Tribunal Act and afterwards</p> <table border="1" data-bbox="745 649 1338 886"> <thead> <tr> <th>Name of the cargo</th><th>Before Implementation of Manning Scales</th><th>After Implementation of National Tribunal</th><th>After Implementation of Union Agreement</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ores</td><td>20.00</td><td>6.00</td><td>21.00</td></tr> <tr> <td>Iron & Steel</td><td>44.00</td><td>59.00</td><td>233.00</td></tr> <tr> <td>Coking Coal</td><td>16.00</td><td>6.00</td><td>16.00</td></tr> <tr> <td>General Cargo</td><td>54.00</td><td>134.00</td><td>121.00</td></tr> <tr> <td>All Cokes</td><td>22.00</td><td>9.00</td><td>27.00</td></tr> <tr> <td>Bulk Cargo</td><td>37.00</td><td>8.00</td><td>24.00</td></tr> </tbody> </table>	Name of the cargo	Before Implementation of Manning Scales	After Implementation of National Tribunal	After Implementation of Union Agreement	Ores	20.00	6.00	21.00	Iron & Steel	44.00	59.00	233.00	Coking Coal	16.00	6.00	16.00	General Cargo	54.00	134.00	121.00	All Cokes	22.00	9.00	27.00	Bulk Cargo	37.00	8.00	24.00
Name of the cargo	Before Implementation of Manning Scales	After Implementation of National Tribunal	After Implementation of Union Agreement																											
Ores	20.00	6.00	21.00																											
Iron & Steel	44.00	59.00	233.00																											
Coking Coal	16.00	6.00	16.00																											
General Cargo	54.00	134.00	121.00																											
All Cokes	22.00	9.00	27.00																											
Bulk Cargo	37.00	8.00	24.00																											
(b).	A comparative position of the productivity of the cargo handling workers in terms of average output per hook per shift commodity-wise, vessel turn around of the vessel, may be furnished for the two years 2006-07, 2007-08 prior to the merger and for the post merger period till August 2010.	<p>In addition to the above to ensure higher labour productivity, the Port had proposals to replace the existing electrical wharf cranes with higher capacity wharf cranes and also to increase the existing grabs capacity to higher capacity. All these factors put together will ensure quicker turn-round of vessel on long term basis and thus it can be stated the Port had taken efforts to meet the objectives stipulated in the Memorandum of Settlement.</p>																												
(iii).	The Government of India vide letter no LB-13018/4/05-L-II dated 24 June 2009 (as forwarded by the VPT) has formulated a new Stevedoring policy wherein it has directed all the port trusts to calculate the stevedoring levy on tonnage basis instead of percentage of wages of labour. The VPT has not given any valid reasons for not complying with the directions of the Government in this regard except stating that the Stevedores have requested to continue with the existing system of levy on percentage of wage cost. The VPT is requested to explain the reasons for not complying with the Government direction. It may be clarified whether the VPT has approached the Government seeking exemption for not complying with the government direction for per tonne levy for stevedoring activity and if so obtained	<p>A comparative position of the productivity of the cargo handling workers in terms of average difference per hook per shift, commodity-wise, vessel turn around of the vessel for the years 2006-07, 2007-08 i.e. prior to the merger and for the post merger period till 31.8.2010 is furnished.</p>																												

	any exemption from the Government in this regard. If so, relevant documents may be furnished.	
(iv).	The proposal filed by VPT is for levy at 350% on the daily wage rate from 1.7.2010 onwards. The Minutes of the meeting held with the trade members with reference to proposed levy for deployment of labour from Cargo Handling Division, however, shows that the trade had requested to continue with the existing system of levy on percentage basis for some more period. It is not clear upto what time period the VPT proposes to continue with the proposed percentage system of levy before switching over in tonnage based rates, as mandated by the Government instructions.	The VPT proposes for collection of levy at the rate of 350% till such time the accrued financial loss of Rs.21.78 crores as on 31.3.2009 and with further accruals of Rs.41.74 crores till 31.3.2010 (as per audited) and also till fulfilling the shortfall in the pension fund of Rs.165 crores are met. It is anticipated that it may take a period of 5 years with the proposed levy rate, at 350%, to wipe off the accrued financial loss as well as shortfall in the pension fund. However, if the same is fulfilled in less than 5 years, the Management will take necessary steps to switchover to collection of levy on tonnage basis as per the Ministry's instructions.
(v).	The cargo-wise performance assurance by the VPT with reference to the productivity of the labour deployed from the CHD may be stated explicitly which will be included as a conditionality in the Scale of Rates. The VPT may show how the improvement in productivity of the cargo handling workers port merger is considered while arriving at the proposed rate.	Based on the forecast indicated in the Business Plan, the existing cargo profile may continue in future. In order to provide work chance to the labour of CHD it is anticipated that the handling of bulk cargos will continue in future also and thus there will be reasonable employment to the workers of CHD. With this assurance, the Port had proposed for collection of levy on percentage basis in future. The improvement in productivity of CHD in the port merger is furnished.
(vi).	(a). The proposal states that the levy @ 189% of time rate wage being collected by the port is based on the approval of Tripartite Body constituted by the Ministry constituting of members from management, union and stevedore. Please furnish a copy of the sanction of the existing levy and copy of gazette notification if the same has been notified in the gazette. (b). Briefly explain the basis on which the existing levy of 189% was determined in the past.	The Tripartite body consisting of members of Union representative of Stevedores and Management has resolved to collect levy at 189% of time rate wages. Further, it is to state that there is no practice of notifying these levy rates in the Dock Labour Board in the Gazette and, therefore, no Gazette Notification is available for the same. The existing levy of 189% is the combination of various percentages of levies i.e. general levy at the rate of 95%, the special levy at the rate of 39% and additional levy at the rate of 50% and productivity linked reward levy at the rate of 5% on the time rate wages. The general levy is proposed to meet the administrative expenses of the Organization, the special levy is to meet the expenditure on arrears on account of wage revision for Class I & II Officers and Class 'C' & 'D' employees, the additional levy is to meet the deficit of financial loss that which is being accumulated and 5% levy is to pay PLR to the workers only since this being the responsibility of the Stevedores as per the schemes prevailed in Dock Workers Regulations and Employment Act.
(vii).	The proposal states that time rate wages and piece rate payments will be collected on thermal coal at actuals. In this regard the following information may be furnished: (a). Justify the reasons for proposing a different methodology of collecting levy based on actuals only for this cargo item.	Thermal Coal is being received at this Port in bulk in large scale and the cargo handling operations are being done through dockworkers. In this process as the Stevedores have to make all the payments

		<p>including time rate wages, piece-rate payments and levy percentage in addition to other expenditure of overtime, etc., and in order to attract more cargo at this Port, it was proposed to have cost effectiveness for Thermal Coal. Keeping this in view it was proposed to collect the time rate wages and piece-rate payment on actuals on Thermal Coal.</p>																				
	(b). Please indicate the actual income and the actual expenditure related to the deployment of labour for handling thermal coal separately in the cost statement for the period prior to merger and post merger.	<p>The details of actual income and actual expenditure related to deployment of labour for handing of Thermal Coal furnished for the period prior to merger and post merger is furnished. A summary of the cost statement for thermal coal furnished by VPT is given below:</p> <p style="text-align: right;">(Rs. in lakhs)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Particulars</th> <th>26.09.08 to 31.03.09</th> <th>2009-10</th> <th>01.04.10 to 31.08.10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i).</td> <td>Income</td> <td>469.47</td> <td>1009.96</td> <td>1500.35</td> </tr> <tr> <td>(ii).</td> <td>Expenditure</td> <td>757.41</td> <td>1544.48</td> <td>1039.71</td> </tr> <tr> <td>(iii).</td> <td>Surplus/ Deficit</td> <td>(-287.94)</td> <td>(-534.52)</td> <td>460.64</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Particulars	26.09.08 to 31.03.09	2009-10	01.04.10 to 31.08.10	(i).	Income	469.47	1009.96	1500.35	(ii).	Expenditure	757.41	1544.48	1039.71	(iii).	Surplus/ Deficit	(-287.94)	(-534.52)	460.64
Sl. No.	Particulars	26.09.08 to 31.03.09	2009-10	01.04.10 to 31.08.10																		
(i).	Income	469.47	1009.96	1500.35																		
(ii).	Expenditure	757.41	1544.48	1039.71																		
(iii).	Surplus/ Deficit	(-287.94)	(-534.52)	460.64																		
	(c). Please show how the indirect cost like overheads etc, allocable to handling thermal coal is considered for the purpose of levy.	The collection of indirect cost like overheads, etc., for the purpose of levy rate is considered on the basis of ratio between thermal coal and other cargo quantities.																				
	(d). Confirm and show that there is no cross subsidy received by this cargo from the other cargo.	It is to confirm that there is no cross subsidy received by this cargo and in support of the same the cost statement is enclosed.																				
	(e). Explain the term PR levy on thermal coal. Explain the existing procedure for collecting such levy from thermal coal.	In addition to the general levy i.e. 95%, a separate levy is being collected in the name of P.R. levy on thermal coal operations at the rate of 95% of time rate wages of the workers employed for the operations of thermal coal on wagons unloading and this is termed as P.R. levy and the present percentage of levy is at 300% whereas for the period from 1.4.2010 to 30.6.2010 the same was at 250%.																				
(viii).	Furnish the following details for the years 2007-08 and 2008-09 till 25 September 2009 and from 26 September 2009 to 31 March 2009 upto 2010-11 (upto August 2010) subsequent to merger of VDLB with VPT and also with reference to the estimates for the years 2010-11 to 2013-14. The details for thermal coal may also be furnished:																					
	(a). Composition of on-board workers per hook/ per gang.	The composition of on-board workers per hook/per gang for the years 2007-08 and 2008-09 till 25.9.2009 and from 26.9.2009 to 31.3.2009 upto 2010-11 (upto August 2010) subsequent to merger of VDLB with VPT and also with reference to the estimates for the years 2010-11 to 2013-14 is furnished.																				
	(b). Furnish cargo-wise actual traffic handled and cargo which has availed stevedoring service from CHD. This details may also be furnished for estimated cargo throughput for the years 2010-11 to 2013-14.	The cargo wise actual traffic handled and cargo which availed the Stevedores services from CHD is furnished for the years 2007-08 upto 31.3.2010 along with the projections for the years 2010-11 upto 2013-14.																				
(ix).	As per Clause 2.6.2 of the revised tariff guidelines it is necessary to regularly adjust manning scales / datum after due process of law. Further, the Memorandum of Settlement stipulates that the deployment of workers will be subject to the outcome of the Writ																					

	Petition filed by the Unions on the National Tribunal Award. The High Court had vacated a stay on the Tribunal award and has ordered its implementation in all major ports in the country with immediate effect. The VPT is therefore to confirm whether the revised manning scales as per the National Tribunal Award is implemented with reference to the deployment of labour from CHD. In this regard, the VPT is requested to furnish the following:																																																						
	(a). A statement showing a comparative position of the manning scale for various commodities prior to the revised Manning scale notified by the National Tribunal Award and after revision of the manning scale.	The VPT has implemented the National Tribunal Award and accordingly the manning scales were also modified. The present deployment of manpower is as per the revised manning scales. As indicated in the letter a comparative position of the manning scales for various commodities prior to the revised manning scales notified by the National Tribunal Award and after revision of the manning scales is furnished.																																																					
	(b). Please clarify whether the time rate wage cost considered in the cost statement is based on the actual deployment of labour as per the revised manning scale and furnish a calculation in this regard for the years 2010-11 to 2013-14.	The time rate wage considered in the cost statement is based on the actual deployment of labour as per the revised manning scales. It has furnished the details of calculation considered for the relevant years 2010-11 to 2013-14.																																																					
	(c). The VPT has considered 313 number of casual workers in each of the year 2010-11 to 2013-14. Please indicate what is the treatment given in the cost statement with reference the cost of casual workers and indicate for which cargo handling activity they are proposed to be deployed. Please furnish working to show that the cost of casual workers estimated in the cost statement is based on the daily wage rate of Rs.250 per day as per Memorandum of Settlement.	313 casual workers considered in each of the years from 2010-11 to 2013-14 are being deployed after exhausting the regular DLB workers for shore and cargo handling operations. The treatment given for these casual workers while preparing the cost statement is shown separately.																																																					
	(d). Please indicate the average days of employment of the cargo handling workers (year-wise) for the post merger period and also for the years 2010-11 to 2012-13. Please show that after merger of the VDLB, there is no notional booking of labour from the CHLD.	A comparative statement of indicating the average days of employment of the CHD is furnished. A summary position is given below:																																																					
Registered Workers:																																																							
(Average employment in days)																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; width: 15%;">Category</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Actuals</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Estimates</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2007-08</th> <th style="text-align: center;">2009-10</th> <th style="text-align: center;">2010-11</th> <th style="text-align: center;">2011-12</th> <th style="text-align: center;">2012-13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tally Clerks</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Winch</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Winch Drivers</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>T/S Signalman</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>Mazdoors</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table>			Category	Actuals		Estimates			2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Tally Clerks	23	7	14	13	14	Winch	23	7	14	14	14	Winch Drivers	18	10	13	14	15	T/S Signalman	21	17	20	21	23	Mazdoors	22	12	19	20	21												
Category	Actuals			Estimates																																																			
	2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13																																																		
Tally Clerks	23	7	14	13	14																																																		
Winch	23	7	14	14	14																																																		
Winch Drivers	18	10	13	14	15																																																		
T/S Signalman	21	17	20	21	23																																																		
Mazdoors	22	12	19	20	21																																																		
Unregistered Workers:																																																							
(Average employment in days)																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; width: 15%;">Category</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Actuals</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Estimates</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2007-08</th> <th style="text-align: center;">2009-10</th> <th style="text-align: center;">2010-11</th> <th style="text-align: center;">2011-12</th> <th style="text-align: center;">2012-13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W/U/L Maistries</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>I&S Tindals</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>I&S Maistries</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>G K Maistries</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>W/S Sweepers</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>Mazdoors</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Casual Workers</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>			Category	Actuals		Estimates			2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	W/U/L Maistries	23	13	—	—	—	I&S Tindals	17	13	16	20	20	I&S Maistries	22	—	20	20	21	G K Maistries	22	—	—	—	—	W/S Sweepers	24	—	—	—	—	Mazdoors	—	7	13	13	14	Casual Workers	—	—	—	—	—
Category	Actuals			Estimates																																																			
	2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13																																																		
W/U/L Maistries	23	13	—	—	—																																																		
I&S Tindals	17	13	16	20	20																																																		
I&S Maistries	22	—	20	20	21																																																		
G K Maistries	22	—	—	—	—																																																		
W/S Sweepers	24	—	—	—	—																																																		
Mazdoors	—	7	13	13	14																																																		
Casual Workers	—	—	—	—	—																																																		

		In the post merger scenario, it is to state that there is no notional booking of labour from the CHD and the same is to be treated as NIL.
	(e). The copy of the Memorandum of Settlement dated 8 September 2008 for merger of VDLB with the VPT in page no.7 states that the category of deck foremen is redundant categories as per the Manning Scale of National Tribunal Award and for the existing Deck Foremen, it was decided to consider after disposal of the court case. Indicate the present status of the said court case and clarify whether the said litigation has any impact on the existing tariff fixation proposal filed by the VPT for CHLD levy.	The accrued cost pertaining to Deck Foreman is presently referred back to Asst. Labour Commissioner (ALC) [Central] and the same is still pending with ALC. As the category of Deck Foremen is being classified as deck worker, the wages paid to this Deck Foremen will be recovered from the Stevedores and also the applicable levy component on these wages will also accrue to VPT. However, while doing the calculations the time rate wages paid to the Deck Foremen and recovered will be nullified and only the levy component rests with the administration to meet the other direct and indirect costs, contribution to statutory fund, etc. Under this category there are only 16 deck foremen in number, and it would not have considerable impact on the existing tariff fixation proposal.
(x).	(a). The payment of piece rate wages is stated to be as per the incentive scheme. Kindly furnish the details of the existing incentives scheme based on which the time rate wages are estimated for the years 2010-11 to 2013-14. (b). Clause 4.7.3. of the revised tariff guidelines requires all the major ports to revise the datum and rates of piece rate scheme from time to time in terms of the national wage settlements. In respect of the existing piece rates, please indicate when the datum was last revised. Measures taken by VPT to rationalise the piece rate scheme post merger may please be informed.	A copy of the incentive scheme made applicable to the dock workers of CHD is enclosed. The scheme is valid for a period of 5 years from the date of implementation. The present incentive scheme was finalized w.e.f. 1.5.2010 and the cost statement furnished along with the proposal is inclusive of the present incentive scheme. As already mentioned in the preceding para the new incentive scheme was revised w.e.f. 1.5.2010 in which the datum was also revised. The periodicity of 5 years is parallel to the TAMP in terms of the National Wage Settlement and, therefore, the subsequent revision will be taken place after the term of 5 years. However, considering the productivity that may emerge in future may lead to revise the datum on need basis.
(xi).	Income: (a). Please confirm the traffic recognized for estimating employment of workers and therefore, the Revenue, is in line with the Business Plan of the Port. Please furnish the detailed calculations of revenue from time rate, piece rate and levy. (b). Clarify the basis of the estimation of rental income from quarters, stalls and other buildings in the income estimation for the years 2010-11 to 2013-14. (c). Explain the nature and basis of estimating income from Administration charges Deck foremen, hire charge – SSV and electricity and gas Charges SSV other receipts, interest on delayed payments, medical charges from retired employees, hire charges and electricity and gas charges and explain its relevance for determining the levy for deployment of labourers for stevedoring operations.	Based on the traffic projections it is estimated that the dock workers will get full employment and accordingly the calculation of revenue is made. The detailed calculations of revenue from time rate, piece-rate and levy are appended in the cost statement furnished to the TAMP. The rental income from quarters was considered based on the present occupation and also the rates considered are as applicable to the respective categories. Rental income on stalls and other buildings is based on the monthly rental values presently being received by the Organization. The income generating from administrative charges – Deck Foreman and interest on delayed payments are related to workers and cargo handling operations and, therefore, is to be considered for the purpose of fixation of levy. The other rates such as hire charges on SSV, electricity and cost charges on SSV, medical charges from retired employees, hire charges and electricity and cost charges was also considered while fixing the levy since the percentage of levy is to run the administrative charges of the Organization which includes the expenditure being incurred under the above heads. It is, therefore, to

		<p>state that the income being generated on the above heads is having relevance in fixation of levy for deployment of labour for stevedoring operations since it is the responsibility of the Stevedores to incur all the administrative expenditure of the Organization including the welfare measures relating to workers.</p> <p>As clarified at Sl.No. (iii) above, the total levy of 189% is a combination of various levies of which the component of general levy is only being shown in the income and expenditure statements. The rest of the components are of specific nature and, therefore, being adjusted against the respective heads in accounts and, therefore, the variation in the percentage of levy for the period from 1.4.2008 to 25.9.2008 and thereafter upto 31.3.2009. Initially a special levy for wage revision arrears was considered at 20% only which was subsequently enhanced to 39%. In respect of a copy of the relevant Board Resolution is furnished. The 5% levy being collected for payment of PLR to the workers was shown under the relevant head PLR Fund and, therefore, this will not figure in the income and expenditure statements similarly, the additional levy of 50% being collected to meet the deficit in the annual income and expenditure was also transferred to the general reserve and accordingly this component is also not shown in the income and expenditure statements.</p>
	(e)	<p>Explain the relevance of considering the interest income on loan to co-operative society in the tariff fixation of stevedoring services. The details of corresponding expenditure, if any, included in the cost statement, may be furnished.</p>
	(xii).	<p>Expenditure projections:</p> <p>(a). Please confirm whether the Time Rate Wage estimated for the year 2010-11 at Rs.1395.19 lakhs factor the impact of wage revision of staff and officers</p> <p>(b). As communicated vide our letter No.TAMP/27/2005-Misc dated 18 May 2010 to all Major Port Trusts based on the average movement in WPI for the year 2009-10, the escalation factor of 3.76% will be considered for expenditure projections in the tariff cases to be</p>
		<p>The VDLB has given a loan amount to the Cooperative Society which is meant for the benefit of the VDLB workers and employees. As per the provision of the scheme under the Dock Workers Regulation and Employment Act, the welfare measures for dock workers including societies in way of grant of loan or otherwise to cooperative society form for the exclusive benefit of the dock workers and for the benefit of the Board, the loan was granted by the Board from time to time. In the process no expenditure will be incurred by the Board and as such no component is included in the cost statements. However, the interest income on loan to Cooperative Society was considered in tariff fixation since the funds are provided from the general reserve fund of VDLB which was accumulated mainly from the levy component which is nothing but a specific percentage of time rate wages. Thus this is treated as a part of the revenue generated on the reserve fund and, therefore, this component is included in the tariff fixation in the cost statements. No loan is given to the society after merger of VDLB with VPT.</p> <p>The impact of wage revision in respect of dock workers is considered in the time rate wages estimated for the year 2010-11.</p> <p>The escalation factor of 3.76% as communicated by the TAMP vide letter dt.18.5.2010 may not be applicable in respect of the expenditure pertaining to CHD with reference to time rate wages, payments to workers, payment to staff and contribution to statutory funds. In this context it is to state that the escalation factor ranging from 5% to 10%</p>

	<p>decided in the year 2010-11. Hence, the annual escalation considered by VPT in the estimates may be modified at the stated level.</p> <p>(c). The proposed levy to be collected is to cover the overheads as well the retirement benefits such as pension, gratuity, superannuation, etc. Indicate the amount estimated towards the pension fund / gratuity fund contribution. Confirm whether the proposed levy is adequate to meet these liabilities.</p> <p>The Board's contribution to pension fund and other funds is reported at Rs.565 lakhs in 2008-09 which is increased to almost double i.e. Rs.1403 lakhs in 2009-10. For the future period 2010-11 to 2013-14 it is estimated in the range of Rs.1053 lakhs to Rs.1048.79 lakhs annually. Justify the reasons for steep hike in this item in the year 2009-10 and furnish a working in this regard. The source of revenue from which the Board had made the said contribution may also be indicated.</p>	<p>considered while preparing the cost statements, as the major portion of the expenditure is pertaining to labour component only. In view of the above the application of escalation factor of 3.76% in respect of CHD may be exempted.</p> <p>The contributions estimated for the year 2009-10 towards Pension fund is Rs.8,52,87,600/- and for Gratuity is Rs.5,43,04,899/- . The reasons for steep hike in Boards Contribution to Pension fund and other funds is that the Wages/ Salaries were enhanced due to the implementation of wage revision to Staff/ Workers and Officers. The approximate increase is 26 % for Workers & Staff.</p>
	<p>(d). The figures considered in the working of Wage arrears provision from 1.1.2007 to February 2010 is not clear. In this regard furnish the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Actuals wage cost for the years 2007-08 to 2009-10 category-wise duly tallying the total wage cost with the figures reported in the respective Annual Account. ➤ Computation of wage revision impact year wise with reference to the base actual wage cost along with the working. ➤ Provision for the wage revision made in the years 2007-08 to 2009-10. ➤ Clause 2.5.2. of the tariff guidelines stipulates that one time expense such as arrears of wages and pension, VRS compensation, etc., are not allowed as admissible cost while fixing tariff. The VPT has estimated a separate cost under the head "wage revision officers, staff and workers" for the years 2009-10 to 2013-14. Please clarify whether this estimate is towards wage arrears. If so, it is not in line with clause 2.5.2. of the tariff guidelines and cannot be built in the tariff fixation process. 	<p>In accordance with the provision contained in Clause 2.5.2, one time expenditure towards wage revision arrears - Officers, staff and workers and VR benefit to workers and staff are deleted and revised cost statement is furnished.</p>

	(e). The VRS benefit included in the cost statement is not admissible as a cost item while determining the tariff as per clause 2.5.2. of the tariff guidelines and hence may be excluded.	
(xiii).	Capital Employed: (a). Please furnish detailed working of capital employed for the CHD as per Form -4A of the format prescribed. (b). Indicate the basis of segregation of assets as business asset and business related asset and confirm it is in compliance with Clause 2.9.7. of the tariff guidelines.	The detailed workings of capital employed for CHD is furnished. The segregation of assets as business assets and business related assets is done in compliance with the Clause 2.9.7 of the tariff guidelines.
(xiv).	Kindly state whether in the existing set up any surplus labour exists and whether the expenditure attributable to such surplus work force has been included in the cost statement.	The CHD has considered 313 numbers as casual workers in order to meet the shortfall in the manpower depending upon the work. It is further to state even after adding these 313 casual workers the Stevedores are being permitted to engage private labour from outside market as and when necessary.
(xv).	The VPT may confirm that there is no overlapping of any cost elements or capital employed estimated in its general revision proposal and in the cost statement submitted for CHLD.	It is to confirm that there is no overlapping of any cost elements or capital employed estimated in VPT's general revision proposal. In this connection, a work sheet duly deleting the components related to CHD is furnished.

6.2. A summary position of the revised cost statement for the Cargo Handling Division furnished by the VPT is given below for the years 2008-09 and 2009-10 and estimates for the years 2010-11 to 2013-14:

Sl. No.	Particulars	Actuals		Estimates at existing tariff				(Rs. in lakhs)
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
(i).	Total Income	4424.62	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22	
(ii).	Expenditure (excluding ROCE)	5172.36	5594.06	5745.22	5745.51	5968.09	6148.86	
(iii).	Capital Employed	Not furnished	209.03	185.99	163.86	141.73	119.61	
(iv).	ROCE:							
	16% on Business Assets	--	10.31	9.04	7.91	6.77	5.65	
	6.35% on Business Related Assets	--	9.18	8.22	7.27	6.31	5.35	
(v).	Total Expenditure + ROCE (ii + iv)	5172.36	5613.55	5762.48	5760.69	5981.17	6159.86	
(vi).	Excess Expenditure over Income (i - v)	(748.10)	(2440.45)	(1233.10)	(1268.48)	(1352.18)	(1381.64)	

7.1. A joint hearing in this case was held on 2 November 2010 at the Visakhapatnam Port Trust. The VPT made a power point presentation of its proposal. At the joint hearing, VPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

7.2. As decided in the joint hearing, the Visakhapatnam Port Trust (VPT) was advised to furnish its response to the following points:

- (i). Detailed break-up of administrative expenses for the past period as well as the next three years under consideration.
- (ii). Quantify the past period losses pertaining to this activity and explain the treatment given to adjust such past losses in the proposed tariff. The port should also review the period over which such past losses are proposed to be recovered.
- (iii). At the joint hearing, one of the user associations has submitted that the port has already reduced the proposed levy from 350% to 300%. The port may review the proposed percentage levy with reference to the current financial position.

7.3. With reference to the points discussed at the joint hearing, the VPT has responded vide dated 18 November 2010. The main points submitted by VPT are summarised below:

- (i). A statement containing detailed break-up statement of administrative expenses for the past period as well as the next three years is furnished. When comparing the expenditure of 2009-10 with 2010-11, 2011-12 and 2012-13, the increase in expenditure is mainly due to implementation of revised pay scales for the Class I & II Officers and Group 'C & D' employees, effective from 1.1.2007 and arrears were paid during the year 2010-11. Increase in the expenditure under the Head 'Health', is mainly due to extension of rationalized medical facilities to the retired employees (approx. 3000 pensioners) as well as family pensioners which includes referring the medical cases to outside hospitals for treatment as against the existing procedure of providing in-house treatment. Consequent to implementation of cadre restructure in respect of Class-I Officers there is hike in salaries apart from annual incremental expenditure being considered on year to year basis.
- (ii). The erstwhile VDLB is having one activity i.e., manual cargo handling operations. The past period losses that are quantified till the end of 31.3.2009 was Rs.22.57 crores and the accumulated net loss as on 31.3.2010 was Rs.55.40 crores. In order to adjust the past losses, the present CHD had proposed to hike the tariff from existing 189% to 250% w.e.f. 1.4.2010 for a period of 3 months and at the rate of 300% from 1.7.2010 to 31.12.2010 and at the rate of 350% from 1.1.2011 onwards. Considering these percentages and upon continuation of 350% levy w.e.f. 1.1.2011, the annual deficit losses are expected to be adjusted a span of 5 years commencing from 1.4.2010.
- (iii). As already mentioned in the joint hearing, considering the request of the Trade to reduce the enhanced levy from 350% to 300% the revised cost levy statement at the rate of 300% was calculated and the revised cost statement is furnished. Considering the percentage at the rate of 300%, the past losses are expected to be adjusted over a period of 7 to 8 years commencing from 1.4.2010. A comparative statement of Income and Expenditure with 189%, 250%, 300% and 350% as levy is furnished. In the year 2010-11, the workers strength as on 1.4.2010 was 958 and consequent to implementation of VRS, the strength reduced to 873 by 1.8.2010. Accordingly, the time rate wages were calculated and also the levy income.
- (iv). A summary of the revised cost statement is given below:

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Actuals		Estimates at existing tariff collected by VPT			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	Levy %			250 & 300%	300%	300%	300%
(i).	Total Income (including income levy)	4424.26	3089.69	8624.30	8026.82	8644.42	9326.06
(ii).	Expenditure (excluding ROCE)	5172.36	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii).	Capital Employed	--	--	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv).	ROCE						
	15% on Business Assets	--	--	6.89	4.43	2.22	0.01
	6.35% on Business Related Assets	--	--	6.97	4.61	2.29	0.01
(v).	Total Expenditure + ROCE (ii + iv)	5172.36	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi).	Excess Expenditure over Income (i - v)	(748.10)	(4174.03)	-	-	-	-
(vii).	Excess Income over Expenditure (i - v)	--	--	798.69	529.17	707.61	831.58
(viii).	Deficit/ Surplus after adjusting past losses	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4212.14)	(3504.53)	(2672.95)

From the information furnished at item ii and iii above, in order to reduce the span for adjustment of past losses, the TAMP may consider the percentage of levy at 350% commencing from 1.1.2011 onwards till the above losses are adjusted as already agreed by the Trade earlier and thereafter review the levy percentage suitably.

8. Subsequent to the joint hearing, the Visakhapatnam Stevedores' Association (VSA) vide letter dated 10 November 2010 has filed written submissions on the proposal. The submissions made by VSA were forwarded to VPT for their comments. The VPT has responded on the submissions made by the VSA.

9.1. On examining the reply furnished by the VPT vide letters dated 22 October 2010 and 18 November 2010, further information was sought from VPT and same dated 14 December 2010. The VPT has responded vide email dated 24 December 2010. A summary of the questions raised by us and the clarifications furnished by the VPT are summarized below:

Sl. No.	Queries raised by us	Reply furnished by VPT
(i)	The computation of time rate wages for classification of 'Time Rate Wages furnished in Annex 23 does not match with the time rate wages considered in the revised cost statement' filed vide e-mail dated 18 November 2010.	As per the communication of 18 Nov 2010, the Time Rate Wages furnished in Annex 23 does not match with the time rate wages considered in the revised cost statement filed vide e-mail dated 18 November 2010. This was based on revised cost studies. Hence the difference and the information furnished on 18 November 2010 through e-mail is to be considered.
(ii)	The nature of Miscellaneous Expenses 'Difference of time rate wages estimated at Rs.180.00 lakhs in the year 2009-10 may be explained.'	As per the practice in vogue the Time Rate Wages are being collected based on the highest Wage Rate of the category Worker engaged for the work, where the payment is being made as per actuals to be accounted. The difference if any between T.R. Wages accounted and actual payment, is being classified under Misc. Receipts under the head of 'Difference of TR Wages'.
(iii).	The expenditure under the head 'payment to workers' shows steep hike from Rs.967.52 lakhs reported in 2008-09 to Rs.1975.76 lakhs in the year 2009-10. The reasons for such steep increase in this expense in the year 2009-10 which would form the base for the future estimated may be explained particularly in the light of the fact that the port has somewhere else clarified that the impact of wage revision is 26%. The wage revision impact, if any, included in this figure may be indicated separately. Also, confirm it does not include wage revision arrears.	The variation in expenditure under the head 'payment to workers' is due to implementation of the Wage Revision retrospectively i.e. 1.1.2007 onwards. The payment to workers reported in the years 2007-08 and 2008-09 includes provision to the tune of Rs.452.35 lakhs and Rs.517.61 lakhs respectively and of Rs.966.83 lakhs provided in the year 2009-10 is shown separately under the head "Wage Revision Arrears-Workers". A total amount of Rs.216.79 lakhs was shown under other liabilities as on 31.03.2010 towards the provision of wage revision arrears for the workers, Staff & Officers and includes Rs.1936.79 lakhs provided for workers.
(iv).	As regards the health expense, the VPT in its email dated 18 November 2010 clarified that the increase in the expense under this is on account of rationalized medical facilities proposed to the retired employees as well as family pensioners which includes referring the medical cases to outside hospitals for treatment as against the existing procedure of providing in-house treatment. If so, clarify whether the expenditure on health and hospital otherwise incurred in-house is adjusted/reduced to that extent.	As per rationalisation of medical facilities the out-of-hospital referrals were allowed to the retired employees as well as family pensioners in addition to in-house treatment. Hence the increase in expenditure lies in this head.

<p>(v)</p> <p>The port has clarified that of the 189% levy collected in the past, the 50% additional levy is transferred to general reserve fund to meet the deficit in annual income and expenditure. Please show how the objective to meet the deficit is met by transferring the 50% of the levy income so collected to the general reserve fund.</p>	<p>Additional levy @ 50% is being collected based on the Board Resolution No.17/2007 of erstwhile VDLB passed with an object to adjust the losses incurred and accordingly levy transferred to reserve fund to meet the accrued losses and is reflected in the General Reserve Fund Account. The details are as follows:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th style="text-align: center;">2008-09</th><th style="text-align: center;">2009-10</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a).</td><td>Opening Balance of accrued losses</td><td style="text-align: center;">228807508</td><td style="text-align: center;">225729197</td></tr> <tr> <td>(b).</td><td>Current year losses</td><td style="text-align: center;">82684988</td><td style="text-align: center;">417402808</td></tr> <tr> <td></td><td>Subtotal</td><td style="text-align: center;">311492496</td><td style="text-align: center;">643132005</td></tr> <tr> <td>(c).</td><td>Less: Receipts from Additional levy</td><td style="text-align: center;">85763299</td><td style="text-align: center;">89131783</td></tr> <tr> <td>(d).</td><td>Closing balances of accrued losses</td><td style="text-align: center;">225729197</td><td style="text-align: center;">554000222</td></tr> </tbody> </table>			2008-09	2009-10	(a).	Opening Balance of accrued losses	228807508	225729197	(b).	Current year losses	82684988	417402808		Subtotal	311492496	643132005	(c).	Less: Receipts from Additional levy	85763299	89131783	(d).	Closing balances of accrued losses	225729197	554000222
		2008-09	2009-10																						
(a).	Opening Balance of accrued losses	228807508	225729197																						
(b).	Current year losses	82684988	417402808																						
	Subtotal	311492496	643132005																						
(c).	Less: Receipts from Additional levy	85763299	89131783																						
(d).	Closing balances of accrued losses	225729197	554000222																						
<p>(vi)</p> <p>Furnish the Audited Income & Expenditure of Cargo Handling Division operating under Visakhapatnam Port Trust (Traffic Department) for the year 2009-10 and also the actuals for 2010-11 upto October 2010.</p>	<p>Audited Income and Expenditure for the year 2009-10 and the actuals for 2010-11 upto October is furnished. The revised estimates for 2010-11 are based on actuals upto August 2010 i.e. for 5 months and estimates from September 2010 to March 2011 is also furnished which were calculated on prorata bases for 7 months duly relying on actual of 5 months with increase of 5%.</p>																								
<p>(vii)</p> <p>Explain how the income from levy is estimated. Furnish detailed working in this regard for each of the years 2010-11 to 2013-14. Confirm whether income from levy is estimated on the actual time rate wages payable to the worker deployed for handling cargo.</p>	<p>The income is estimated only on the actual Time Rate Wages collected from the workers deployed for handling cargo. For the year 2010-11, it is estimated on the actuals of Time Rate Wages incurred upto October 2010 and escalated with 3% for the remaining 5 months keeping in view the increase of Dearness Allowances, annual increments, etc. and the levy was computed at different percentages i.e. 189% to 350% of Time Rate Wages as resolved by the Board. However as an example the calculation of TR Wages and Levy @ 300% is furnished.</p>																								

The port has furnished revised cost statement wherein it has estimated the differential time rate wages for the years 2011-12 to 2013-14 which was not considered earlier by the port. A summary position of the final revised cost statement for the Cargo Handling Division furnished by the VPT vide its letter dated 28 December 2010 is given below for the years 2008-09 to 2009-10 and estimates for the years 2010-11 to 2013-14:

Sl. No.	Particulars	Actuals		Estimates at existing tariff			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	Levy %			250% & 300%	300%	300%	300%
(i).	Total Income	4424.62	3089.69	8624.30	8086.82	8684.42	9356.06
(ii).	Expenditure (excluding ROCE)	5251.11	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii).	Capital Employed	Not furnished	Not furnished	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv).	ROCE	Not furnished	Not furnished	13.86	9.04	4.51	0.02
(v).	Total Expenditure + ROCE (ii + iv)	5251.11	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi).	Excess Expenditure over Income (-) and Excess of income over expenditure (+) (i - v)	(826.85)	(4174.03)	798.60	589.17	747.	861.58
(vii).	Deficit/ Surplus after adjusting past losses	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4152.14)	(3404.53)	(2542.95)

10. Subsequently, VPT vide fax dated 28 December 2010, 30 December 2010, 4 January 2011 and 7 January 2011 has furnished further information/ clarifications which are summarised below:

- (i). It has furnished the working of the estimate of time rate wage and the levy for the year 2010-11 based on the actuals upto October 2010.
- (ii). It has furnished breakup of C & Rmt relating to previous year estimated at Rs.3/ lakhs in the year 2010-11. As per the breakup furnished by the VPT, Rs.52 lakhs pertains to wage revision amounts relating to previous year.
- (iii). The port has clarified that as per the actuarial valuation of Group Levy Encashment Scheme given by the LIC for the year 2009-10, an amount of Rs.4.75 crores has been charged in Group Levy Encashment Scheme in the year 2009-10.
- (iv). (a). The port has also furnished the breakup of the contribution to pension fund reported as Rs.1.75 crores in the year 2009-10 as follows:

Contribution to pension fund in respect of Officers, Staff, Workers & Peons	85287000
Wage Board Levy and Pensions	66700000
Total	151987600

- (b). The port has informed that hike in the pension contribution is due to revised actuarial valuation consequent to revised DA and/or periodical increase in DA etc. A provision for payment of pension benefits is also made on the basis of outcome of wage revision to pensioners during the year 2010-11 as the revised pension amounts are received in January 2010 only.
- (c). The contribution to pension fund is made at 27% of the basic and DA of the workers based on the report of the actuarial valuation. For the year 2009-10, Basic Pay of 75% of the staff strength was restricted to Rs.1 lakh per employee and making contribution towards pension @ 27%. Hence less provision is made. For the year 2010-11, the contribution towards pension is made at 27% on basic plus DA of the CHD employees and if the contribution so arrived is more than Rs.1,00,000, then it is restricted to Rs.1,00,000 per employee.
- (d). The pension fund based on actuarial valuation as on 1 April 2010 is estimated at Rs.152.20 crores by the actuarial LIC. The port has substantiated the same in its fax with copy of the actuarial report. The port has stated that the pension fund balance as on 1 April 2010 is Rs.158.20 crores and the shortfall in the pension fund is Rs.162 crores.

11. The proceedings relating to adjudication in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the documents received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the concerned parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

12. With reference to the total amount of collection collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The erstwhile Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) has merged with the Visakhapatnam Port Trust (VPT) with effect from 20 September 2008. Prior to the merger, levy for deployment of labourers from the VDLB was decided by the Dock Labour Board. With the merger of the VDLB with the VPT, a separate division termed as Cargo Handling Division (CHD) under VPT oversees the function of deployment of workers for cargo handling purposes and, therefore, the charges levied therefor fall under the regulatory ambit of this Authority.

- (ii). As per the terms of the Memorandum of Settlement entered between the VPT and the VDLB, the port continued to apply the then prevailing levy of 189% in the post merger scenario till 31 March 2010. The instant proposal of the port is to increase the (then) prevailing levy of 189% to 250% of the time rate wages for three months with effect from 1 April 2010 to 30 June 2010 and thereafter at 350% from 1 July 2010 onwards.

The port has justified that the then prevailing levy of 189% collected prior to the merger is insufficient to meet the administrative expenses. The increase proposed in the levy is with the sole objective to meet the administrative and welfare expenditure of the CHD, to recover the past period losses to the tune of Rs.55.40 crores over five years span and the shortfall in the pension fund liability. The port has stressed that the increase proposed in the levy is not with any profit motive. Based on the discussion with the trade and consent of the trade, the port has implemented the increase proposed in the levy from 1 April 2010. Though the proposal of the port was to increase the levy to 350% of the Time Rate Wages, on the request made by the trade, levy is being collected 300% of time rate wages as reported by the port, which is confirmed by some of the users/ user associations.

- (iii). Clause 4.7.2. of the tariff guidelines recommends prescription of levy on per tonne basis for stevedoring activity when the stevedoring operations is undertaken as a separate activity by the port. The guidelines allow prescription of percentage based levy on the actual wages where only on-board labour is supplied. At VPT, the role of the port is limited to supply of labours. The VPT has brought out that the Ministry of Shipping vide its letter No.LB-13018/4/05-L-II dated 24 June 2009 has formulated a new Stevedoring policy wherein it has directed all the port trusts to calculate the stevedoring levy on tonnage basis instead of percentage of wages of labour. When sought the reasons for not complying with the directions of the Government, the VPT has clarified that whilst the port insisted on prescription of the per tonne rate, the trade and the stevedores have objected to introduction of per tonne levy for CHD labour and requested to continue with the existing system of collection of levy on percentage basis for some more time. The Board of Trustees of VPT had reconsidered its earlier stand and approved continuance of percentage levy. It is notable that tariff guidelines of 2005 allow prescription of percentage based levy on the actual wages where the service is only for supply of labour which is the position in the instant case. In view of that, and recognising the proposal of the VPT to continue with the existing method of levy on percentage of actual wages flows from the request made by the trade which is substantiated with the copy of the minutes of the meeting dated 18 March 2010 attended by the relevant trade members including Visakhapatnam Stevedores Association (VSA), the proposal of VPT for percentage based levy on the time rate wages is accepted for the current cycle.

It is notable that per tonne rate linked to productivity of workers will act as an incentive to stevedores to achieve better performance and the said approach will foreclose the scope for multiple accounting of the cost of same labour gang. Viewed from this perspective and in view of the specific direction from the MOS for prescribing per tonne levy for stevedoring activity, the port is advised to formulate tonnage based levy at the time of the next review / revision of the CHD activity.

- (iv). Though the VDLB is merged with the VPT, accounts are maintained separately for the CHD as per the Memorandum of Settlement. The VPT has furnished cost statement for the CHD activity based on the actuals for the year 2008-09 prior to merger (till 25 September 2008). It has also furnished the actual cost position for the post merger period from 26 September 2008, and for the year 2009-10 along with the estimates for the years 2010-11 to 2013-14. On our request, the port has subsequently furnished the actuals for the CHD activity for the year 2010-11 upto October 2010. The estimates furnished in final revised cost statements submitted by the VPT vide its letter dated 28 December 2010 alongwith the information/ clarifications furnished during the processing of the case is considered in the analysis.

- (v). The accumulated loss in the CHD activity as on 31 March 2010 is reported as Rs.55.40 crores. The port proposes to recover the legal expenses and the admissible return of the CHD activity for each of the years 2010-11 to 2013-14 and to set off total past period loss of Rs.29.97 crores out of the accumulated loss of Rs.55.40 crores assessed for the past period till 31 March 2010. The balance past period loss of Rs.25.42 crores is proposed to be recovered in the next tariff cycle.

It is notable that users/ user associations including CHD have principally not made any pointed objection on the proposal of VPT to set off the past losses in the CHD activity except suggesting that a separate stevedoring levy may be prescribed for limited period to meet the past period loss. Instead of clubbing with the general levy, The VPT, however, demands that such a special levy should be levied directly from Importers/ Exporters. This suggestion cannot be accepted as stevedoring levy is recovered from stevedores who engage the cargo handling workers and no justification emerges for shifting the tariff burden on to some other user group.

The approach adopted by the VPT to propose a separate levy which will also provide funds to meet the past losses does not appear to be sound in as much as it may not only perpetuate the past loss in future years but also does not ensure the application of the specified utilisation to offset the past losses.

That being so, a separate levy as a percentage of the time rate wages to arrived at for a limited period to meet the past period loss. Thus, as apprehended by some of the user associations, the past period loss will have little influence on the determination of basic levy and at the same time will not put the port in any financially disadvantageous position.

- (vi). The time rate wages and the piece rate wages payable to workers deployed from the CHD are recovered from the SI stations. Hence estimates of time rate wages and piece rate wages payable to workers are rightly reflected in the income side as well as the expenditure side by the VPT. The levy is proposed to be collected on the time rate wages. The time rate wages estimated by the VPT and the modification done in our analysis is explained hereunder:

- (a). The port has confirmed that impact of wage revision in respect of dock workers is considered in the estimation of time rate wages for the year 2010-11. The time rate wages will depend on the deployment of labour from the CHD. The port has furnished actual time rate wage upto October 2010. For the purpose of estimates for 2010-11, the annual time rate wages reported by the VPT for the period from April 2010 till October 2010 together with the estimates furnished by the port on pro rata for the balance five months are considered. The differential time rate wages is also added to the estimates for the reasons explained in the subsequent paragraphs.
- (b). The estimated time rate wages for the year 2011-12 as arrived by VPT by increasing the corresponding figure for the previous year by 1.4%. No justifiable reason is given by the VPT for restricting the increase in time rate wages to 1.4% when the overall traffic of the port as furnished in the general revision shows 7.5% increase in the year 2011-12 and the coal traffic in particular is projected to increase by 22.6% in this year. Further, the time rate wages for the subsequent two years 2012-2013 and 2013-2014 are estimated to increase by 9.4% and 10.4% respectively.

The average deployment of labour for the year 2010-11 furnished by the VPT is 14 to 16 days for most of the categories of workers and 19 to 20 days in a month for the mazdoors, signal men and maistries. On examining the working of time rate wages furnished by the VPT for the year 2011-12 to 2013-14 vide its letter dated 22 October 2010, it is observed that the port has not factored increase in deployment of labour from the CHD on account of increase in the cargo volume availing the

services of the CHD. The cargo traffic expected to avail the CHD services and the annual escalation in wage cost are the two factors relevant for estimation of time rate wages.

The port has not furnished cargo volume which will utilise the services of CHD for the years 2010-11 to 2012-13 despite request. Based on the actual cargo volume reported to have availed services of CHD for the year 2010-11 till August 2010, the total traffic of CHD for the year 2010-11 will be 161.65 lakh tonnes. In the proposal filed by the VPT for general revision of its Scale of Rates which is being processed separately, the overall traffic for the years 2011-12 to 2012-13 is estimated to increase by 7.5% and 11.5% respectively. In the absence of any traffic details provided by the VPT relating to the CHD for the years 2011-12 to 2013-14 but at the same time recognising the cargo volume availing the services of the CHD need not necessarily grow at the same level as the overall growth in the traffic of the port, for the purpose of this analysis, cargo volume availing the services of the CHD is assumed to grow by 5% per annum for the purpose of estimating the time rate wages. The time rate wage estimated for the year 2010-11 based on seven months actuals is taken as the base and adjusted for 5% growth in the traffic and annual escalation of 3.76% is applied for estimating the time rate wages for the years 2011-12 to 2013-14. The estimate for time rate wage considered in the income side is also reflected in the expenditure side.

(c). The VPT has reported that time rate wages are collected at the highest wages for each category of workers. Actual payment to workers are, however, made with reference to the wages payable as per the entitlement of each worker. Difference between the time rate wages actually collected from the Stevedores and the time rate wages actually paid are accounted for as miscellaneous receipts under the head "Difference of Time Rate Wage".

Ideally, the time rate wages should be collected on the actual wages payable for the workers deployed. But recognising that the practice of collecting highest time rate wage for each category of workers is already in vogue and the billing issues, the same is allowed in this tariff cycle. A careful examination of the practice will reveal that the billing method adopted will not result in any undue advantage to the port at the expense of stevedores. The difference between the time rate wage collected and actually paid is accounted as income which goes to reduce the uncovered deficit to be met out of levy.

For the purpose of determining the levy in the cost statement prepared by us the differential of time rate wage shown separately by the VPT is clubbed with the estimate of revenue from time rate wages recovery to reflect the total time rate wages on which the levy is collected.

(d). The revenue on account of difference in time rate wages estimated by VPT is Rs.180 lakhs. The actual receipts on account of difference in time rate wage for the period from April 2010 upto October 2010 is reported at Rs.131.08 lakhs. For the balance five months of the year 2010-11, the estimate of difference in the time rate wages is considered pro rata based on the estimates furnished by the port in line with the approach adopted for estimating the time rate wages for the year 2010-11. Accordingly, the estimate for this item is considered at Rs.206.09 lakhs for the year 2010-11 in line with the approach adopted for estimating the time rate wages.

In the original proposal, the port had not estimated revenue from difference in time rate wage for the subsequent years 2011-12 to 2013-14. It has subsequently vide letter dated 28 December 2010 estimated the income under this head at Rs.80 lakhs, Rs.60 lakhs and Rs.40 lakhs for the years 2011-12 to 2013-14 respectively.

The sudden drop in revenue from difference in time rate wage during these years is not explained by the VPT. Reduction, if any, under this head can mainly be on account of one annual increment in wages actually earned by all workers. In the absence of detailed working given by the port for estimating this item of income, for the purpose of the analysis, the average of the differential in time rate wages reported at Rs.326.35 lakhs for the year 2008-09, Rs.79.50 lakhs in the year 2009-10 and estimate of Rs.206.09 lakhs in the year 2010-11 is taken as a base and adjusted for traffic growth assumed at 5%. Recognising that this estimate will reduce to the extent of one increment payable to workers which is 3%, the annual escalation in the wage cost of 3.76% which is otherwise applicable is not factored. Subject to above modification, the revenue from difference in the time rate wages is estimated at Rs.214.18 lakhs in the year 2011-12, Rs.224.89 lakhs in the year 2012-13 and Rs.236.13 lakhs in the year 2013-14.

- (e). The modified time rate wages including revenue from the difference in time rate wages considered in the cost statement is Rs.1836.99 lakhs, Rs.1976.40 lakhs, Rs.2144.80 lakhs and Rs.2327.83 lakhs for the years 2010-11 to 2013-14 respectively.

- (vii). Apart from the time rate wages, the cost statement furnished by the VPT shows various items of income and expenditure. In the modified cost statement considered, the income and expenditure items have been suitably grouped based on the nature of the income and expense. The analysis relating to the other items of income and the expenditure estimated by the VPT and the modifications done in the estimates are discussed briefly hereunder:

- (a). The VPT has confirmed that it has implemented the National Tribunal Award on manning scales and accordingly the manning scales has been revised for various activities of cargo handling. The port has confirmed that present incentive scheme was finalized from 1 May 2010 and the estimates reckons the present incentive scheme. The estimates of piece rate wages furnished for the year 2010-11 seem to be reasonable when the actuals reported upto October 2010 are extrapolated for the full year and hence the estimates of VPT are accepted. For the years 2011-12 to 2013-14, the piece rate payment is estimated to reduce by 2.7%, 0.4% and 0.5% respectively.

The piece rate wages are shown at the same level on both the income as well as the expense side representing the amount collected from stevedores and the payment made to workers.

- (b). On the income side VPT has considered interest income from loan to co-operative society, interest on investment, and interest on advance to staff and workers in the estimates for the years 2010-11 to 2013-14. On the expenditure side, the VPT has considered interest payable on PF trust in the estimates for the year 2010-11. In line with the general approach followed by this Authority, the interest element both on the income side and the expense side are excluded from the cost statement.

- (c). The port has stated that annual escalation of 3.76% permitted as per tariff guidelines will not apply in this instant case as the major cost component is relating to the labour component. The port has estimated the expenses considering annual escalation of 5% to 10%. The annual escalation factor adopted for the year 2010-11 is 3.76% based on the WPI for the year 2009-10. The annual escalation of 3.76% has been applied uniformly in the other tariff revision cases like the Mormugao Port Trust, South West Port Limited, etc. decided in the year 2010-11. The tariff guidelines do not specify any differential treatment in fixing cargo handling worker related charges. Therefore, the annual escalation in the estimates of expenditure is restricted to 3.76% wherever it is found to be higher subject to the analysis given hereunder.

- (d). The port has considered VRS payment to workers as a cost and amortised the expense over five years. One time expense such as arrears of wages and pension, VRS compensation, etc., are not allowed as admissible cost while fixing tariff. Hence the VRS payment is not considered in the cost statement for the years 2010-11 to 2013-14.
- (e). Time rate wages reflect payments made to the workers who are engaged for the cargo handling service. Apart from time rate wages, wages payable to worker for the period when they are not deployed is captured separately as an expense in the cost statement by the VPT. The port has confirmed that the estimate of payment to worker, officers and staff in the year 2010-11 is after taking into consideration the impact of the wage revision. It has also confirmed that the estimate for the year 2010-11 under this head does not include any arrears relating to the past.

For the year 2010-11, the VPT has estimated payment to worker at Rs.1989.46 lakhs. The expenditure on payments to workers and staff will generally follow the fixed pattern. The estimates furnished by the VPT are found to be higher when the actuals furnished by the VPT upto October 2010 are extrapolated for the full year. The estimates for the year 2010-11 are moderated based on actuals furnished upto October 2010. The estimate of payment to officers and staff for the year 2010-11 is found to reasonable when compared with the extrapolated figures based on actuals upto October 2010 and hence is accepted.

The payment to workers, officers and staff is estimated to increase by 5% per annum in the years 2012-13 and 2013-14. The VPT has stated that the total strength of workers and staff under the CHD is expected to reduce from 1165 in 2010-11 to 1015, 981 and 974 during the years 2011-12 to 2013-14 respectively. The payment to worker and staff estimated by the VPT does seem to capture the reduction in the workers and officers/staff particularly in the years 2012-13 and 2013-14.

The estimates of payment to workers and officers/ staff are modified considering the average payment to workers/ staff and officers considered for the year 2010-11, the strength of workers/ staff and officers furnished by the VPT assuming that on an average retirement will be in the middle of the respective year and applying 3.76% annual escalation.

- (f). The VSA has argued that the levy should be to recover only the direct expense payable to the workers and the indirect expenditure like quarters no longer used by labourers, schools etc. should be included in the overall overheads of VPT and recovered through wharfage charges. The port has clarified that administration and other expense relate to the CHD activity and the facility like quarters, etc., are being used by CHD labourers and staff only and hence the expenditure relating to CHD is to be recovered as part of the levy. The suggestion of the VSA to recover the overheads of the CHD through the general revision of the port Scale of Rates would entail other cargo to share the burden of cost for services not availed by them and result in cross subsidizing the CHD activity. Hence, the point made by the VSA cannot be considered.
- (g). The estimate of expenses by the VPT for the year 2010-11 towards office maintenance, repairs and maintenance, health, education, etc. are modified extrapolating the figures based on the actuals furnished upto October 2010 as done for estimation of payment to workers and staff.

For the years 2011-12 to 2013-14, the VPT has considered 5% escalation factor while estimating most of the items and 10% annual escalation is considered while estimating the health expense. The annual escalation in estimates for the years 2011-12 to 2013-14 is restricted to 3.76% per annum over the estimates of the respective previous year in line with the general approach followed for estimating other expense.

- (h). The actuals reported in the year 2009-10 includes Rs.4.74 crores towards Group Leave Encashment Scheme. The port has clarified that the estimate is based on the actuarial valuation of Group Leave Encashment Scheme given by the LIC for the year 2009-10. For the year 2010-11 Rs.1.33 crores is estimated under this head. When the actuals furnished by the VPT under this head upto October 2010 is extrapolated for the full year, the estimate for the year 2010-11 are found to be matching and hence the estimate furnished by VPT for this item is accepted. The estimates for the years 2011-12 to 2013-14 do not include any estimate on Group Leave Encashment Scheme.

- (i). The contribution to various pension funds like DA provident fund, HRA fund, etc., is reported in Rs.2124 lakhs in the year 2009-10 as against Rs.916.81 lakhs in the previous year 2008-09. The increase in the contribution to Pension Fund, Gratuity Fund, etc., for the year 2009-10 is found to be more than four times the amount of contribution reported in the year 2008-09. In the year 2010-11, the contribution towards the above mentioned funds is estimated at Rs.1519 lakhs, Rs.1958 lakhs respectively. For the subsequent years, the port has estimated 5% and 10% increase respectively over the last rates of the respective previous years.

On seeking clarification for steep increase in this item over the 2008-09 actuals, the port has clarified that the increase in the contribution is mainly due to revised actuarial valuation consequent to revised pay scale, provident increment, DA, etc. Of Rs.1519 lakhs reported as contribution to Pension Fund in the year 2009-10, the port has clarified that Rs.852.87 lakhs is the actual contribution made to the Pension Fund and Rs.667 lakhs is the provision made towards the contribution to the Pension fund based on huge revision to pensioners declared in January 2010. The contribution to Gratuity Fund is reported at Rs.595.58 lakhs in the year 2009-10 reportedly made at 8.33% of the basic plus DA of the strength of the CHD employees.

The port has clarified that in the year 2010-11, the contribution to pension fund is made at 27% of the basic and DA of the workers and if the contribution is more than a lakh per employee, the contribution is restricted to 1 lakh per employee. Whereas in the year 2009-10, the contribution to Pension Fund was made at 27% of restricting the basic plus DA per employee at 1 lakh for making such contribution. The contribution to pension fund and gratuity fund is reportedly as per the actuarial valuation in line with the terms of the Memorandum of Settlement.

Though port has attempted to justify its estimates, a clear position for the steep increase in this item does not emerge. The pension fund liability as per the actuarial valuation is estimated at Rs.320 crores as on 1 April 2010 by the Life Insurance Corporation. The pension fund balance is reported at Rs.158.20 crores and shortfall in the pension fund is as on 1 April 2010 is estimated at Rs.162 crores. The port has confirmed that the estimates of contribution towards Pension Fund, Gratuity Fund, etc., does not include any arrears. Despite specific request, the port has not furnished the working of the estimated contribution to various funds for the years 2010-11 to 2013-14 with reference to the revised estimates furnished to the VPT vide letter dated 28 December 2010.

Nevertheless, from the position furnished by the port, it emerges that there is huge shortfall in the Pension Fund liability to the tune of Rs.162.00 crores as on 1 April 2010. Therefore, contribution to Pension fund, gratuity fund, provident fund, etc., reported in the year 2009-10 and the estimates by the VPT for the year 2010-11 are considered without any modification. For the subsequent years, the total contribution to the various funds is restricted to the annual escalation of 3.76% as allowed for other items.

As mentioned earlier, the estimates of VPT lack clarity. The actual position in this regard will be verified at the time of next tariff review and the excess estimates, if any, considered now will be fully adjusted in the tariff to be set for the next cycle.

- (i). The items relating to previous year in the year 2010-11 is estimated at Rs.87 lakhs which includes Rs.52 lakhs towards wage revision arrears for the previous year. The port has clarified that the provision for wage revision arrears was made in the years 2008-09 and 2009-10. To the extent of shortfall in the provision to the tune of Rs.52 lakhs, wage revision arrears paid in the year 2010-11 is treated as an expense under items relating to previous year.

As per clause 2.5.2. of the tariff guidelines of 2005, one time liability like arrears of wages/pension, VRS compensation, contributions to Pension Fund for past liability, etc. are allowed as admissible cost while determining the tariff. Such arrears are to be met from the accumulated surpluses/ reserves other than specifically earmarked funds or provisions and if it is still not adequately covered, then through a special rate for a limited period. In view of loss reported in the CHD Annual Accounts for the past period, the shortfall in the wage arrears provision cannot be covered from the reserves/ surplus. Guidelines of 2005 allow to recover such one time liability which cannot be met from reserves and surplus through a special rate for a limited period. Recognising the amount is not significant instead of prescribing a separate rate only to meet this liability, it is clubbed with the past period loss for which a special rate is prescribed. That being so, the wage arrears to the tune of Rs.52 lakhs reported in the year 2010-11 which relates to previous years is clubbed with the past period loss and met from special levy prescribed separately.

- (viii). The VPT has considered the working capital as nil in the capital employed. The net fixed assets as reported in the Annual Accounts of 2009-10 is taken as the base for capital employed which is relied upon. The port has not proposed any additions to the gross block of asset in the years 2010-11 to 2013-14. There seems to be some arithmetical error in the depreciation considered by the VPT while estimating the net fixed assets for the years 2010-11 to 2013-14 which is corrected in our analysis.

The port has classified the net fixed assets as business asset and business related assets. The classification of assets furnished by the VPT is relied upon. However, in view of modification done in the estimate of net fixed assets, the classification of net fixed assets into business assets and business related assets are suitably modified maintaining the ratio of the business assets and business related assets at the level estimated by VPT.

The port has computed the Return on capital employed at 16% for business assets and at 6.35% on business related assets. Since the rate of return fixed for the year 2010-11 is 16% for business assets and 8.4% for business-related assets, return of 16% for business assets and 8.40% for business related assets are considered for all the years 2010-11 to 2013-14.

- (ix). Subject to the above analysis, the cost statement furnished by the VPT is modified. The modified cost statement is attached as Annex - I. Summary of the cost position reflected in the revised cost statement prepared by us is given below:

(Rs. in lakhs)

Year	Time Rate Wages	Net deficit	Net deficit as % of time rate wages
2010-11	1836.99	(-)5244.23	(-) 285%
2011-12	1976.40	(-)5004.77	(-)253%
2012-13	2144.80	(-)4945.40	(-)231%
2013-14	2327.83	(-)5063.36	(-)218%
Total for the period 2010-11 (from March 2011 till 2013-14)	6602.12	(-)15450.55	(-) 234% Avg.

The year 2010-11 will almost come to an end by the time the levy approved in this case is made effective. Hence, the proportionate deficit for the year 2010-11 and the levy income collected by the port for eleven months i.e. from 1 April 2010 to 28 February 2011 is considered as part of the past period for determining the special levy.

Based on the above, the total deficit for March 2011 and the years 2011-12 to 2013-14 estimated at Rs.15450 lakhs are considered for determining the levy. As per the cost statement, the levy to bridge the deficit of Rs.15450 lakhs is 234% of the time rate wages. Thus, the levy for the CHD is prescribed at 234% of the time rate wages.

The port has clarified that in case of workers deployed for the wagons unloading operations of thermal coal in addition to general levy a separate levy at par with general levy is being collected termed as piece rate levy as per the procedure in vogue at the time of the merger. Though it is termed as PR levy, the said levy is collected as percentage of time rate wages. The logic and the basis for collecting separate levy in the name of piece rate levy is not explained by the port. The port has also in the proposal not explicitly proposed PR levy on Thermal Coal except stating that it will be collected as per the existing procedure without offering any other explanation. As per the cost statement, the levy to bridge the deficit is 234% of the time rate wages which will apply uniformly for all cargo availing the deployment of labour from the CHD including the thermal coal for wagon unloading operations.

The levy of 234% of the time rate wage is in addition to the recovery of time rate and the piece rates to workers collected from trade for deployment of workers from the CHD as stated by the VPT.

- (x). (a). It is notable that of the 189% levy collected by the port at the time of merger included levy of 50% of time rate wages which was adjusted against the past period loss. After such adjustments, the cumulative loss as on 31 March 2010 is reported at **Rs.55.40 crores** in the Annual Accounts. The position reported in the Annual Accounts is relied upon subject to exclusion of interest income, interest expenses and the VRS payments for the years 2008-09 and 2009-10 which are not considered in fixation of tariff. As stated earlier, payment of wage arrears of Rs.52 lakhs made in the year 2010-11 is added to the past period loss. Subject to the above adjustment, the total past period loss till 31 March 2010 is Rs.5554 lakhs.

There is no specific provision in the guidelines to 2005 to set off the past losses. It has to be recognised that this exercise is done to make this activity a self-reliant which is one of the conditions of the Memorandum of Settlement. Even the trade has not raised any pointed objection except requesting a separate levy instead of clubbing the past period loss for determining the basic levy.

- (b). The activity reflects an estimated deficit of **Rs.5244.23 lakhs** for the year 2010-11 as per the cost statement. The deficit for the eleven months period i.e. from 1 April 2010 till 28 February 2011 which is considered as part of the past period will be **Rs.4807.21 lakhs**. It is notable that the estimated deficit shown in the cost statement is before accounting for the income from the levy collected by the port on adhoc basis. The VPT has estimated the income from levy at Rs.6395.31 lakhs. The actual income collected by the port upto October 2010 from applying the levy on adhoc basis is Rs.4091.57 lakhs and the estimates for the balance four months from November 2010 to February 2011 on pro rata based on the estimates furnished by the port is Rs.2131.77 lakhs. Thus, the total revenue from the levy till 28 February 2011 is Rs.6223.34 lakhs which after adjustment with the deficit reflected for the corresponding period leaves a surplus of Rs.1416.13 lakhs. This surplus of Rs.1416.13 lakhs is applied to partly meet the loss assessed for the past period.

- (c). The interest income and the interest expenses are not admissible in the tariff fixation exercise and hence excluded. The net interest income over the interest expenses earned in the years 2008-09 and 2009-10 and estimated position for the year 2010-11 to 2013-14 is a source available to the port to meet the past period loss to some extent. The sum of net interest income over the expenses reported in the years 2008-09 and 2009-10 and estimated for the year 2010-11 to 2013-14 to the tune of Rs.195 lakhs is adjusted against the past period loss.
- (d). At the existing levy of 300% of the time rate wage, the port expects the recovery of past period loss over seven to eight years beginning from 1 April 2010. As per the cost statement furnished, the uncovered loss pertaining to the past period is expected to be Rs.25.43 crores at the end of this tariff cycle at the existing levy of 300%. The past period loss is expected to be recovered in four years i.e. by 2013-14 at the proposed levy of 350% of the time rate wages. There does not appear to be any specific reason to peg the recovery period to only a single tariff cycle and burden the users. The recovery of accumulated losses should be done in a gradual manner without causing a heavy burden on the users and at the same time, cannot be extended to a very long period, at the expense of the port. The Mormugao Port Trust (MOPT) during their tariff revision in 2006 had proposed to introduce a special levy to augment the Pension Fund over five years. It was decided by this Authority to spread over the pension liability over longer duration so as to reduce the burden on users. The special levy introduced in 2006 for one tariff cycle has been extended for another tariff cycle in the tariff revision of the MOPT approved in May 2010. It is notable that in case of Kolkata Port Trust where the shortfall in the Pension Fund was found to be substantial, a special levy is being introduced to augment the Pension Fund over three tariff cycles. In the instant case, the past period loss is proposed to be recovered in two tariff cycles beginning from 1 March 2011.

- (e). The position relating to the past period loss is explained hereunder:

		(Rs. In lakhs)
1.	Past period loss upto 31 March 2010	-5554
2.	(a).Deficit for the year 2010-11 as per the cost statement (Rs.5244.23 lakhs considered proportionately for 11 months till 28 February 2011)	-4807.21
	(b).Less: Revenue earned by VPT from recovery of levy on adhoc basis at 250% from 1 April 2010 till 30 June 2010 and at 300% thereafter till 28 February 2011	6223.34
	(c). Net surplus for the year 2010-11	1416.13
3.	Net of interest income over the interest expenses for the years 2008-09 to 2013-14	195.00
4	Net loss for the past period loss as on 1 March 2011 (1+2+3)	-3942.87
5.	Past losses (net) to be recovered in the current cycle from 1 March 2011 till 31 March 2014	-2026.20
6.	Total Time Rate Wages for the month of March 2011 and for the years 2011-12 to 2013-14	6602.12
7.	Special levy to meet the past period losses (% of time rate wage) [5/7]	31%

Accordingly, a special levy of 31% of the time rate wage is approved to meet the past period loss. The port is advised to maintain a separate account of income to be generated from the special levy and apply the revenue only for the stated purpose. The port should furnish the audited accounts in this regard for scrutiny at the time of the next review, based on which the quantum of special levy will be decided for the next cycle.

- (xi). The VPT has proposed to include definitions of Cargo Handling Division, Dock Work, Dock Worker, Rate of levy, Time Rate Wage and Piece Rate in the existing Section-1 of its proposed Scale of Rates. These terms are not defined while approving charges for deployment of cargo handling labour for stevedoring operations in the Scale of Rates of the Mormugao Port Trust (MOPT), New Mangalore Port Trust (NMPT), Mumbai Port Trust (MBPT) and Chennai Port Trust (CHPT). The definitions of the terms dock work, dock worker are common port parlance and hence need not be specifically defined in the Scale of Rates. The Memorandum of Settlement entered between the VPT and the VDLB defines the term Cargo Handling Division.

The time rate wages and the piece rate wages payable to the workers are as per the wage settlement and the incentive scheme is stated by way of a general note.

The port has proposed to define Rate of levy as a percentage of time rate wages paid to workers to be collected from the Stevedores to meet the administrative and welfare expense of cargo handling division. The mode of recovery of levy is separately mentioned in the Schedule and hence the rate of levy need not be defined separately. A note is inserted under the schedule to state that the levy is payable to VPT by the stevedores.

- (xii). During the processing of this case, it emerged from the comments received from the Tamil Nadu Electricity Board that the port has implemented the proposed levy. The port was vide our letter dated 9 August 2010 alerted that this Authority has not approved any levy for deployment of labour from Cargo Handling Division in the Scale of Rates of VPT. The VPT has clarified that in view of substantial financial loss in the CHD, the VPT with the consensus arrived with the trade which included the handling agent of the TNEB, representative of the VSA amongst other trade members decided to enhance the levy from the existing 189% to 250% for a span of three months i.e., w.e.f. 1.4.2010 till 30.6.2010 and thereafter at 350%. The port has, however, restricted the levy at 300% in view of request made by the trade.

As per clause 2.17.1 to 2.17.3 of the tariff guidelines whenever a specific tariff for services / cargo is not available in the notified Scale of Rates, the port can submit the proposal and levy the rate on an adhoc basis till the rate is finally notified. For this purpose, the adhoc rate must be derived based on the existing notified tariffs for comparable services / cargo and it must be mutually agreed upon by the port and the concerned users.

The Scale of Rates of the VPT approved by this Authority did not prescribe any rate for CHD as it was operated by the VDLB prior to merger i.e. till 25 September 2008. Post merger, the VPT continue to offer this service at the then prevailing levy of 189% collected by the VDLB. Since the operations were not found sustainable at the then prevailing levy, the VPT after obtaining the consent of the trade proposed to increase the levy and implemented the proposed hike of 250% at the first stage from 1 April to 30 June 2010. For the period after 30 June 2010, though original proposal proposed the levy at 350% of the time rate wage, based on the request of the trade, the port has been collecting the levy at 300% of the time rate wages.

Clause 2.17.4. of the tariff guidelines of 2005 permits this Authority to recognize the interim rate adopted in an ad-hoc manner retrospectively if it is not found to be excessive. While deciding the quantum of special levy, the income earned by the VPT based on adhoc levy implemented by the port is considered for the period from 1 April 2010 till 28 February 2011 and revenue in excess of the permissible level is adjusted against the past period loss. The levy implemented by the port on adhoc basis from 1 April 2010 is, therefore, recognised by this Authority.

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following rates to be incorporated in the existing Scale of Rates of the VPT as Schedule 4.7.4, under Section 4 – Cargo Related charges.

Schedule 4.7.4 - Levy of charges for obtaining services of cargo handling worker from the Cargo Handling Division

4.7.4.1. Levy on Time Rate Wages

Description	Percentage of Levy on Time Rate Wage
For all Cargo availing services of cargo handling worker from Cargo Handling Division including Thermal Coal availing services of cargo handling worker for wagon unloading	234%

Notes:

1. The levy indicated above is in addition to recovery of time rate wages and piece rates payable to workers as per the respective clauses of prevailing wage settlement/ incentive scheme.
2. The above levy is payable by the stevedores to the VPT.

4.7.4.2. Special Levy

Particulars	Percentage of additional special levy on Time Rate Wage
On all cargo availing services of cargo handling worker and also on thermal coal availing services of cargo handling workers for wagon unloading	31%

Note:

The special levy prescribed above will be levied in addition to the levy prescribed in Schedule 4.7.4.1. above for deployment of workers from CHD for handling cargo.

13.2. The levy approved will come into effect from 1 March 2011 and will remain valid till 31 March 2014.

RANI JADHAV, Chairperson
[ADVT. III/4/143/10-Exty.]

COST STATEMENT RELATING TO CARGO HANDLING DIVISION OF VISAHKHAPATNAM PORT TRUST

Annex - 1
in Rs.

24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

S.I.NO.	PARTICULARS	ACTUALS		Furnished by VPT		Modified by TAMP		Estimates considered by TAMP (excludes the levy income for the years 2010-11 to 2013-14)
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	
	INCOME	250.4	302%	300%	300%	300%	201.12	2012-13
(i) TIME RATE WAGES	113023532	179749000	170550000	185056000	201057000	185598192	19764014	214479682
(ii) PIECE RATE WAGES	28241832	305680000	29771000	29564000	29521000	305680000	29771000	29564000
(iii) LEVY	1522303661	639531000	586562000	643168000	694171000	0	0	0
(iv) RECEIPTS FROM RENT	3517602	3123356	3218000	3371000	3544000	3218000	3371000	3544000
(v) OTHER RECEIPTS & INTEREST ON DELAYED PAYMENTS	6219296	5216800	3234000	2042000	2083000	2120000	2042000	2120000
(vi) INTEREST INCOME (ON INVESTMENT, LOAN TO CO-OPERATIVE SOCIETY, ADVANCE TO STAFF, etc.)	7506501	7063012	60950000	5380000	4927000	5016000	0	0
TOTAL OF INCOME	424261188	308365903	362430000	308632900	368442000	315608000	220758792	248770632
II EXPENDITURE								
(i) TIME RATE WAGES	151905621	105072798	161745000	164650000	181056000	198057000	15309061	176222301
(ii) PIECE RATE WAGES	84061989	28241832	305680000	29771000	29564000	29521000	305680000	29771000
(iii) PAYMENTS TO WORKERS	1967520266	197515595	186546000	185600000	194250000	203862000	192994344	188784620
(iv) PAYMENTS TO OFFICERS & STAFF	64216752	75149578	68652000	70218000	77415000	69652000	65314357	59319030
(v) ADMINISTRATION EXPENSES	1246323093	7035191	6130000	6154000	64246000	67151000	5738302	56716522
(vi) STAFF WELFARE EXPENSES ON HEALTH, RECREATION, HOUSING, CANTEEN ETC.,	38912004	42179538	70118000	72526000	76889000	81969000	67216395	67044969
(vii) DEPRECIATION	2497519	2762140	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000
(viii) FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENSE								
(a) CONTRIBUTION TO PENSION FUND, GRATUITY FUND, FAMILY SECURITY SCHEME ETC.,	56531750	21240206	194065000	195830000	205621000	226183000	194065000	195830000
(b) INTEREST ON BANK LOAN, PF TRUST, etc.	9848734	4338439	2255000	0	0	0	0	0
(c) ITEM RELATING TO PREVIOUS YEAR	0	23909	8700000	0	0	0	3500000	0
(d) GROUP LEAVE ENCASHMENT SCHEME	0	4740000	13364000	0	0	0	12364000	0
(e) VRS BENEFITS TO WORKERS & STAFF OPERATING EXPENDITURE	51723644	726372311	781175000	748361000	793230000	22826000	749446000	731405102
(f) Surplus / deficit	74810856	-417402808	61255000	598210000	75212000	86168000	-522231311	-498575295
IV CAPITAL EMPLOYED								
(i) BUSINESS ASSETS	4307000	27659000	1387000	50000	5830160	5056800	4283440	3510080
(ii) BUSINESS RELATED ASSETS	10844000	7271000	3607000	13000	14991840	13003200	2192140	11014560
V RETURN ON CAPITAL EMPLOYED								
(i) RETURN ON CAPITAL EMPLOYED ON BUSINESS ASSETS 16%	685000	443000	222000	10000	932826	809088	685350	561613
(ii) RETURN ON CAPITAL EMPLOYED ON BUSINESS RELATED ASSETS 6.35% (as per compilation at 3.4%)	697000	461000	229000	10000	1259315	1092269	925221	758177
VI RETURN CAPITAL EMPLOYED	13865000	9840000	451000	20000	2192140	1901357	1610573	1319730
VI TOTAL EXPENDITURE + RETURN	51723644	726372311	7812561000	749765000	793641000	849448000	56158000	53140251
VII NET SURPLUS/DEFICIT	74810856	-417402808	793650000	589170000	86158000	53140251	498446000	505633214
VIII NET SURPLUS/DEFICIT AS PERCENTAGE OF TIME RATE WAGES	-235729197	-554000000	-415214000	-340453000	-254295000	-255%	-231%	-21%
IX AVERAGE DEFICIT AS PERCENTAGE OF TIME RATE WAGES (From March 2011 to March 2014)								-2.34%
X (DEFICIT) / SURPLUS AFTER ADJUSTMENT OF FAST PERIOD LOSS								

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.